[श्री कल्पनाथ राय]

आर्डिनेंस लागू किया कि जो अध्यापक 5 तारीख तक हड़ताल नहीं खत्म कर देंगे उन की नौकरी खत्म कर दी जायेगी ।

MR. CHAIRMAN: What is your suggestion?

श्री कल्पनाथ राय : उस के विरुद्ध हाई कोर्ट में अध्यापकों ने एक रिट दाखिल किया । हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आर्डिनेंस को गलत घोषित किया फिर यू०पी० की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस काले आर्डिनेंस के पक्ष में एक अपील दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट में भी यू०पी० की सरकार हार गयी । तो उस सरकार को उस गंदे कानून के रद्द होने के सवाल पर भी इस्तीफा देना चाहिए था । लेकिन उस सरकार ने इस्तीफा न देकर उन अध्यापकों की नौकरी को बरखास्त करने का फैसला किया और इस के परिणाम-स्वरूप उत्तर प्रदेश में जिले-जिले में छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और उन पर गोली वर्षा की गयी । फैजाबाद में एक विद्यार्थी अध्यापकों के समर्थन में गोली से मारा गया । आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के प्रधान मंत्री और चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ के हड़ताली अध्यापकों को हड़ताल के 43 दिनों की तनख्वाह नहीं दी है । इसलिये मैं कमलापति त्रिपाठी जी से अपील करता हूं कि इस सदन को हम नहीं चलने देंगे । अगर इन 43 दिनों की तनख्वाह उन को नहीं दी गई तो इस सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार धरना होगा । इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अध्यापकों ने फैसला किया है कि 24 मार्च को लखनऊ की विधान सभा के बाहर पूरे उत्तर प्रदेश के अध्यापकों का प्रदर्शन होगा ।

MR. CHAIRMAN: You conclude now. Your time is over.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (उत्तर प्रदेश) : तनख्वाह कौन देगा ।

श्री सभापति : श्रीमती कुलकर्णी ।

श्री कल्पनाथ राय : मैं अपनी पार्टी के नेता पंडित कमलापति त्रिपाठी से प्रार्थना करता हूं कि इस गूंगी-बहरी सरकार से हड़ताल के 43 दिनों की तनख्वाह अध्यापकों को दिलवायें ।

MR. CHAIRMAN: It is all right. You conclude, otherwise they will not take down.

SHRI SUNDER SINGH BHAN-DARI: Unless you do that, he will not stop.

MR. CHAIRMAN: That is all right. You may conclude. Shrimati Kul-karni.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—contd.

श्रीमती सुमित्रा जी० कुलकर्णी (गुजरात) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उसका समर्थन करते हुए मुझे बहुत ही खुशी है । श्रीमन्, नीतियों को लागू करने में बहुत समय लगता है । एक-दो दिन में नीति बदलना या नई नीति को स्थापित करना संभव नहीं है ।

[**Mr. Deputy Chairman** in the Chair.]

खासतौर पर नीतियों को लागू करना और सरकार का काम बढ़ाना और भी कठिन हो जाता है जब कि विरासत में इतनी खराब व्यवस्था मिली हो । जो नीतियां हमारी प्रस्तुत हुई हैं उन्हें हम को लागू करना है ।

श्रीमन्, एक खास स्तर पर कुछ खास सिद्धान्तों को लेकर पिछले साल जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और वह जीत गई । मगर जिस दिन से भी उन्होंने सरकार को हाथ में लिया एक दिन भी न काम में विक्षेप आया और न

क्षति हुई, सतत् जिस प्रकार से सरकार का काम चलना चाहिये वैसे वह चलता रहा । अब 4–6 महीने इस सरकार को इस अव्यवस्था, इस अनीति और इस अन्याय की दलदल से निकालने में लग गये । यह बात सही है कि चार-छः महीने इस सारी परिस्थिति को समझने में लग गये । मगर मेरा निवेदन है कि तीन-चार महीनों से हर क्षेत्र में व्यवस्थित कदम उठाये जा रहे हैं जो हमारी नीतियों का प्रतिपादन करते हैं ।

श्रीमन्, आप जानते हैं कि हमारी औद्योगिक नीति के संबंध में 6 हफ्ते पहले चर्चा हो चुकी है और दो-तीन हफ्ते के अन्दर इसी सदन के सामने हमारी औद्योगिक नीति का उल्लेख होगा और उस पर चर्चा होगी । हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी को दूर करना और उत्पादन को बढ़ाना ।

श्रीमन्, सब चीज तो है हीं मगर सबसे बड़ी विशेषता इस इंडस्ट्रियल पालिसी की है वह है टाइनी सैक्टर की । आज तक स्माल स्केल सेक्टर 15 लाख रुपये तक का होता था । 15 लाख रुपये ऐसी आमद नहीं है, राशि नहीं है कि उस को आसानी से एकत्रित किया जा सके । उसको एकत्रित करने में बड़ी कठिनाई होती थी इसलिये हमारी सरकार ने टाइनी सैक्टर की व्यवस्था सोची है जिसके अन्तर्गत पांच लाख रुपये के अन्दर कोई भी इंडस्ट्री चालू की जा सकती है । पांच-छः लाख में मुश्किल से एक मशीन आ सकती है । यह लेबर इन्सेटिव की व्यवस्था है इससे अनएम्पलायमेंट कम हो सकेगा । इस बारे में जनता सरकार बहुत सतर्कता पूर्वक काम कर रही है । मई के महीने से हर प्रांत के हर जिले में इंडस्ट्रीयल एडवाइजर का दफ्तर होगा । उसके अन्दर हर परिस्थिति की सलाह सूचना जो भी महत्वपूर्ण सूचना अथवा मदद चाहिये वह मिल सकेगी । मैं समझती हूं कि इस प्रकार की हमारी औद्योगिक व्यवस्था भविष्य में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है ।

श्रीमन्, दूसरी चीज जिसके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं वह यह है कि हम सब लोग यह मानते हैं कि आपातकाल के दौरान हमारे देश के संविधान में अनेक प्रकार की विकृतियां भर दी गई । अब हमारी जनता पार्टी की सरकार की ओर से इन विकृतियों को दूर करने का प्रयास हो रहा है और चुनाव कानून में भी संशोधन लाने का प्रयास हो रहा है । यह बात भी नहीं भुलाई जानी चाहिए कि अगर यह सरकार चाहे तो एक पार्टी के स्तर पर और दल के स्तर पर ही इस प्रश्न को उठा सकती थी । मगर हमने राष्ट्रीय स्तर पर इसके बारे में विचार किया है और हम इसको एक राष्ट्रीय समस्या समझते हैं । इसलिए हमारे दल के प्रत्येक सदस्य की यह इच्छा है कि इसके बारे में गहराई से चर्चा की जाय और विपक्ष के हर एक सदस्य के साथ और हर एक नेता के साथ विचार-विमर्श होना चाहिए और जब इसके बारे में पूरे तौर पर बातचीत हो जाय, पूरा सोच-विचार हो जाय तब दोनों सदनों के सामने कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाय । मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि विपक्ष के नेताओं ने हमारे इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है और वे इस संबंध में पूर्ण विचार-विमर्श के लिए सहमत है । मगर मैं यह कहना चाहती हूं कि आज तक क्या पिछले 30 सालों के अन्दर इस तरह से विपक्ष के साथ बातचीत करके सोच-विचार के साथ राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार कभी नहीं हुआ ? मैं समझती हूं कि अगर यही तरीका पहले की सरकार ने अपनाया होता तो हमारे संविधान में इस प्रकार की विकृतियां और डिसटोरसन्स न पैदा हुए होते और चुनाव के कानून में व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तोड़-मरोड़ नहीं होती और न ही हमारे देश में प्रेस सैंसरशिप लागू होती । अगर पिछली सरकार ने विपक्ष से विचार-विमर्श किया होता तो देश की वह दुर्दशा नहीं

[श्रीमती सुमित्रा जी० कुलकर्णी]

होती जो दुर्दशा आपातकाल के दौरान हुई । मैं समझती हूं कि अगर पिछली सरकार ने विपक्ष के लोगों के साथ बातचीत करके एक दूसरे को समझने की कोशिश की होती तो जो स्थिति हमारे देश में पैदा हुई वह न हुई होती । अब हमारी वर्तमान सरकार की तरफ से बातचीत करने और विचार-विमर्श करने का पूरा प्रयत्न चल रहा है ।

श्रीमन्, मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहती हूं कि हम लोगों ने और जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र की संस्थापना की है और उसको फिर से पुर्नजागृत किया है । इतना ही नहीं, हम लोग उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं । सारी दुनिया के अन्दर हर एक देश में इस बात की बहुत बड़ी गरिमा मानी जा रही है कि भारतवर्ष की 60 करोड़ जनता ने लोकतंत्र को अपने देश में फिर से स्थापित कर दिया है ; अन्यथा दुनिया के अन्दर हमारी स्थिति यह हो गई थी कि भारतवर्ष में लोकतंत्री व्यवस्थाओं के संबंध में दुनियां के और देशों का विश्वास उठ गया था । उन लोगों का यह विश्वास हो गया था कि एक बहु-संख्यक देश केवलमात्र तानाशाही में ही चल सकता है और उसका शासन-प्रबन्ध लोकतंत्री व्यवस्थाओं के अन्तर्गत नहीं चल सकता है । आप जरा इस बात पर विचार कीजिये कि अगर जनता पार्टी की सरकार न आई होती तो आज भी हम लोग तानाशाह के राज के अन्तर्गत चल रहे होते और हम लोग अपनी जबान भी नहीं खोल सकते थे । आज हमारे देश में यह स्थिति है कि हर स्थान पर हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं । हमारे देश में पूर्ण रूप से वाणी स्वातंत्रय है, विचार स्वातंत्रय है । मैं समझती हूं कि जनता पार्टी की सरकार की यह विशेष उपलब्धी है । इतना होते हुए भी हमारे ऊपर लांछन लगाये जाते हैं, आरोप लगाये जाते हैं और यह कहा जाता है कि हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं । श्रीमन्, मैं इस संबंध में बहुत शर्मिन्दा हूं और बहुत दुःख के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि इस तरह के अत्याचार आज भी हमारे समाज में हो रहे हैं । हमारी सरकार और हमारे दल के प्रत्येक सदस्य की यह इच्छा है कि इस प्रकार की एक भी वारदात नहीं होनी चाहिए ताकि लघुमति के लोग इन बातों को ऊपर न उछाल सकें । हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो आदिवासी, हरिजन, गिरिजन आदि हैं उनकी गरिमा में और उनकी मर्यादा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि न आने पाये और उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो । इसी भावना से प्रेरित होकर हमारे प्रधान मंत्री ने हर एक मुख्य मंत्री को यह पत्र लिखा है और हिदायत दी है कि वे इस संबंध में तत्काल कदम उठायें । प्रधान मंत्री जी ने अपनी सार्वजनिक और मुख्य मंत्रियों की सभाओं में भी इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है । अब इस बारे में बहुत सजगता दिखाई जा रही है । हमारी सरकार की यह मान्यता है कि किसी भी हरिजन अथवा किसी भी कमजोर वर्ग के ऊपर कहीं भी कोई अत्याचार नहीं होना चाहिये । मगर इस संबंध में आपके सम्मुख मैं कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहती हूं । आज से तीन साल पहले जिला लखनऊ में थाना माल में एक हरिजन महिला पर अत्याचार हुए । उसको निरावरण करके और एक पेड़ से बांध कर मारा गया । उसके बाद उसकी बेइज्जती की गई, उस पर बलात्कार किया गया । श्रीमन्, मैं बताना चाहती हूं कि उस समय वह मामला कांग्रेस पार्टी के सामने आया था । उस समय पार्टी के अन्दर यह कह दिया गया कि ठाकुर साहब से गलती हो गई है, माफ कर दीजिये । अब इसको बढ़ाओ मत, इसको दबा दीजिये । श्रीमन्, यह बड़े दुख की बात है कि उस समय किसी ने लोक सभा या राज्य सभा में यह प्रश्न नहीं उठाया । मेरा इरादा किसी के ऊपर लांछन लगाने का नहीं है । मैं यह कहना चाहती हूं कि यह एक सामाजिक प्रश्न है । उस समय किसी ने इस प्रश्न को नहीं उठाया ।

उस समय किसी ने यह हमदर्दी नहीं दिखायी कि कम से कम इस चीज को उठा कर राज्य सभा के सभा पटल पर रख दें । यह वाकया सही है कल्पना नहीं । मेरा आपसे निवेदन है ऐसी दुखद घटना के ऊपर अगर हम राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश करेंगे तो हम देश को बरबाद करेंगे, अपने समाज को बरबाद करेंगे और हम अपनी पिछड़ी जातियों को आगे आने से रोक देंगे और हम उन के भविष्य को बरबाद कर देंगे । हम किस तरह के विचारों में फंस गये हैं ? हमारी उनसे पूरी हमदर्दी होनी चाहिए । इस देश में हजारों सालों से यह चीज चल रही है । यह एक सामाजिक प्रश्न है और अब यह एक आर्थिक प्रश्न भी बन गया है । सही चीज जो है उसको समझना हम सब का काम होना चाहिए । मेरा आपसे नम्र निवेदन है, मेरा इस सदन के हर एक और एक-एक भाई से निवेदन है कि वे सब इसमें हमारी सरकार की सहायता करें । हम सब मिल कर इस पवित्र काम में लग जायें । अगर हम इस मसले को इस तरह से नहीं सुलझायेंगे तो यही लगेगा कि हम हरिजनों से केवल नाजायज राजनैतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं और जब कभी भी नाजायज राजनैतिक फ़ायदा उठाया जाता है तो किसी भी समाज को, किसी भी गिरिजन को किसी भी हरिजन या आदिवासी को उससे फायदा नहीं हो सकता । तो यही चीज सोचने की है । हम लोग क्या चाहते हैं ? विपक्ष के लोग यहां बहुमत में हैं । हम चाहते हैं कि वह इस मामले में सरकार की मदद करें और इस चीज से ऊपर उठ कर सोचें ।

श्रीमन, यह बात हुई हरिजनों की अब हम मूल्यों के बारे में सोचें । हमारे यहां जो चीजों के मूल्य बढ़े हैं, अनाज के भाव बढ़ गये, दाल के भाव बढ़ गये, तेल के भाव बढ़ गये, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए । आर्थिक नीतियां न तो एक दिन में बदली जा सकती हैं और न ही एक दिन में उनको उल्टा जा सकता है । श्रीमन, दाल की उपज हिन्दुस्तान में ही सब से ज्यादा होती है, मगर तीन चौथाई हिन्दुस्तान के एरिया में दाल नहीं उग सकती है क्योंकि 30–35 इंच पानी के अन्दर ही दाल की उपज हो सकती है । 76 के साल में पानी नहीं गिरा, तो दाल की कमी पड़ गई और दाल कहीं से मंगाई नहीं जा सकती क्योंकि कहीं पैदा नहीं होती ।

श्रीमन, मैं एक और चीज आपके सामने रखना चाहती हूं । 1975 और 1976 साल के आरम्भ में यह मामला उठा था कि तेल की कमी है । उस समय मैं गुजरात गवर्नमेंट की एडवाइजरी कमेटी की सदस्या थी । मैंने जनवरी 76 को केन्द्रीय सरकार को कहा कि गुजरात के लिये तेल की व्यवस्था की जाये । श्रीमन, तेल का लाइसेंस दिया गया और वह तेल खरीदा भी गया विदेशों से, डालर का पेमेंट करके । लेकिन जब उस तेल को वहां से उठाया जाना था, उसी समय विदेशों में तेल के भाव बढ़ गये । जब वहां तेल के भाव बढ़ गये तो हमारे मित्रों ने वहां पर उस तेल को बेच दिया और उससे लाभ उठाया । जितने भी डालरों का फायदा हुआ वह सारा विदेशों में जमा हुआ और वह पैसा कभी हिन्दुस्तान में आया ही नहीं । श्रीमन, यह बात सबकी जानकारी में है । इस तरह के भ्रष्टाचार से देश में तेल की कमी हो गई थी । श्रीमन, एक महीने पहले हमारे यहां रेप-सीड तेल का भाव 4 सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चल रहा था आजकल उसका भाव 3 सौ रुपये है और आशा है कि उसकी दरों में और भी कमी होगी । धीरे-धीरे सरसों की इस देश में बहुत कमी हो रही है । क्योंकि सरसों का फसल पर बहुत जल्दी से बीमारी लगती है इसलिये इसका रकबा कम हो रहा है । मगर तो भी इसकी कीमत कम होती जा रही है । यह सब कारण हैं, जिनकी वजह से ये भाव बढ़े थे मगर अब सदन के सभी साथी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इस समय मूल्यों

[श्रीमती सुमित्रा जी० कुलकर्णी]

में कमी हो गई है। पिछले सालों में 12 प्रतिशत मूल्यों में वृद्धि हुई थी ।

मगर पिछले साल 4% वृद्धि ही हुई है। आज भाव एकदम संतुलित है और बहुत नियंत्रित है। तो इस बारे में सोचना चाहिए कि यह चीज केवल 10 महीने के अंदर अनेकों तकलीफों के बावजूद यह आर्थिक नियमन हुआ है।

(*Interruption*)

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (मध्य प्रदेश) : श्रीमन, सरसों को घुन नहीं लगता यह तो वर्षों तक रखी रह जाती है।

(*Interruption*)

श्रीमती सुमित्रा जी० कुलकर्णी : सुनिये, विद्यावती जी। मैंने घुन नहीं कहा। सरसों के पौधों के अंदर बीमारी लग जाती है और सरसों का रकबा भी बहुत कम हो गया है, मैंने तो यह कहा है। आप तो सुनती नहीं है और देर से भी आई हैं। फिर कहती है (*Interruptions*) सुनिये यादव जी मैं आज तक किसी की बात में आक्षेप नहीं करती। मैं आपकी बात शांतिपूर्वक सुनती हूं। अगर आप नहीं चाहते तो मैं बैठने को तैयार हूं (*Interruptions*) मैं जो कह रही हूं अगर आप कहें कि यह गलत है तो मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। मगर 12% मूल्यों के वृद्धि के मुकाबले में अब केवल 4% मूल्यो की वृद्धि हुई है यह बात तथ्य है। श्रीमन, हर तरह की तकलीफों के बीच इस सरकार ने इस स्तर की आर्थिक स्थिरता को प्राप्त किया है। इसलिए इस के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। श्रीमन, यह सब चीजें कोई एक दिन में नहीं हो सकतीं। जनता सरकार कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा सकती कि एक दिन में इसको सुधार दे और रामराज्य आ जाए। इतनी कठिनाइयों के बीच, इतनी गलतियों के बीच, इतनी अव्यवस्थाओं के बीच यह सरकार आई और इस सरकार की यह हिम्मत है कि एक दिन भी हिम्मत हारे बिना शांतिपूर्वक, सम्पूर्ण विचारों की स्वतंत्रता के साथ अपना काम कर रही है। एक माननीय सदस्य ने जो यहां पर इस समय नहीं हैं बहुत बड़े वकील है और उच्चतम न्यायालय में काम करते है। हां अब सामने बैठे हैं। श्रीमन, उनको बहुत एतराज हुआ---शाह कमीशन के बारे में। मैं यह कहना चाहती हूं कि शाह कमीशन की नियुक्ति कमीशन आफ इन्क्वायरीज एक्ट जिसको कांग्रेस सरकार ने पास किया उसके अन्तर्गत की गई। इस एक्ट के अन्तर्गत आज तक अनेकों कमीशन नियुक्त किए जा चुके है, उनके ऊपर गवाही हुई है। किसी ने भी उसके प्रोसीजर में गलती नहीं निकाली, किसी ने उनके सामने गवाही देने से इन्कार नहीं किया। श्रीमन, यह तो सिर्फ एक चीज है अनेकों गलतियां, अनेकों अव्यवस्थाएं हो गई थी, अनेक ज्यादतियां हो गई थी, अगर हम उनकी जांच नहीं करेंगे तो हम क्या चाहते है ? एक समय था जब एक नादान युवक हर तरह से जो भी उसके दिल में आया हुक्म दे दिया। न वह सरकार में था, न संसद के किसी सदन का सदस्य था, न कोई हस्ती थी, मगर हर जगह जा कर गांव-गांव और बस्तियों को तोड़ फोड़ कर बरबाद कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में अगर हम जांच भी न करवाएं तो हमें और क्या करना है ? मेरा मात्र नम्र निवेदन है कि शाह कमीशन कोई विशेष चीज नहीं है, न कोई अजनबी चीज है। बरसों से इस तरह के कमीशन चलते रहे। हर तरह के कमीशन हर परिस्थिति में लागू हुए, यह भी एक वैसा ही कमीशन है। इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं।

SHRI D. P. SINGH (Bihar): **Sir,** with your permission, may I ... *(Interruptions)*. Madam, because you are misrepresenting the facts,, I am only drawing your attention to... *(Interruptions)* .

श्रीमती सुमित्रा जी० कुलकर्णी : मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करती।

श्री कल्प नाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभापति महोदय, शाह आयोग के भ्रष्टाचार की जांच कौन करेगा जिसको भ्रष्टाचार की जांच करने का हुक्म... *(Interruptions)*

SHRI D. P. SINGH: Kindly appreciate the problem. The problem tha< I have raised is: Article 74(2) of the Constitution says that there shall be no inquiry into what advice was given to the President. But the lawyer of the Commission gets up and the first thing he says is that the advice was a "fraud" on the President. This is the matter that I was raising.

श्रीमती सुमित्रा जी० कुलकर्णी : श्रीमन, मैं आपसे संरक्षण चाहती हूं। अगर कल्पनाथ राय जी वहां से बोलेंगे तो आप कह दीजिए कि मैं बैठ जाऊं। मगर मैंने आज तक किसी व्यक्ति को सदन में न रोका है, न टोका है। एक सदस्य के नाते मेरा भी हक है और जब मैं बोल रही हूं तो उसको शांति से सुनें। क्या आप लोगों में इतनी भी उदारता नहीं है कि आप किसी को सुन नही सकते।

मेरा दूसरा प्रश्न है, श्रीमन्, यह कहा गया कि वरिष्ठ न्यायालय के उच्चतम न्यायाधीश की जो नियुक्ति हुई उसके अन्दर क्यों एक दूसरे से परामर्श करवाया गया। श्रीमन्, मैं आपके सामने बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहती। हमारे कांस्टीट्यूशन की एक कापी के पेज 59 आर्टीकल 124 और सब क्लाज (2) में है कि :

"Every judge of the Supreme .Court shall. . .after consultation with such of the judges of the Supreme Court..."

श्रीमन्, यह तो कांस्टीट्यूशन, संविधान के अन्दर व्यवस्था है। इसके अन्दर राष्ट्रपति को हक है और उनको पूछना चाहिए कि किस तरह के व्यक्ति को चीफ जस्टिस बनाया जाये या किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाय.... *(Interruptions)* श्रीमन, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार के लिए तो यह बहुत सरल था कि हम पुरानी सरकार के ए० एन० राय की नियुक्ति की परम्परा को रख लेते। श्री चन्द्रचूड़ ने मूल अधिकारों के ऊपर एक ऐसा जजमेंट दिया था कि इस देश के लोगों को अपने जिन्दा रहने का भी हक नहीं रह गया था। मगर वह सरकार न्यायाधीश की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना चाहती है यह सरकार चाहती है कि उच्चतम न्यायालय में वैचारिक स्वातंत्र्य रखा जाये। इसलिए अपने ऊपर खतरा होते हुए भी हमारे सामने आपकी परम्परा होते हुए भी हमारी सरकार ने नियमों का, सिद्धांतों का पालन किया है। श्रीमन्, हमने तो कोई गलती नहीं की। हम तो प्रलोभन में पड़ सकते थे। हमारे लिए तो यह बहुत अच्छा था कि चन्द्रचूड़ हमारे पास 7 साल के लिए न आते। मगर अब यह दुनियां के सामने सिद्ध हो गया है कि जनता सरकार के खिलाफ अगर कोई न्याय दे तो भी जनता सरकार की हिम्मत है कि वह हर एक न्याय को सहन करने की स्वीकार करने की सक्षम है। श्रीमन, यह तो हमारी तारीफ की चीज हुई कि हम इतनी निष्पक्षतापूर्वक नम्रतापूर्वक सिद्धांतों और संविधान का पालन कर रहे हैं।

तीसरे श्रीमन्, वह सज्जन नहीं हैं—नहीं नहीं—वे पीछे बैठे हैं उन्होंने कहा कि दूरदर्शन के अन्दर आधे सैकेंड के लिए जो श्रीमती इंदिरा गांधी की फोटो का डिस्प्ले हुआ उसे जनता सरकार सह नहीं सकी। श्रीमन् जब मैंने यह चीज सुनी तो मुझे खटका लगा। मेरे विपक्ष के मित्र हमारे वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं जब उन्होंने यह कहा तो मेरा कहना यह है कि उसके पहले अगर वे थोड़ी जांच करते या किसी अखबार को थोड़ा सा देखते तो उनको भी पता चलता कि किस परिस्थिति में और क्यों यह कदम उठाया गया। श्रीमन्,मैं आपके सामने यह बतलाना चाहती हूं कि एमरजेंसी में कैसी स्थिति थी, मैं संस्कृत की एक छोटी सी

[श्रीमती सुमित्रा जी० कुलकर्णी]

स्तुति आपके सामने पढ़कर सुनाती हूं-- क्षमा करेंगे मेरा संस्कृत का उच्चारण शायद पंडितों को अच्छा न लगे मगर वे कृपा कर सह लें।

"आपातकालं समारुध, देवीव, सिंहवाहिनी,
माहिश जाड्यमुत्सार्य धृत्वा मांगलयंविशतिम्।
संजयंती दिशाः सर्वा राजीवायतलोचना,
भूयात भूत्यैं सदास्मकं इंन्दिरा प्रियदर्शिनी।

श्रीमन्, उस काल में जबकि चापलूसी करना ही एक मात्र धर्म था, उस समय भी इस स्तुति को अतिशयोक्ति माना गया इसलिए यही सोचकर उस समय के जो डाइरेक्टर थे उन्होंने इसका प्रदर्शन करने को रोक दिया। क्योंकि उन्हें यह लगा कि शायद उस समय के वातावरण में भी लोगों के लिए भी यह ज्यादती हो जायगी। श्रीमन, ऐसी स्तुति के ऊपर सस्पेंशन का कष्ट उठाना पड़ा हो, उनको डिसमिस नहीं किया गया आप हमारे माननीय मित्र हैं और आप स्वीकार करेंगे कि यह स्तुति भगवान शंकर की होती, भगवान विष्णु के लिए होती या भगवान गणपति के लिए होती तो लोग उसको स्वीकार करते। आज के जमाने में यह मानव धर्म के खिलाफ हो जायगा कि हम ही इसको मूर्ति स्वरूप दे दें और इस तरह से मनुष्य की स्तुति करें। मैंने आपके सामने स्तुति पढ़कर सुना दी है। इसके अन्दर वंश परंपरा की बातों का उल्लेख है। क्योंकि यह सब किसी को अच्छा नहीं लग सकता अतः इसी वजह से यह किस्सा हुआ। मेरा आपके सामने यह निवेदन है कि कलाकार और कवि, ये समाज के और शासन के ऊपर होते हैं। वे स्वतंत्र हैं, मगर जब किसी देश का कलाकार और कवि चाटुकारिता और भाटचरण की तरह से बात करने लगे तब उस समाज का पतन होने लगता है। *(Interruptions)*

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (राजस्थान): आपने भी कम चापलूसी नहीं की।

श्रीमती सुमित्रा जी० कुलकर्णी: मैंने भी की होगी अगर आपको लगता है तो मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। श्रीमन, अन्त में मैं आपके सामने...

(Interruption)

कई माननीय सदस्य: क्या आपने चापलूसी नहीं की?

श्रीमती सुमित्रा जी० कुलकर्णी: जरूर, क्योंकि मैंने आप से सीखा। आप जैसे वरिष्ठ नेताओं से यह काम सीखना पड़ा। आज तक नहीं आता था। मेरे परिवार के अन्दर यह चीज कभी नहीं रही थी। यह आपके

श्रीमन्, अन्त में मैं एक और विषय के बारे में कहना चाहती हूं। हमारे कुछ सदस्यों ने कहा कि इस सरकार की विदेश नीति इम्मैच्योर है और हमारे देश के विदेश मंत्री पाकिस्तान चले गए यह गलत हुआ। मैं तो चाहती थी कि मेरे इस अज्ञान को कोई दूर कर दे कि पाकिस्तान जाने में कौन सी बड़ी भारी गलती हो गई, कौन सा बड़ा बचकानापन हो गया? श्रीमन्, 12-13 साल बाद एक विदेश मंत्री पड़ोसी देश पाकिस्तान गए तो समस्त संसार में भारतवर्ष की विदेश नीति के ऊपर लोग नाज करते हैं। इसके पूर्व कभी अपने देश को इस तरह का गौरव प्राप्त नहीं हुआ, न कभी इतनी इज्जत हमारी हुई, दुनिया के हर एक देश के प्रतिनिधि आज यह कहते हैं कि 60 करोड़ की गरीब जनता ने हमें बता दिया कि डेमोक्रेसी क्या है और कैसे इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। श्रीमन् अपने पड़ोसी देशों के साथ हमने मित्रता के नाते को घनिष्ट किया तो उसमें हमारी क्या गलती हो गई और जब इसको बचकानापन बताया

जाता है ? हमारी रूस के साथ दोस्ती थी तो अब भी कायम है । सबसे पहले मेहमान रूस के विदेश मंत्री यहां आए और अगर हमारे प्रधान मंत्री भी कहीं सबसे पहले गए तो वह रूस गए । अगर हमारी रूस के लोगों के साथ दोस्ती है तो अमेरिका के लोगों के साथ भी है । जब अमरीका के राष्ट्रपति खुद इस देश में आए तो उन्होंने बता दिया कि किस तरह हमारे प्रधान मंत्री ने बहुत गरिमा के साथ, बहुत फर्मनेस के साथ बहुत दृढ़ता के साथ बता दिया कि वे सिद्धांत के प्रश्न पर किसी देश के साथ किसी प्रकार का अनुचित समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं । ये शब्द उनके हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूं । इसलिए श्रीमन, इसमें कौन सी गलती हो गई ? अभी होम मिनिस्टर गए थे श्री लंका, वहां पर उनका इतना अच्छा प्रभाव पड़ा । अभी पाकिस्तान में हमारे विदेश मंत्री गए तो वहां के विदेश मंत्री आगा शाही भी यहां आने को तैयार हैं ; अगर ऐसे विदेश मंत्री की विदेश नीति को हम यह कहें कि यह इम्मेच्योर है, यह बचकानापन है, तो मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से अच्छे वैदेशिक संबंध स्थापित किये जा सकते हैं । नेपाल आफगानिस्तान, बर्मा और श्रीलंका के साथ हम संबंध कर रहे हैं, हर देश के साथ हम अपने अच्छे रिश्ते लगा रहे हैं । यह सब आप लोगों की नजर में है, कोई पीछे तो काम नहीं हो रहा है, न इस बारे में कोई गलत बातें की जा रही हैं । अगर हम इसी भाव से हर चीज के अन्दर गलती निकालते रहेंगे हर चीज के अन्दर हम यह चाहेंगे कि उसके विपरीत काम करें तो कुछ काम नहीं हो सकता । यह तो बात की खाल उखाड़ना होगा ।

श्रीमन एक छोटी सी कहानी कह कर समाप्त कर दूंगी । एक वयस्क व्यक्ति था जो अपने 9–10 साल के बच्चे के साथ एक गधे को लेकर जा रहा था । सारे गांव वालों ने उसको टोका, कभी कह दिया बेचारे उस सुकुमार बच्चे को चला कर ले जा रहे हैं, उसको गधे पर नहीं बैठाते । फिर जब उसको गधे पर बैठाया तो लोग कहने लगे कि बच्चे को शरम नहीं आती, अपने वयस्क बाप को पैदल चला कर खुद गधे में बैठ कर जा रहा है । जब दोनों जने गधे पर बैठ गए तो कह दिया कि देखो, दोनों को शरम नहीं आती, इस गधे की जान खाने पर क्यों तैयार हैं, एक बेजुबा जानवर परेशान हो रहा है । वैसा ही हाल हम देख रहे हैं अगर हर चीज की आलोचना करनी है तो हर चीज की आलोचना हो सकती है । लेकिन मैं आपको इतना आश्वासन देना चाहती हूं कि जनता सरकार के कंधे इतने चौड़े और सशक्त हैं कि हर तरह की आलोचना को सहन कर लेंगे । पहले से भी जनता सरकार के लोगों को जेल में रहने की और विरोध पक्ष में रहने की आदत है मगर वे अपनी नीति को और अपने सिद्धांतों को कभी अलग नहीं होने देंगे । मैं बहुत नम्रतापूर्वक आपके सामने यह कहना चाहती हूं कि हम अपनी नीतियों और सिद्धांत से कभी अलग नहीं रहेंगे चाहे कितना ही लांछन लगाया जाए । यह हमारे चरित्र-बल की हिम्मत है कि हम खुले आम लड़ने की ताकत रखते हैं । अगर हम दोगली बातें करते, अगर हम हर प्यार का स्वांग करते तो कोई बात कही जा सकती थी । ऐसा नहीं है कि हमने किसी की विरोधी आवाज को सहन नहीं किया है । अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसको एन्टी पार्टी कह कर उन लोगों के जवाब नहीं दे दिया । यह तो इस सरकार की हिम्मत है, इस दल की यह हिम्मत है और उनके सदस्यों का यह चरित्र है कि हर परिस्थिति में, हर कठिनाई को देखते हुए वह चलता है । हो सकता है कि हम कुछ काम न आ सकें । हम यह नहीं कहते कि हम को सभी काम आता है, या हम सब कामों में निपुण हैं, मगर हम सीख रहे हैं मगर हमारी ईमानदारी के बारे में किसी को शंका नहीं है । हमारी निष्ठा के बारे में किसी को शंका

[श्रीमती सुमित्रा जी० कुलकर्णी]

नहीं है । हमारी लोकशाही के बारे में किसी को शंका नहीं है । गरीबों के लिये हमारे प्रयत्न में किसी को शंका नहीं है । अभी रेलवे बजट आया । मैं उस की चर्चा नहीं कर रही हूं , मगर यह स्पष्ट है कि एक रुपये की जनता पैकेट देने वाले मंत्री सतत इस बात की चिन्ता में रहते हैं कि गरीबों को सस्ता खाना कैसे मिले और क्या उन के लिये काम किया जा सकता है । हर एक मंत्री अपनी जगह पर, चाहे कितना ही उसे काम न आता हो मगर प्रयत्न करता है और वह अपने स्थान पर निष्ठा से काम कर रहा है और हम ने तो देख लिया है कि बहुत चतुर लोग किस तरह से समाज को धोखा दे सकते हैं । उन की चतुराई ने ही हमारे देश की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और वाणी स्वातंत्र्य को नष्ट किया । हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म हो गयी थी । कैसे गरीबों को सताया गया और लोगों को बोलने नहीं दिया गया । यह हम सब जानते हैं लेकिन जनता सरकार बोलती नहीं काम कर के दिखा रही है । पिछले दस महीनों में चीजों के भाव कम कर दिये । जनता साड़ी जो 30 रुपये में मिलती थी आज 15 रुपये में मिल रही है । शक्कर जो 5 रुपये के भाव पर बिक रही थी आज 3.20 में मिल रही है । तो यह जनता सरकार की उपलब्धियां हैं जिन को कोई मिटा नहीं सकता । यही मेरा निवेदन है कि और मुझे खुशी है कि आप ने मुझे इतना समय दिया । धन्यवाद ।

SHRI P. RAMAMURTI (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, in the President's Address much has been said about the restoration of democracy, the democratic rights of the people. We welcome it to the extent it has been done. But at the same time I would like to point out that even as we were fighting for the democratic rights in this country and even as our Indians abroad during the period of Emergency, rallied and demonstrated whenever Ministers from here went to England or other countries, the people of other countries who are here—those countries where democracy is suppressed—have a right to protest against that, I am extremely sorry to point out that when the Shah of Iran visited this country and when some students of that country demonstrated against the suppression of all democratic rights in that country, they were arrested and the people who sympathised with them were arrested. I do not know how we can reconcile our pride restoration of democrats into this suppression of the right of these people to fight for the democratic rights in that country. I would like to point out in this connection that during the period of Emergency when the Indians and Indian students in Britain and America demonstrated against the Emergency, the Janata Party people and we also circulated the news of such demonstrations under secret circulars. I would like to ask the Government of India to reconsider their position in this perspective. Similarly, when the Palestinians here demonstrated, before the Egyptian Embassy they were arrested and the cases are still going on. We all know that throughout the world, in every country, the Palestinian students demonstrated when Sadat betrayed the Arab unity and went over for talks with the Israelis; the students and the people throughout the world, in every part of the world, went on demonstrating and even some of the embassies were burnt, but in no other part of the world has action been taken against those students. Unfortunately India is the only country where for demonstrations against the disruption of the Arab unity action has been taken against those students. I would ask the Government to reconsider that position.

I would not like to deal with other economic aspects and foreign affairs in this speech because the time at my disposal is very short. I would like to confine my whole speech to the question of Centre-State relations which has now assumed a tremendous importance. The Prime Minister does not want to have a national debate

on that. But whether the Prime Minister wants it or not, a national debate is - *6iir~"Knd* I am glad to say that even the President of this country has joined that national debate. In the last interview that he gave to the LINK on the 25th of last month he stated his own experience as a Chief Minister,, how even for every small thing he had to come here and discuss with an official, a Deputy Secretary, in order to get that thing done. If this has been""the experience of the President of" India 20 years ago, one can imagine what the position today is. Now,, Sir, I do not want to go into the details of the working of the various State Governments and the Central Government. ,

I would like to take the Constitution and point "out"{hat as far as this Constitution is concerned, it is not a question of working it in a flexible manner. The Constitutional safeguards have got to be built in, in order to see that the States function within their sphere without any let or hindrance by the Central Government. I would like to point out that as far as our Constitution is concerned, section by section or article toy article, it is the replica of the Government of India Act, 1S35. And that was an Act which the national movement rejected *in toto.* In 1935, for example, in the then central Legislative Council, the Congress Party, together with the Muslim League, jointly passed a Resolution which stated among other things,

> This House is of the opinion that it is most xinsatisfactory and disappointing inasmuch as it includes various objectionable features, particularly, the establishment of second chambers, extraordinary and special powers of the Governors which render the real control, as for the scheme of provincial autonomy, of the executive and legislature ineffective.

This was the Resolution adopted by the Central Legislative Council in 1935. With reference to the Government of India Act of 1935, I can quote chapters and verse from the speeches of Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Parasad,, Sardar Vallabhbhai Patel, Acharya Kiipalani and Maulana Azad who, after that, in successive sessions of the Congress spoke on this subject. I was then part of the Congress and I was also fighting against the imposition of the Government of India Act of 1935. And the main ground on which we rejected the scheme of Provincial Autonomy of that 1935 Act was that the provincial autonomy that was supposed to have been enshrined therein was farcical for the simple reason that whereas the responsibilities of the provinces were very great and all the nation building work and activities were under the charge of the provincial Governments, the Provincial Governments did not have the" financial resources to discharge the responsibilities. And what is more,, the power of the Viceroy to interfere in the power of the so-called federal structure which was at that time contemplated was such that the so-called provincial autonomy was rendered meaningless and it was an absolute farce. This was the very ground on which we rejected the Government of India Act of 1935.

And today, what is the position? What is the position today in the present Constitution of India? This is what I would like t° point out.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Would you like to continue your speech after lunch?

SHRI P. RAMAMURTI; Yes, I would continue my speech after lunch-

श्री उपसभापति : अब सदन दो बजे तक के लिए स्थगित किया जाता हैं ।

> The House then adjourned for lunch at fifty-nine minutes past twelve of the clock.

The House reassembled after lunch at three minutes past two of the clock, The Vice-Chairman, (Shri H. M. Trivedi) in the Chair.

SHRI P. RAMAMURTI: Sir, this morning. I was talking about the new Constitution, the Constitution of India

(Shri P. Ramamurti] that we have now, as being in essential features the replica of the Government of India Act, 1935. But, before that, I would like to point out that after the Motilal Nehru Committee was appointed in the year 1927 by the Congress Party to frame a constitution for India,, the Motilal Nehru Committee, of which the late Shri Jawaharlal Nehru was the General Secretary, had recommended a constitution for India. The Motilal Nehru Committee had recommended a constitution for India which recognised that *the* linguistic groups of this country were distinct groups, I won't use the word 'nationality' because it is jarring on the ears of somebody. But the national movement itself had recognised that the linguistic groups as distinct groups and it had stated that in free India provinces created by the British Government must he broken into linguistic provinces and it had recommended a constitution with the widest autonomy for these provinces. I would also like to point out that in the August 8, 1942 Resolution, the "Quit India" Resolution as it came to be known, was passed at the stroke of midnight, when I was present as a member of the A.I.C.C. The All-India Congress Committee, in the operative part, authorised Mahatma Gandhi to start a movement. Because it wanted to enthuse the entire people of the country speaking different languages to participate in the war against fascism, it demanded the Government of Britain to appoint a provisional Government in India consisting of all political groups in order to carry on the war effort. In that Resolution, the A. I. C. C. said that the provisional Government will among other things evolve a scheme for a Constituent Assembly which will prepare a Constitution for the Government of India. Mark these words: this is the most important point; "The Constitution according to the congress view, should be a federal one with the largest measure of autonomy for the federating units wd with rpsHuary powers vesting with th° U"its." This solemn undertaking was given by the Congress in 1942—August 8—on the eve of starting what was called the 'Quit India Movement.' Now, here is a Constitution which goes completely against that solemn undertaking and which gives it a complete go-by. Ali residuary powers; are vested in the Central government as per the last item in the 1st list of the Seventh Schedule. And still if we say that the undertaking given solemnly to the people by the National Movement in the struggle against imperialism must be honoured by free India, we are called anti-nationals, that we are for separation. If we are for separation, I must point out, then all those people who participated in that AICC meeting in passing this Resolution almost unanimously, including Mahatma Gandhi, Sar-dar Vallabh Bhai Patel, Raj en Babu Pt. Jawaharlal Nehru and Maulana Azad, who presided over that session— all these people were separatists. It is because they knew that in a country with this multi-lingual character, with distinct multi-lingual groups, unless a federal structure is evolved with the widest autonomy for the federating States, the unity of this country cannot be maintained that solemn undertaking was given. The unity of this country was forged during the struggle against imperialism against a common enemy, India was never a politically united country throughout its history and for the first time political unity was evolved in this country in the struggle against British imperialism. And if that structure, if that unity, has got to be cemented, it is not going to be done by any number of National Integration Committees, but it can only be cemented on the basis of the struggle of the common people, the downtrodden people, the working class, the peasantry and other exploited people against exploitation. Therefore, our party is interested much more than anybody else in fighting against divisive forces. In this connection I may point out that when the D.M.K. in Madras was fighting for a separate Dravida Nadu, it was our party that carried on a v'grous struggle against that ideology. Even Mr. C. Subramaniam, who was then the

leader of the House, had to quote from my writings to counter it. Therefore, we yield to none in maintaining, preserving and cementing the unity of this country. All that I say is that in order to cement that unity, the federating States must have enough powers to carry on their responsibilities which they are charged with. Now, I want to point out that the 1935 Constitution in its Seventh Schedule—unfortunately, it so happens that the same Seventh Schedule also in the Seventh Schedule here—defines the powers of various States and the Centre as also what is called the Concurrent List. The 1935 Government of India Act also contains the same Lists—the Central List, the State List and the Concurrent List.And if you take the subjects, you will find the same thing. You would not find anything different. The only thing is that the Concurrent List contains 36 items in the Government of India Act, 1935. The present Constitution has increased the number of items from 36 to 47. Beyond that there is absolutely no difference whatsoever. What are the provisions? You will kindly bear with me this is a very important subject on which I am speaking. What were the responsibilities of the State? Public order, Prisons. Local Government, Public Health, Relief to Disabled and the Unemployed, Communications, that is. Roads, Bridges, Roadways, Inland Waterways, Agriculture in all its aspects. Development of agriculture in all its aspects. Water supply, including Irrigation, Canals, Drainage, Land Reforms Fisheries, Money-lending. Agricultural Indebt. edness, Industries, Theatres. Dramatic Performances—every thing. Th$_e$ present constitution has also listed the same items in the State list of the Seventh Schedule. These are the vital functions which the State has got to fulfil. What are the resources in order to do that? The resources are the same as have been defined in the 1W5 Government of India Act. What are the resources available to the States in order to fulfil all these functions? These are land revenue, agricultural income-tax, estate duty on agricultural land, excise duties on all alcoholic liquors— with prohibition that source will also go—sales-tax and professional tax**.** These are the only resources which the State has got. Actually, land revenue and sales-tax are the only two itema and the States are charged with the responsibility of doing welfare activities for the people in respect of all their vital needs. It is precisely for this reason that the Congress Party as well as the National Movement rejected the 1935 Act. They rejected it because it wanted to divert the attention of the people from the struggle against the British Government to the Ministries that may have been formed under the 1935 Act. That was why there was a ii iious debate whether to accept the office in the provinces or not. I must say that the same provision in the present Constitution is meant to divert the attention of th$_e$ people from the struggle against the exploitation of the all-powerful centre dominated by big business to the State ministries who cannot perform any of these functions. The same policy of divide and rule has been adopted by this Constitution, That is the gravamen of my charge. Apart from these resources, the other source of income for the States is the divisible pool of the income-tax collected by the Centre. The whole of the income-tax that is raised by the Government of India can be divided among the States on the basis of the formula recommended by the Finance Commission, beyond that, there are some grants in-aid. For the grants-in-aid, the States have got to take the begging bowl to the Central Government and it depends on the sweet will and pleasure of the Central Government. All sorts of political pressures can operate, I know that in 1970 when Shrimati Indira Gandhi was in need of the help of the D.M.K. for the elections in 1971, she visited Madras, Tamil Nadu, and immediately sanctioned 20 crores of rupees for drought relief. It is political pressure. Therefore, the States have got to depend upon the sweet will and pleasure of the Central Government. Political presure and political conside-' rations operate on the Central Gov-

[Shri P. Ramamurti]

ernment and nobody can say that the Central Government will be free from these pressure groups. Therefore, the States have got to come with begging be wis. Even with regard to the income-tax, the 1935 Act says that corporation tax will not form part of the income-tax. The present Constitution also says that corporation tax is not income-tax. Then there is also another proviso. In order to get circumvent this provision, the 1935 Act says that if the Government of India imposes a surcharge on the income-tax—it is increased income tax, but they call it surcharge—then that surcharge will not form part of the divisible pool. The same thing is repeated in the Constitution. Therefore, I want to point out that as far as the financial resources are concerned, they have got to depend upon the sweet will and pleasure of the Central Government. Unless this financial lacuna, this financial imbalance, is removed, how can the States fulfil those functions? This is one aspect of the question that I want to point out.

Another thing that I want to point out is this. What is the position even with regard to the functions, which are within the competence of the State Government as per the State list? The position is that the Governor—under article 200 and article 201—can reserve any Bill passed by the State Legislature even with regard to those subjects which are listed as State subjects for the assent of the President of India, that is the Government of India. What has happened in practice for the last lany years?

Every land reform measure is entirely the exclusive preserve of the State according to List II. But then what happens? Every official land reform Bill before it is placed before the Assembly has got to be sent to the Central Government and its approval got with regard to those provisions. And who are the people to decide? The Chief Minister of a State cannoi discuss with the Prime Minister because the Prime Minister is busy and all th*"" people have no time, they go to a Deputy Secretary who in the ultimate analysis has got to decide and he puts up a note. Therefore, even with regard to those subjects on which the State is entirely competent according to the Constitution to enact laws, even with regard to those subjects it is always sent to the Central Government. Either before the enactment you have got to get the permission of the Central Government; otherwise after the enactment, the Governor always sends it to the Central Government for its assent. The crux of the matter is that, that this is now a question of democracy versus Bureaucracy. Therefore, where is the State autonomy? Where is the autonomy. Under these provisions, if the Central Government happens to be of a different character and the State Government happpens to be more progressive than the Central Government and it passes a legislation with regard to land reforms which the Central Government does not like, which the party in power at the Centre does not like, then in that case down comes the axe saying, "We are not giving you the assent unless you change this and unless you change that." Today this position exists not only with regard to land reforms, but with regard to almost all bills of the State Government, in reality what happens is this. The States have been reduced to a position of municipality. In 1952, when Mr. Rajagopalachari was the Chief Minister—I was then the Leader of the Opposition in the Madras Assembly—when so many demands were made on him by the members of his own party, he said, "What is the use of your making all these demands? After all, what is a State under this Constitution? It is a glorified municipality." This is what he said in the Assembly. And I said, "Well. Mr. Rajagopalachari, you have now agreed to my position. We have been saying that it is a glo-ified municipality. But then why not you join me and our Party in fighting the Central Government for a revision of the Constitution." Mr. Rajagopalachari, in his reply stated, "Mr. Ramamurti wants me to fight the Centre. Why should I fight

the Centre? After all, they are my .friends. When I can get the things by gentle persuasion, why should I enter into a fight?" This is what Mr. Rajagopalachari said. It is there in the record of the Madras Assembly proceedings. After all his persuasion what has happened is that the powers of the Centre have been more and more increased, amendment after amendment has been made to the Constitution as it emerged in 1951, and more and more powers have been taken by the Centre so much so today the States have been reduced to—I do not know what to call it and I cannot call it a glorified municipality—at that time he called it so and n(>w I would call it—a glorified panchayat. The States today have been reduced to the position of glorified panchayats. And today if voices are raised that there must be a national debate on this question, the States cannot be reduced to the position of a glorified panchayat, what is wrong about it? It was all right at that time when one Party ruled in the centre and all the States, it was all a family affair, and a circular from the Central Government was honoured by all those people. Those days arc gone now. It is not going to be possible now. Mr. Sanjiva Reddy has said, the President of India has said, the Rashtrapati has said that today different parties have come to power in different States, They have got their policies.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Please conclude.

SHRI P. RAMAMURTI: Just a few minutes, Sir. We have got our policies. In West Bengal, for example, we are committed to carrying out certain policies. I may say that four months back, the West Bengal Legislature passed a Resolution defining the qualification for resumption of land for self-cultivation. It defined what is meant by self-cultivation . It said that it can only be resumed if the landlord actually contributes personal, physical labour by himself or by members of his family and if he resides in the village for a certain number of days. This only means self-cultivation. It is still awaiting the assent of the President, *i.e.,* the Government of India. I know the Janata Party may not like that. Many landed interests in the Janata Party may not like that. And because the Central Government does not want that we are not able to meet the commitment that we have made to the people of West Bengal even though this is a subject which falls completely within the competence of the State Legislature. So, how can things go on like this? If things go on like this, then naturally people in different States will begin to say, well, to hell with this. (Time Bell). Kindly give me a few minutes more, please. The divisive forces will begin to rear their head again. It is because we are extremely anxious to see that such divisive forces do not raise their heads again, that we are anxious to see that this question is debated and properly debated and is settled once and for all. *(Time Bell).* Now, Sir, just one more point. The other day I saw a newspaper report. I do not know whether it is correct. The other day Mr. Morarji Desai, our Prime Minister, is reported to have said it and it has appeared only in the Standard. I have not seen it in any other paper. I do not know if it is true. It says: 'The C.P.I. (M) had done certain things in West Bengal that it should not have, Mr. Morarji Desai said in an exclusive interview while boarding the special Air Force Plane Rajhansa. He, however, refused to comment."

AN HON. MEMBER: Which newspaper has got this report?

SHRI P. RAMAMURTI: This report is contained in day before yesterday's Business Standard.

SHR[T]MATI SUMITRA G. KUL-KARNI: It must be off standard.

SHRI P. RAMAMURTI; This can be contradicted. I will be happy if this statement is contradicted. I want to tell you that I did not expect that a person of the standing of our Prime

[Shri P. Ramamurti]

Minister, Mr. Morarji Desai, would make such a statement. If you have got any specific charges against the West Bengal Government bring it out openly, say it openly. Tell the Chief Minister of West Bengal that it is here that you have done wrong. He might not have done something which is according to your policy. We axe not running the West Bengal Government to carry out the policy of the Janata Government. We are not elected by the Janata Party. As a matter of fact, the Janata Party was rejected by the people of West Bengal and we were elected there on the basis of the promises that we have made and so long as we are able to carry out the promises that we have made and within the competence of the State Legislature, the Central Government has no business whatsoever to interfere with that. If that Government transgress the provisions of the Constitution, then there is the Supreme Court to decide that such and such a law is beyond the competence of the State Government and therefore the Supreme Court can strike it down. But what "Business has the Central Government got to interfere so long as we stick to this thing. We are saying that this is not conducive to the improvement of Centre-State relations. If Comrade Jyoti Basu has done something, have a discussion with him, point out to him that you have done this wrong. You first get yourself convinced about it. You might get some police reports. Are we to depend on police reports? Are the police to decide the conduct of elected representatives? Therefore, Sir, this is not the way in which this question can be decided. Therefore, I say that this whole problem has now attained a tremendous importance. I want to tell you that even the other Chief Ministers, those people who have been the Chief Ministers, know where exactly the shoe pinches. Today, for example, Shri Sanjiva Reddy has come out with the position. And, I know, as a matter of fact, Mr. Babhubai Desai, who happens to be the Chief Minister belonging to the Janata Party itself, has agreed to attend a conference to be held in Chandigarh because he also feels aggrieved.

AN HON. MEMBER: Not Mr. Babhubai Desai but Mr. Babhubai Patel.

SHRI P. RAMAMURTI: All right. I am sorry, it is Mr. Babhubai Patel who has agreed to do that. I know you might impose party discipline and prevent him from attending it but nonetheless this feeling is growing in this country and every Chief Minister of this country is feeling this state of helplessness when he has got to take the begging bowl. Is this position to continue? If you want to cement the unity that has been achieved during the struggle for independence against British imperialism, now a new common bond must be evolved and a new common bond can only be evolved on the basis of the States feeling that they are equal partners in developing the country and that they are not just subordinates or servants of the Central Government and for that proper provisions must be made in the Constitution. (Time *Bell rings).* Just a minute, Sir. Therefore, to say that a national debate cannot take place is burking the question. Whether Mr. Morarji Desai wants it or not, whether the Janata Party wants it or not, there will be a national debate on this question. Nobody can stop the people of this country speaking on this thing and I know that the truth will prevail because we are interested in the unity of this country much more than anything else. It is the exploiting forces that want *to* divide the working class. They help the Shiva Sena and this thing and that thing, which often-times receive the support of the ruling party in various places. Therefore, Sir, in the interests of unity for which we have fought. I appeal to the Government of India give up this thinking and have an open mind. Let not the Prime Minister say that he will have a talk with Mr. Jyoti Basu. What i_s the use of talking to Mr. Jyoti Basu when it is a question concerning the entire people of this

country. Therefore, there must be a national debate on this question of Constitution and we must see how far it has worked successfully during the last thirty years. This is a question that has got to be seriously debated on a nation-wide basis, with full freedom to all the State ministers who should not be fettered by mandate from their Parties. Just a last point I want to mention that we who ask for this are carrying on the heritage of the national movement. This is the heritage of the national movement. We want the national movements promises to the people to be fulfilled, and those who today refuse to do that, are going against the heritage of the national movement. They are betraying the heritage of the national movement. That is what I wanted to point out. Thank you.

SHRI ABU ABRAHAM (Nominated): Sir, the President has rightly referred at the beginning of his Address, to the cyclone in Andhra. He also referred to the relief measures that are being undertaken there. But I must confess that I am disappointed that the President's Address gives no indication as to what precise measures the Government proposes to take for the long-term welfare of the coastal people, the peasants and the fisher men who live in those areas. There is no indication of any new scheme for these people there is no suggestion of any long-' - for the improvement of the lives of the people there who are the poorest in the country. Sir. the Prime Minister and several Members of Parliament visited the coastal areas of Andhra which were affected by the cyclone. I too went to see the place. It was a shock to see how poor, how famished and how ill-clothed these people are and how wretched their mud huts are and, therefore, how vulnerable they are to disease and to any natural disaster. Even Andhra MPs. were shocked by this experience because even they had not realised how backward and poor some of these areas are. The unfortunate fact is that these coastal areas, a wide belt of about ten miles all along the coast, have been neglected for a very long time. There are no proper roads, no modern sanitation, no electricity, no amenities of any kind, no decent housing, no schools, no community centres and no medical facilities. These are the places where even the district officials pay a visit very seldom. These are really the areas of darkness in this country. Even our political parties have neglected these people although the fishermen are the most exploited people in the country. They are exploited because they are backward and because they deal with a very perishable commodity. If they could be better organised, they could get the basic needs of life like housing, some elementary education etc., they will not be so exploited. Therefore, what we need to do is an overall re-construction of these coastal areas. Right now, in Goa, there is a dispute going on between the traditional boatmen and the trawlers. The trawlers refuse to go deep into the sea; they want to fish in the same area near the coast, because there are more prawns there, The trawlers were not meant to fish in those areas. So, there is a dispute and there is nobody to support these fishermen, except some Catholic priests. This als$_0$ shows" a" kind of political neglect that these people have to suffer from. The Goa Administration seems to be indifferent to these people's demand and we in this House and also in the Lok Sabha have never discussed the problems of these fishermen. So. one cannot blame the Government alone for this, because we are all responsible. T would earnestly suagest that the Government should appoint a special committee or a commission. They are appointing a Backward Classes Commission. Perhaps, a separate committee or commission could be appointed by th$_e$ Government to look into the problems of the people who live in the coastal areas. Those areas have remained extremely neglected and they have to be brought into the mainstream of national life.

LShri Abu Abraham]

As for the disasters and natural calamities as such, we have to think in more fundamental terms always. In the United States, they passed, about 4 years ago, a piece of legislation, a comprehensive legislation, which is called the Disaster Relief Act, 1974. It gives the President wide and •specific powers to use defence and civilian agencies in times of national disasters or other troubles. In the United States, they have also prepared programmes for disaster preparedness, disaster relief, long-range planning and economic reconstruction, This is a continuing programme and this is what we should aim at. We should also have a similar legislation perhaps so that the Central Government is fully equipped to deal with any natural disaster or any internal disturbance, whether it is cyclone or floods or drought or communal violence. The Government should also sponsor studies on these subjects, jut as they do in the U.S.A. where they iiave a number of these studies being undertaken, which will enable the administrators and the general public to understand the problems involved so that they can be better prepared to deal with them.

Perhaps, one reason why the coastal areas are being neglected, the fishermen in particular, is that th*» coastline is too far from New Delni. There are no fishermen to march to Parliament House. They do not even have a spokesman to represent tneii case in Parliament although they are an important sector of our aconorr.y. There is a saying 'Distance lends enchantment to the view*. Perhaps, the Central Government has a romantic view of these areas. Perhaps, a more suitable saying in this context is 'Out of sight, out of mind'. This seems to be a truer statement as fat-as some of the Southern and Eastern States are concerned. It :s far more difficult for a State like West Bengal or Orissa or Kerala to get the attention of the Central Government in regard to certain problems tlian it is for a State like Haryana, Punjab or U.P. Whereas the Chief Minister ot Haryana or Punjab can get things done, perhaps, over the telephone, a Minister from Kerala or West Bengal has to keep flying to Delhi every week to discuss even small matters. Even in regard to a small project, they have to get the approval of the Central Government and they have to actually come here.

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO (Orissa): The Orissa C. M. cannot fly here. There is no direct route.

SHRI ABU ABRAHAM: Therefore, this is how our administrative and political system is working. I am coming to the question about which Mr. Ramamurti has so eloquently spoken just 'now, the question of more autonomy for the States. This is another subject about which the President's Address has nothing to say. It is a pity because this is an important subject and one wants at least ta have an open discussion even if the demand for greater autonomy is not to be immediately accepted. Now, we find that Mr. Mandal only yesterday in the Lok Sabha has stated that the time is not opportune for such a debate. He has stated that the time is not propitious: this is the exact word he has used. He has stated that the time is not opportune to alter the Centre-State relations and this is not a propitious time for a national debate. Now, what is the propitious time for a debate? Do we have to consult an astrologer before we start a debate, to find out the time? As Mr. Ramamurti has pointed out, the debate has already started and nobody can stop a debate like this. This is very much in the minds of the people and whoever I have talked to in the States farther away from New Delhi, from the central capital, this is a subject on which they have very strong feelings and the feelings are

growing greater and greater. It is a misrepresentation to say that the demand for greater autonomy has anything to do with separatism. This is totally untrue. We are still suffering from the hang-over of the partition days. But conditions have changed since then. No serious person can really say that the people of West Bengal or Tamil Nadu or Kerala want to secede from the Union. All they want is a greater control, a greater financial conrtol, over the affairs of the States and they do not want to be tied down to the apronstrings of the Central Government in all kinds of matters and to be patronised by the all-knowing officials of the Central Secretariat. Sir, I would say indeed that greater autonomy is the only way to remove the kind of frustrations and tensions that we see all round, which the President has been pleased to refer to as the suppressed feelings of the people finding expression in various forms, protests and agitations. But this is not a case of 19 months of emergency bringing up these frustrations. These have been there all the time and they have been growing all the time. So, autonomy in my opinion is the only way to remove these frustrations and strengthen the Centre and the country as a whole. If it is not granted, the demand for separate States might arise.

Also, connected with this question of autonomy is the question of smaller States. In fact, they are the two sides of the same coin. Smaller States will create greater participation by the people and greater efficiency in the admjnistration. Even Mr. Charan Singh has been the champion of the smaller States, but it is surprising that the Janata Party which is committed to decentralisation should turn its face against autonomy and smaller States so soon after coming to power. On smaller States. Mr. Charan Singh said in this House the other day that the time is not opportune, but surely we can have a debate on this subject as well. When we have had a debate, pherhaps we might appoint a commission again to make recommendations on the greater autonomy for the States and for a sensible, practical division of some of the larger States, so that there will be more participation of the people, as I said, and also so that this administration would have a better grasp of the problems of the smaller States. To me this is a very urgent matter and, as I said, I am surprised that there ia no mention of these subjects in the Presidential Address and I hope that the Government will soon make up for this omission.

شری محمد یونس سلیم (آندھرا پردیش) : جناب وائس چیرمین صاحب - میں بہت افسوس کے ساتھ راشٹرپتی جی کے خطبہ کے متعلق یہ کہتے ہوئے اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں کہ جس دن اس پارلیمنٹ کے شروع کرنے کی تاریخ رکھی گئی جس دن راشٹرپتی جی کا خطبہ ہو رہا تھا سینٹرل ہال میں اس دن ربیع الاول کی بارہ تاریخ تھی - بعض جنتریوں کے اعتبار سے ۲۰ کو تھی اور بعض کے اعتبار سے ۲۱ کو تھی - یہ ہم مسلمانوں کے پیغمبر کی پیدائش کا دن ہے - یہ حکومت جو اس وقت برسراقتدار ہے اس نے وقتاً فوقتاً انتخابات سے لے کر اور انتخابات سے بعد تک یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس ملک میں سیکولرزم کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریگی اگر گورنمنٹ کا کلینڈر اٹھا کر دیکھا جائے تو جناب وائس چیرمین صاحب - اس ملک میں جتنے مذہبوں کے ماننے والے رہتے ہیں سب کے پیغمبروں اور بانیوں کی تاریخ پیدائش کو تعطیل دی جاری ہے - میں نے گورنمنٹ کے کلینڈر سے یہ نوٹ

[شری محمد یونس سلیم]

کیا کہ مہابیر جینتی کی تعطیل ہوتی ہے بدھ جینتی کی تعطیل ہوتی ہے- جنم اشٹمی کی تعطیل ہوتی ہے - مہاتما گاندھی کے برتھ ڈے کی تعطیل ہوتی ہے - گورو نانک کے برتھ ڈے کی تعطیل ہوتی ہے - کرسمس کی تعطیل ... - لیکن اس ملک میں آٹھ دس کروڑ مسلمانوں کے جذبات کا خیال نہیں کیا جاتا ہے اور ان کے لئے ۱۲ ربیع الاول کو تعطیل دینے کے لئے گنجائش نہیں کی جاتی ہے - اور یہ دعوی کیا جاتا ہے کہ ہم اس ملک میں سیکولر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور مذہب کی بنیاد پر ہم کوئی ڈسکریمینیشن کرنا نہیں چاہتے ہیں ایک مذہب کے ماننے والے اور دوسرے مذہب کے ماننے والے کے درمیان— کیا میں آپ کے توسط سے جنتا حکومت سے یہ سوال کر سکتا ہوں کہ کیا ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ مسلمانوں کے پیغمبر جن کی ساری دنیا میں عزت اور وقار ہے ان کی پیدائش کی تاریخ میں اس طرح سے چھٹی دینی چاہئے جس طرح سے اس ملک میں دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے مہاتماؤں اور بانیوں کی پیدائش کے وقت دی جاتی ہے- مجھے افسوس ہے اور دکھ ہے کہ اس طرف حکومت کی توجہ نہیں گئی- دوسری بات جو اس سے زیادہ دکھ کے ساتھ جناب وائس چیرمین صاحب میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فخرالدین علی احمد مرحوم صاحب ہمارے ملک کے دوسرے راشٹرپتی تھے جو اقلیتی طبقہ سے تعلق رکھتے تھے- اس ملک میں اس سے پہلے دو پرائم منسٹر اور ایک پریذیڈنٹ (راشٹر پتی) ایسے وقت دنیا سے اٹھے کہ جب وہ اپنے عہدے پر برقرار تھے - جواہر لال جی - لال بہادر شاستری اور ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم - حکومت نے اپنے تعارف سے ان کی سمادھی اور ان کے مقبرے بنائے ڈاکٹر ذاکر حسین کے مقبرے کو بنانے میں جو جامعہ ملیہ کے قریب بنایا گیا ہے کافی رقم خرچ کی گئی اور اس وقت کی حکومت نے کافی توجہ سے ان کے مقبرے کو بنایا مگر یہ ہمارے لئے - اس ملک کے لئے اس حکومت کے لئے باعث شرم ہے کہ اس پارلیمنٹ سے دس قدم کے فاصلہ پر ان کا مقبرہ کس مپرسی کی حالت میں پڑا ہوا ہے جہاں ایک شخص بھی نہیں ہے جو وہاں کئے جاتے ہیں ان کو جانے سے روکے - صفائی دیتا ہے جب جب بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے اب تعمیر کے لئے کام شروع کیا جا رہا ہے - مگر اس بات کو برابر سال بھر سے ٹالا جا رہا ہے - یہاں تک کہ اس سے پہلے ۱۱ فروری کو ان کی پہلی برسی بھی منائی جا چکی ہے - میں آپ کے توسط سے جنتا حکومت سے صاف طور سے

جو چیف جسٹس بنے ہیں جنہوں نے کل حلف لی ہے وہ اس میں شریک تھے اس لئے یہ جد و جہد شروع کی جائے کہ اس کو چیف جسٹس بنایا جائے یا نہیں بنایا جائے یہ بڑی شرم ناک بات ہے اور اس سے اس ملک کا وقار بڑھا نہیں بلکہ اس سے صدمہ پہنچا ہے کہوں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ ججوں کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ دیتے وقت یہ سوچیں کہ ہمارے اس فیصلہ دینے کے بعد ہمارے مستقبل کا کیا حشر ہونے والا ہے - مہر وائس چیرمین صاحب— اس سے پہلے بھی ہاؤس میں اس بات کی طرف توجہ دلا چکا ہوں— یہ طریقہ ہمارے ملک سے ہمیشہ کے لئے ختم ہو جانا چاہئے کہ جو ججیز سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ہیں آئندہ کے لئے کچھ امید ہیں ان کے عہدے سے ہٹنے کے بعد ان کی دامن گیر ہوں - جس وقت وہ انصاف کرتے ہوں اس وقت ان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہئے کوئی خوف نہیں ہونا چاہئے اور نہ کوئی ڈر ہونا چاہئے - اور نہ ان پر کسی کے رحم و کرم کی بارش کی توقع ہونی چاہئے بلا خیر یا خوف کے ان کو اپنا فرض انجام دینا چاہئے - جس طرح سے کمیشنوں کے چیرمین اور مختلف کمیٹیوں کے ارکان بنا کر ججوں کو نوازہ جاتا ہے یا جس طرح یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فخرالدین صاحب کے مقبرہ کو بلوانے کا پروگرام رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں - اس ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر حکومت اس کام کو نہ کرے تو بھی اس کام کو ایک منٹ میں کرنے کی ہمت رکھتے ہیں لیکن اس طرح سے کسی کے ساتھ سلوک کرنا جس نے اس ملک کی اپنی پوری عمر پوری زندگی خدمت کی ہے جو اس ملک کو آزاد کرانے کے لئے آزادی کا سپاہی رہا ہے جس نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لئے جیلوں میں رہ کر زندگی گزاری ہے اس کے ساتھ یہ حکومت ایسا سلوک کرتی ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس حکومت کو سیکولرزم کی کتنی پاسداری ہے - میں ان دو باتوں کی طرف آپ کا خاص دھیان بٹانا چاہتا ہوں -

قبل اس کے کہ میں کوئی اور بات کہوں مجھے افسوس ہے کہ گزشتہ دو مہینے سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے انتخابات کے متعلق جو فضا پیدا کی گئی وہ بڑی افسوس ناک اور بڑی شرم ناک تھی -

ملک کی سب سے بڑی عدالت جوڈیشیری اور عدلیہ کے لئے سیاسی بنیاد پر یا کسی ایک فیصلہ کے نافذ کرنے کی بنیاد پر یہ بحث اٹھانا کہ چونکہ بمبئی کورپس کی درخواست کے اوپر جو فیصلہ کیا گیا تھا موجودہ

تیار نہیں ہوں کہ سارے جہاں کے لوگ جھوٹے ہیں اور حکومت کے لوگ سچے ہیں؟ - احمدآباد کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ بھیونڈی کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ مئوناتھ بھنجن اور بنارس کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ کانپور کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ میرٹھ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں صرف سچ بولتے ہیں سرکار کے عہدےدار اس لئے اس پر کڑی توجہ کی ضرورت ہے اور یہ جو کمیشنس مقرر کئے گئے ہیں جو پولیس کمیشن اور اقلیتوں کا کمیشن مقرر کیا گیا ہے یہ تماشہ ہے - ہم اس جال میں پھنسنے والے نہیں ہیں - اقلیتی کمیشن کے بارے میں بڑی اور نیچی اونچی باتوں کا ذکر کیا گیا مگر یہ کمیشن کیا ہے اس کے پیچھے قانونی مدعا کیا ہے قانونی سینکٹیٹی کیا ہے -

It is not a statutory Commission. It has Viot been constituted under any law of the land. It is just like any other ordinary Committee constituted by the Government. Therefore, it is not a statutory Commission.

جناب وائس چیرمین صاحب — میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اقلیتی کمیشن میں بڑے بڑے وعدے کئے گئے ہیں - چناؤ کو جیتنے کے لئے ووٹروں کو پھسلانے کے لئے اقلیتوں کو بے وقوف بنانے کے لئے بڑے بڑے وعدے کئے گئے اور کہا گیا کہ ہم کمیشن قائم کریںگے -

[شری محمد یونس سلیم]

سے سیاسی پارٹیوں میں ٹکٹ دے کر منسٹری اور دوسرے عہدوں پر سرنواز کیا جاتا ہے اس سے جوڈیشری کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے اور اگر اس کو روکا نہیں گیا تو اس سے ملک میں کرپشن کے دروازہ کھلنے والے ہیں اور میں اس کے خلاف اپنی آواز اٹھا کر آپ کو پھر سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں- جناب وائس چیرمین صاحب — دوسرے صاحبان نے بھی توجہ دلائی ہاؤس کی اور میں بھی اپنی آواز اٹھانا چاہتا ہوں کہ گذشتہ ایک سال کے اندر اس ملک میں جو فرقہ وارانہ فسادات ہوئے اس ملک میں جس طرح سے ہریجنوں اور کمزور طبقوں پر مظالم کئے گئے اس کے اعداد و شمار کی تعداد ہزاروں تک پہنچ رہی ہے لیکن پریذیڈنٹ کے خطبہ میں اس کا ذکر تک نہیں ہے - یہ ایسا خطرہ ہے کہ جس طرف حکومت کو متوجہ ہونا چاہئے - بنارس میں جو کچھ ہوا لکھنؤ میں جو کچھ ہوا کانپور میں جو کچھ ہوا میرٹھ اور بہار میں جو کچھ ہوا ہندوستان کے مختلف حصوں میں جس طرح سے غریبوں کا خون کیا گیا جس طرح سے پی - اے سی اور پولیس نے ان کو ظلم سے بچانے کے بجائے ان کے گھروں میں جاکر ان کو لوٹا - ان کی عورتوں کو بے عزت کیا یہ انتہائی شرم کی بات ہے اور میں یہ ماننے کے لئے

اقلیتی کمیشن میں وہ لوگ لئے گئے ھیں جن کے متعلق میں کچھ نہیں کہنا چاھتا - مجھے صرف ایک بات عرض کرنا ھے کہ جو لوگ لئے گئے ھیں ان پر اقلیتوں کو کوئی بھروسہ نہیں لیکن اگر بھروسہ ھونا بھی یہ کیا تماشہ ھے جب تک کہ اس کی سفارشات کو کوئی قانونی سیلکٹیٹی نہ ھو تب تک قلیتی کمیشن ان مسئلوں پر غور کرنے کے بعد اپنی جو رائے دیتا ھے - اس کو ماننا یا نہ ماننا مرکزی اور دوسری حکومتوں کے لئے لازمی نہ ھو یہ ڈھونگ ھے یہ کھلونے دیئے جاتے ھیں -

تمغاؤں میں الجھایا گیا ھوں
کھلونے دیکے بہلایا گیا ھوں

یہ کھلونا دینے سے کام نہیں چلے گا ایک بات —

دوسری بات یہ ھے کہ اس اقلیتی کمیشن کے ساتھ لنگویسٹک مائنارٹیز کو جوڑ کر کیوں پیوند لگایا گیا ایک لینگویج کمیشن آپ کے یہاں موجود ھے اس کے ٹرمس آف ریفرنس میں تبدیلی کرکے اگر لنگویسٹک مائنرٹیز کے ساتھ کوئی بے انصافی ھو رھی ھے تو اس کے پرویو میں اس کو لے آتے - اس اقلیتی کمیشن کے ساتھ جو آپ نے لنگویسٹک مائنریٹیز کا جوڑ لگایا اس کے معنی یہ ھیں کہ اس ملک میں رھنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ھے جو مائنریٹی میں نہ ھو - آج لنگویسٹک مائنریٹی کے معنی یہ ھیں کہ چیرمین صاحب آپ یہاں تشریف فرما ھیں تو مائنرٹیز میں ھیں لیکن اپنی سٹیٹ میں جائینگے تو مجورٹی میں ھو جائیں گے ھمارے سیکریٹری جنرل بھالے راو صاحب بیٹھے ھیں یہ مہاراشٹر میں جائیں تو مجارٹی میں ھو جائیں گے لیکن حیدرآباد میں جائیں گے تو مائنریٹیز میں ھو جائیں گے - اس کے معنی یہ ھیں کہ سارے ملک کے لوگ مائنریٹی بن جائیں گے - اوز اس کمیشن کے سامنے اپنے مسئلے پیش کرینگے -

It is a practical joke with the minorities of the country which will not be tolerated hereafter.

SHRI P- RAMAMURTI: Will you please allow me to interrupt you for a miViute? In Tamil Nadu, for example, i_n the $borde_r$ areas $_a$ lot of Telu-gu-speaking people are living. Similarly, in Andhra Pradesh, in the border areas $_a$ lot of Tamil-speaking people are living. Now, if the Andhra Pradesh Government does not make provision for these Tamil-speaking people being taught in their own language, or if the Tamil Nadu Gove-ernment doe_s not make provision for th_e Telugu-speaking people in that area to be taught in their own lan-uage, then has not something got to be done? When we are talking of minorities^ it inevitably happens that people speaking* different languages living in a linguistic State where the majority of the people speak a different]angaug$_e$ will naturally form a minority. What can you do with that?

شری محمد یونس سلیم : میں گذارش یہ کروں گا کہ میرے دوست راما مورتی صاحب نے میری بات کو سمجھا نہیں - میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں لنگویسٹک مائنوریٹی کے ساتھ بھی بے انصافی ہوتی ہے لیکن اس کو دور کرنے کے لئے لینگویج کمیشن کے ٹرمس آف ریفرنس میں تبدیلی کرکے اس کے پرویو میں لانا چاہئے اس لئے کہ اس لینگویج کمیشن کے سامنے سارے دیش کی لنگویسٹک پرابلمس کی تصویر ہے - (وقت کی گھنٹی) — جناب - میں نے یہ دیکھا ہے آپ نے راما مورتی صاحب کو ۲۵ منٹ دیئے ہیں - کم سے کم میرے ساتھ آپ ڈسکریمینیشن نہ کیجئے -

تو میں یہ گذارش کر رہا تھا کہ یہ کمیشن بہت غلط طریقہ سے بنایا گیا ہے اس کے پیچھے اسٹیچوٹری سینکٹیٹی نہیں ہے - پہلے قانون پارلیمنٹ میں بنانا چاہئے تاکہ اس کی سفارشات مینڈیٹری ہو اور مرکزی حکومت کو ماننا ضروری ہو - نہیں تو یہ کاغذ پھینک دیئے جائینگے جیسے یو - پی گورنمینٹ نے ایک کمیشن مقرر کیا تھا اس کی سفارشات کولڈ اسٹوریج میں پڑی ہوئی ہیں - اس لئے یہ میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اقلیت کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں - اس پر دوبارہ غور ہونا چاہئے بغیر مینڈیٹری پراویژن کے مائنوریٹی کمیشن بے کار ہے -

Nobody cared for those recommendations.

دوسرا سوال اس ملک میں اقلیتوں کی بے روزگاری کا ہے - میں اس بات سے واقف ہوں کہ کنسٹی ٹیوشن میں اقلیتوں کو روزگار دینے کے لئے کوئی پراویژن نہیں ہے لیکن میں نے یہ سوال کیا تھا جناب ہوم منسٹر صاحب سے کنسلٹیٹیو کمیٹی میں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یونین پبلک سروس کمیشن مقرر کئے ہیں - سٹیٹ پبلک سروس کمیشن مقرر کئے ہیں لیکن میں آپ سے جواب چاہتا ہوں کہ پبلک سیکٹر میں ریکروٹمینٹ کے لئے آپ نے کون سے کمیشن مقرر کئے ہیں ہزاروں عہدیداروں میں آپ کو دو آدمی بھی نہیں ملینگے -

اسکولوں کے دروازے کالجوں کے دروازے لائسنس کے دروازے روزی روزگار کے دروازے اقلیتوں کے اوپر بند کئے جا رہے ہیں - آپ دلی کے پورے شہر میں چکر لگائیے جس چوراہے پر جائیے آپ پائینگے کہ چھوٹی چھوٹی دوکانیں بنی ہوئی ہیں کوئی برف بیچ رہا ہے - کوئی شربت بیچ رہا ہے کوئی چائے بیچ رہا ہے تو کوئی پان بیچ رہا ہے - ان ہزاروں دوکانوں میں سے دو دوکانیں بھی ایسی نہیں ملینگی جنہیں اقلیتی طبقے کے لوگوں کو الاٹ کیا گیا

تسلی دی جائے اور اردو کو اس ملک میں ایسا درجہ دیا جائے جو ایک شاندار زبان کو دیا جانا چاہئے بلکہ ہوم منسٹر صاحب نے نئی تاریخ ایجاد کر دی ہے نئی ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کے اوپر انکشاف ہوتا ہے کہ اس ملک میں اردو زبان ترک اور مغل لے کر آئے ہیں— ترک تاریخ دانوں کا عالمانہ انداز ہے گفتگو کا ہم کو یہ نہیں معلوم کہاں سے مغل آئے کہاں سے ترک آئے اور کون سی زبان بولتے تھے وائس چیرمین صاحب— جس وقت اس ملک میں مغل اور ترک آئے ہیں اس سے پہلے دکھن کے اندر دکھنی زبان ترقی کر رہی تھی اس کے اندر نثر میں نظم غزل مثنی اور مرثیہ نہ جانے کتنی تعداد میں لکھی جا چکی تھیں - ہمارے چودھری چرن سنگھ فرماتے ہیں یہ ترکوں اور مغلوں کے بھاشا ہے بڑے افسوس کی بات ہے کاش یہ بات چودھری چرن سنگھ صاحب کی نا واقفیت اور نادانی پر ہی ختم ہو جاتی - ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اپنے بہت بڑے تدبر کا ثبوت دیا ہے -

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Now you please finish.

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: Sir, I have taken only 15 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): I am sorry. I have been watching the time.

ہو - سناوشوں، خوشامدوں، عرضیوں اور درخواستوں کے باوجود - جناب عالی یہ کیا سیکولرزم ہے یہ کیسا کنسنسی ٹیوشن ہے یہ کیسی حکومت ہے - کس طرح سے چلے گا یہ ملک - میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس ملک کی اقلیتیں ہمارا جو نیشنل چین ہے اس کا ایک لنک ہے -

And the test of the strength of a chain lies in the weakest link.

اگر اقلیتوں میں قصور ہے اس میں کوئی کمزوری ہے یا کند ذہن ہیں ان میں کوئی انٹیلیجینس نہیں ہے تو ان کے لئے خاص طور سے انتظام کیا جانا چاہئے تاکہ آٹھ کروڑ انسان اس دیش کے بے کار اور نکمے ہو کر نہ رہیں- ۸ کروڑ مسلمان اس دیش کے نکمے ہیں ہماری پوری قوم نکمی ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بدن میں ناسور ہو اور ہم یہ کہیں گے بدن درست ہے- پوری باڈی کو روگ لگا ہوا ہے اس لئے اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے- اس کے بارے میں پریذیڈنٹ ایڈرس میں ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا -

وائس چیرمین صاحب— لنگویسٹک مائنریٹیز کے ساتھ بےانصافی ہو رہی ہے - میں اردو کا رونا کہاں تک روؤں - کئی مرتبہ اس ہاؤس میں اردو کے متعلق بات کہی جا چکی ہے لیکن بجائے اس کے اردو کے ساتھ انصاف کیا جائے - اردو بولنے والوں کو

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM; I am going to conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): You must conclude now.

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: But I may be permitted to make my submission. I am not wasting the time of the Chair or ot the House.

وزیر اعظم شری مرار جی دیسائی جس
وقت اردو کے گھر کا افتتاح کر رہے تھے-
شری آنند نوائن ملا جو انجمن ترقی
اردو کے صدر ھیں ان کی تقریر سن کر
انھوں نے غصہ اور ناراضگی کا اظہار کیا
اُنھوں نے یہ کہا تھا کہ اردو
زبان وہ زبان ھے جس نے اس ملک
کا بٹوارہ کیا اس وقت ھماری گردن
شرم سے جھک گئی کیونکہ پرائم منسٹر
صاحب نے غیر ملکوں کے سامنے غیر
ذمہ دارانہ بات کر رہے تھے ھم غیر
ملکی ڈلیگیٹوں کے سامنے آنکھیں
نہیں ملا سکے - میں یہ بات کہہ
سکتا ھوں کہ آس ملک کا بٹوارہ
اردو نے نہیں کیا اس ملک کا بٹوارہ
مسلمانوں نے نہیں کرایا اس ملک
کا بٹوارہ دوسرے حالات نے کروایا اگر
کوئی یہ کہے کہ اردو زبان نے بٹوارہ
کرانے میں کوئی پارٹ ادا کیا ھے تو
یہ اس کی تاریخ سے ناواقفیت کی
بات ھے - ھم اس چیز کو ماننے کے
لئے تیار نہیں ھیں -

اردو اس ملک کی زبان ھے -
اس ملک میں پیدا ھوئی ھے اس
ملک کے رھنے والے اس زبان کو بولتے
ھیں - اس زبان سے پیار کرتے ھیں
اور اس زبان میں اتنا شاندار لٹریچر
ھے کہ جو دنیا کی بہترین زبانوں کے
مقابلہ میں پیش کیا جا سکتا ھے -
اس لئے اگر اس زبان کے ساتھ بے انصافی
کرینگے تو اس کے معنی یہ ھوں گے
کہ یہ پرائے شگون ناک کٹانے کے برابر
ھوگا - اس لئے آج سخت ضرورت
اس بات کی ھے کہ اردو کے مسئلہ
پر توجہ دی جائے - میں آج اس
ایوان کے سامنے واضح کر دینا چاھتا
ھوں اگر تھوڑے دن اور اردو کے ساتھ
اس طرح سے بے انصافی کی گئی تو اردو
بولنے والے وھی طریقہ اختیار کرینگے
جس طریقہ کو یہ حکومت پہنچانتی
ھے اور وھی زبان بولیں گے جس زبان
کو یہ حکومت سمجھتی ھے -

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Mr. Saleem, **you** must conclude please. Within a minute you must conclude please.

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: Why are you so unkind to me?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): I am not unkind. You have taken more than 25 minutes.

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: I have taken only 17 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRTVEDI): I am sorr$_y$ I am watching the time. I watch it better than you do.

SHRI MOHAMMAD YUNUS .SALEEM: Mr. Ramamurti concluded his speech, at 2-25. Then another gentleman took 25 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): May I explain to you that if every speaker is going to take 25 minutes...

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: There should be no discrimination between one speaker and another speaker. Every speaker belongs to this House. He should be given proper time and proper opportunity. This is not fair. This is very unfair Sir. I strongly protest against this discrimination, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): There is no discrimination at all. I would like you to appreciate that you have had more than your time. I would only like you to conclude quickly.

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: I was not told at the outset how much time would be allotted to me. I was under the impression that the Chair would allot at least 25 minutes to every speaker. I had planned to conclude within 25 minutes. 1 have taken only 17 minutes so far.

دوسری بات کہکر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاھتا ھوں - کل ھی ایک مقرر نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اندرا گاندھی کی حکومت میں اردو کے مسلہ پر غور کرنے کے لئے گجرال کمیٹی مقرر کی گئی تھی اس کمیٹی نے اس ملک کا دورہ کر کے اپنی رپورٹ دی اس میں بہت سے ملک کے رھنے والے - اخبار نویس - ادیب - شاعر اور اردو کے جاننے والے لوگ شامل تھے لیکن آج یہ رپورٹ ھوم منسٹری کے شیلف میں پڑی ھوئی ھے - میں چاھوں گا کہ اس رپورٹ کو اس ایوان کے سامنے لایا جائے تاکہ ھم لوگوں کو معلوم ھو سکے کہ اس میں کیا کہا گیا ھے اور کسی بات کو یہ حکومت ماننے کے لئے تیار ھے اور کسی بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ھے -

اس کے بعد فوراً میں اس ملک کے اندر جو جو معاشی ڈھانچہ خراب ھو گیا ھے اس کی طرف توجہ دلانا چاھتا ھوں - آپ جانتے ھیں کہ ھمارے ملک میں قیمتیں روز بروز بڑھ رھی ھیں - مجھے معلوم ھے کہ اخباروں کے ذریعہ سرکار کی طرف سے لوگوں کو دھوکا دینے کی کوشش کی جا رھی ھے اور یہ کہا جا رھا ھے کہ قیمتیں گھٹ رھی ھیں لیکن اصل بات یہ ھے کہ قیمتیں روز بروز بڑھتی جا رھی ھیں- میں روز بازار میں جانے والا شخص ھوں اور روز ھی روزمرہ کے استعمال کی چیزیں خود خریدتا ھوں- مجھے معلوم ھے کہ بازار میں قیمتیں کس قدر بڑھ گئی ھیں - اس لئے میرا کہنا یہ ھے کہ جب تک آپ بلیک مارکیٹئرس کو ھوارڈرس کو اور اسمگلرس کو بند نہیں کرینگے ان پر سخت پابندی نہیں لگائیں گے تب تک یہ قیمتیں کم ھونے والی نہیں ھیں - میں جانتا ھوں کہ آپ لوگوں نے ان کو ڈھیل دی ھوئی ھے ان سے ڈونیشنس وصول کرنے کے لئے آپ

[شری محمد یونس سلیم]

ان کو یہ تھیں دے رہے ہیں جب تک آپ ان کے خلاف سخت قدم نہیں اٹھائیں گے تب تک بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو نہیں پایا جا سکتا ہے- آج سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ بڑھتی ہوئی قیمتوں پر پابندی لگائی جائے-

آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کسانوں کی بھلائی کی بڑی بڑی باتیں کہیں جاتی ہیں میں مانتا ہوں کسانوں کی بھلائی اور بہبودی کی آج سخت ضرورت ہے- لیکن جب تک آپ جتنی کاشت کے لائق زمین ہے اس کو بڑھا نہیں والوں کو نافذ نہیں کریںگے تب تک کسانوں کا بھلا نہیں ہو سکتا- آج ضرورت اس بات کی ہے کہ زمین کی سیلنگ نافذ کی جائے اور جن کے پاس زمین نہیں ہے ان کو زمین دی جائے اور ان کے لئے فرٹلائزرس اریگیشنس پانی- بیج وغیرہ کی چیزوں کا انتظام کیا جائے- تبھی اس دیس کی پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے جب ہم کسانوں کے لئے ان چیزوں کو مہیا کریںگے اور تبھی اس ملک میں جو روز مرہ کے غلے میں گرانی بڑھی جا رہی ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے-

میں دو باتیں اس ملک کی عرض کر خارجہ پالیسی کے متعلق کے ختم کر دوں گا - اٹل بہاری واجپئی صاحب پاکستان تشریف لے گئے اور عین ایسے موقعہ پر تشریف لے گئے جس وقت اس ملک میں چناؤ ہونے جا رہے تھے الیکشن ہونے جا رہے تھے - تاریخیں ایسی مقرر کرکے رکھی گئیں تھیں کہ وہاں سے واپسی کے بعد پاکستان سے دوستی کا ڈھونگ رچا کر ووٹرس کو پھسلایا اور بہلایا جا سکے کہ ہم پاکستان سے دوستی کرنے گئے تھے لیکن -

تو برائے وصل کردن آمدی
نے برائے فصل کردن آمدی

وہاں جو کچھ ہی ہوا وہ بہت افسوس ناک ہے - پاکستان میں جو سوالات اٹھائے گئے اور جس طرح سے پاکستان سے تعلقات کے متعلق...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Mr. Saleem, you must conclude. I am sorry, I will have to call the next speaker.

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: I am about to conclude. Within one minute, I will conclude. Bear with me for one minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Please conclude immediately.

شری محمد یونس سلیم : تو میں

یہ عرض کر رہا تھا کہ خارجہ پالیسی کے متعلق بھی خاص طور پر عربوں کے تعلق سے یہودیوں کے تعلق سے جو ہمارا رویہ ہے اس پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے - خالی تقریر کرنے سے

کچھ نہیں ہوگا - ہم چاہتے ہیں کہ عربوں کی زمین جو زبردستی لی گئی ہے - اس کو واپس کیا جائے یہ کہنا کافی نہیں ہوگا - بلکہ ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ فلسطینیوں کو ہوم لینڈ فراہم کیا جائے اور ان کو وہاں پر پورا سیلف ڈیٹرمینیشن کا اختیار دیا جائے - جو وعدے کئے گئے تھے - جس طرح سے تسلی دینے کی کوشش کی گئی تھی عوام کو وہ سب ڈھونگ معلوم ہو گیا اور میں اس کے اوپر ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Mr. Shrikant Verma.

شری محمد یونس سلیم :

تسکین ہو سکی نہ دل نا شکیب کی
سب ہم پہ کھل گئی تیری باتیں فریب کی -

With these words, I support the amendments.

†[श्री मुहम्मद यूनुस सलीम (आन्ध्र प्रदेश) : जनाब वाइस चेयरमैन साहब—मैं बहुत अफसोस के साथ राष्ट्रपति जी के खतबे के मुत्तालिक यह कहते हुए अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं कि जिस दिन इस पार्लियामेंट के शुरू करने की तारीख रखी गई, जिस दिन राष्ट्रपति जी का खतबा हो रहा था—सेन्ट्रलहाल में, उस दिन रबी अलावल की बारह तारीख थी—बाज जंत्रियों के एतबार से 20 को थी और बाज के एतबार से 21 को थी—यह हम मुसलमानों के पैगम्बर की पैदाइश का दिन है । यह हुकूमत जो इस वक्त बरसरेइक्तदार है इसने वक्तन फवक्तन इंतखाबात से लेकर और इंतखाबात से बाद यह तक दावा किया है कि वो इस मुल्क में सेक्लूरिज्म की बुनियादों को मजबूत करने की कोशिश करेगी—अगर गवर्नमेंट का कलेण्डर उठा कर देखा जाये तो जनाब वाईस चेयरमैन साहब—इस मुल्क में जितने मजहबों के मानने वाले रहते हैं सब के पैगम्बरों और बानियों की तारीख पैदाइश को तातील दी जाती है—मैंने गवर्नमेंट के कैलेण्डर से यह नोट किया कि महावीर जयन्ती की तातील होती है—बुद्ध जयन्ती की तातील होती है—जन्माष्टमी की तातील होती है—महात्मा गांधी के बर्थ डे की तातील होती है—गुरू नानक के बर्थ डे की तातील होती है—क्रिसमिस की तातील होती है लेकिन इस मुल्क में आठ दस करोड़ मुसलमानों के जजबात का ख्याल नहीं किया जाता है और उनके लिए 12 रबी अलावल को तातील देने के लिए गुंजाइश नहीं की जाती है । और यह दावा किया जाता है कि हम इस मुल्क में सेकूलर हुकूमत कायम करना चाहते है और मजहब की बुनियाद पर हम कोई डिस्क्रीमिनेशन नहीं करना चाहते हैं—एक मजहब के मानने वाले और दूसरे मजहब के मानने वाले के दरम्यान क्या मैं आपके तवस्त से जनता हुकूमत से यह सवाल कर सकता हूं कि क्या इसके दिमाग में यह बात नहीं आई कि मुसलमानों के पैगम्बर जिनकी सारी दुनियां में इज्जत और वकार है उनके पैदाइश की तारीख में इस तरह से छुट्टी देनी चाहिए जिस तरह से इस मुल्क में दूसरे मजहब के मानने वालों के महात्माओं और बानियों की पैदायश के वक्त दी जाती है । मुझे अफसोस है और दुःख है कि इस तरफ हुकूमत की तव्वजह नहीं गई । दूसरी बात जो इससे ज्यादा दुःख के साथ जनाब वाइस चेयरमैन साहब मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि फ़खरुद्दीन अली अहमद मरहूम साहब हमारे मुल्क के दूसरे राष्ट्रपति थे जो

†[ ] Devanagri transliteration.

[श्री मुहम्मद यूनुस सलीम]

अक्लियती तबके से ताल्लुक रखते थे---इस मुल्क में इससे पहले दो प्राइम मिनिस्टर और एक प्रजीडेंट (राष्ट्रपति) ऐसे वक्त दुनिया से उठे कि जब वे अपने औहदे पर बरकरार थे। जवाहरलाल जी, लाल बहादुर शास्त्री और डा० जाकिर हुसेन मरहूम---हुकूमत ने अपने मुसारिफ से उनकी समाधि और उनके मकबरे बनाये---डा० जाकिर हुसैन के मकबरे को बनाने में जो जामिया मिलिया के करीब बनाया गया है काफी रकम सर्फ की गई और उस वक्त की हुकुमत ने काफी तवज्जह से उनके मकबरे को बनाया। मगर यह हमारे लिए---इस मुल्क के लिए---इस हुकूमत के लिए बाइसे शर्म है कि इस पार्लियामेंट से 10 कदम के फासले पर उनका मकबरा कसमपुर्सी की हालत में पड़ा हुआ है जहां एक शख्स भी नहीं है, जो वहां कुत्ते जाते हैं उनको जाने से रोकें---सुनाई देता है जब-जब बात करते हैं तो कहा जाता है कि अब तामीर के लिये काम शुरू किया जा रहा है---मगर इस बात को बराबर साल भर से टाला जा रहा है---जहां तक कि इससे पहले 11 फरवरी को इनकी पहली बरसी भी मनाई जा चुकी है---मैं आपके तवस्त से जनता हुकूमत से साफ तौर से यह पूछना चाहता हूं और सवाल करना चाहता हूं कि वो फखरुद्दीन अली अहमद साहब के मकबरे को बनवाने का प्रोग्राम रखते है या नहीं रखते हैं---इस मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं कि अगर हुकूमत इस काम को न करे तो भी इस काम को एक महीने में करने की हिम्मत रखते है लेकिन इस तरह से किसी के साथ सलूक करना, जिसने इस मुल्क की अपनी पूरी उम्र, पूरी जिन्दगी खिदमत की है जो इस मुल्क को आजाद कराने के लिए आजादी का सिपाही रहा है, जिसने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जेलों में रह कर अपनी जिन्दगी गुजारी है इसके साथ यह हुकूमत ऐसा सलूक करती है तो हमें सोचना पड़ेगा कि इस हुकुमत को सेकूलरिज्म की कितनी पासदारी है। मैं इन दो बातों की तरफ आपका खास ध्यान बटाना चाहता हूं।

क़बल इसके कि मैं कोई और बात कहूं कि मुझे अफसोस है कि गुजश्ता दो महीने से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इन्तखाब के नुत्तलक जो फिजा पैदा की गई वह बड़ी अफसोसनाक और बड़ी शर्मनाक थी।

मुल्क की सब से बड़ी हाइऐस्ट ज्यूडीशरी और अदलिया के लिये सियासी बुनियाद पर या किसी एक फैसले के नाफिज करने की बुनियाद पर यह बहस उठाना कि चूंकि हैबियस कारपस की दरख्वास्त के ऊपर जो फैसला किया गया था मौजूदा जो चीफ जस्टिस बने हैं जिन्होंने कल हल्फ ली है वो शरीक थे इसलिए यह जद्दो-जहद शुरू की जाये कि उनको चीफ जस्टिस बनाया जाये या नहीं बनाया जाये---यह बड़ी शर्मनाक और अफसोसनाक बात है इससे मुल्क का वक्कार बढ़ा नहीं है बल्कि इससे सदमा पहुंचा है क्योंकि इसके मानी यह हैं कि आप जजों को मजबूर करना चाहते हैं कि वो फैसले देते वक्त यह सोचें कि हमारे इस फैसले देने के बाद हमारे मुस्तकबिल का क्या हश्र होने वाला है---मैं वाइस चेयरमैन साहब---इससे पहले भी हाऊस में इस बात की तरफ तवज्जह दिला चुका हूं---यह तरीका हमारे मुल्क से हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए कि जो जज सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के हैं आइन्दा उनके लिये कुछ उम्मीदें उनके औहदे से हटने के बाद उनकी दामनगीर हों---जिस वक्त वो इन्साफ करते हों उस वक्त उनको कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए---कोई खौफ नहीं होना चाहिए और न कोई डर होना चाहिए---और न उन पर किसी के रहमोंकर्म की बारिश की तवक्का होनी चाहिए--- बिला फीयर या फेवर के उनको अपना फर्ज अन्जाम देना चाहिए---जिस तरह से कमीशनों के चेयरमैन और मुख्तलिफ कमेटियों के अरकान बना कर

जजों का नवाजा जाता है या जिस तरह से सियासी पार्टियों में टिकट देकर मिनिस्ट्री और दूसरे ओहदे पर सरफराज किया जाता है इससे ज्यूडीशरी का कोई फायदा नहीं होने वाला है और अगर इसको रोका नहीं गया तो इससे मुल्क में करप्शन के दरवाजे खुलने वाले हैं और मैं इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा कर आपको फिर से मतवज्जा करना चाहता हूं ।

जनाब वाईस चेयरमैन साहब—दूसरे साहबान ने भी तवज्जा दिलाई हाऊस की और मैं भी अपनी आवाज उठाना चाहता हूं कि गुजशता एक साल के अन्दर इस मुल्क में जो फरकादाराना फसादात हुए इस मुल्क में जिस तरह से हरिजनों और कमजोर तबकों पर मुजालिम किये गये उसके एदादो-शुमाद की तादाद हजारों तक पहुंच रही है लेकिन प्रेजीडेंट के खतबे में इसका जिक्र तक नहीं है—यह ऐसा खतरा है कि जिस तरफ हुकूमत को मतवजा होना चाहिए । बनारस में जो कुछ हुआ, लखनऊ में जो कुछ हुआ, कानपुर में जो कुछ हुआ, मेरठ और बिहार में जो कुछ हुआ हिन्दुस्तान के मुखतलिफ हिस्सों में जिस तरह से गरीबों का खून किया गया जिस तरह से पी०ए०सी० और पुलिस ने उनको जुल्म से बचाने के बजाये उनके घरों में जाकर उनको लूटा—उनकी औरतों को बेइज्जत किया—यह इंतहाई शर्म की बात है और मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि सारे जहां के लोग झूठे हैं और हुकूमत के लोग सच्चे हैं—अहमदाबाद के लोग झूठ बोलते हैं । भिवन्डी के लोग झूठ बोलते है, मउनाथ भंजन और बनारस के लोग झूठ बोलते हैं, कानपुर के लोग झूठ बोलते हैं, मेरठ के लोग झूठ बोलते हैं सिर्फ सच बोलते हैं सरकार के औहदादार—इसलिए इस पर कड़ी तवज्जों की जरूरत है और ये जो कमीशन्स मुकर्रर किये गये हैं जो पुलिस कमीशन्स और अकलीतों की कमीशन मुकर्रर किया गया है ये तमाशा है—हम इस जाल में फंसने वाले नहीं हैं । अकलीती कमीशन के बारे में बड़ी और नीची ऊंची बातों का जिक्र किया गया मगर ये कमीशन क्या है इसके पीछे कानूनी मुद्दा क्या है कानूनी सेनटिटी क्या है । It is not statutory Commission. It has not been constituted under any law of the land. It is just like any other ordinary Committee constituted by the Government. Therefore, it is not a statutory Commission.

जनाब वाईस चेयरमैन साहब—मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अकलीती कमीशन में बड़े-बड़े वायदे किये गये हैं—चुनाव को जीतने के लिए वोटरों को फुसलाने के लिए अकलीतों को बेवकूफ बनाने के लिये बड़े-बड़े वायदे किये गये और कहा गया कि हम कमीशन कायम करेंगे—अकलीती कमीशन में वो लोग लिये गये हैं जिनके मुत्तलक मैं कुछ नहीं कहना चाहता—मुझे सिर्फ एक बात अर्ज करना है कि जो लोग लिये गये हैं उन पर अकलीतों का कोई भरोसा नहीं लेकिन अगर भरोसा होता भी ये क्या तमाशा है जब तक कि इसकी सिफारशात को कोई कानूनी सेनटिटी न हो तब तक अकलीती कमीशन इन मसलों पर गौर करने के बाद अपनी जो राय देता है—इसको मानना या न मानना मरकजी और दूसरी हकूमतों के लिये लाजिमी न हो ये ढोंग है, ये खिलौने दिये जाते हैं—

तमन्नाओं में उलझाया गया हूं
खिलौने दे बहलाया गया हूं

ये खिलौने देने से काम नहीं चलेगा एक बात । दूसरी बात यह है कि इस अकलीती कमीशन के साथ लिगविस्टिक मायनोरिटीज को जोड़ कर क्यों पैबन्द लगाया गया—एक लैंगवेज कमीशन आपके यहां मौजूद है इसके टर्मस आफ रेफरेन्स में तबदीली करके अगर लैंगवेस्टिक मायनोरिटीज के साथ कोई बेइन्साफी हो रही है तो इसके परव्यू में

[श्री मुहम्मद यूनुस सलीम]

इसको ले आते । इस अकलीती कमीशन के साथ जो आपने लैंगविस्टिक मायनोरिटीज का जोड़ लगाया इसके मायने ये हैं कि इस मुल्क में रहने वाला कोई शख्स ऐसा नहीं है जो मायनोरिटीज में न हो । आज लैंगविस्टिक मायनोरिटी के मायने ये हैं कि चेयरमैन साहब आप यहां तशरीफ फर्मा रहे हैं तो मायनोरिटीज में हैं लेकिन अपनी स्टेट में जायेंगे तो मेजोरिटी में हो जायेंगे, हमारे सेक्रेटरी जनरल भालेराव साहब बैठे हैं ये महाराष्ट्र में जायें तो मेजोरिटी में हो जायेंगे लेकिन हैदराबाद में जायेंगे तो मायनोरिटी में हो जायेंगे---इसके मायने ये हैं कि हमारे मुल्क के लोग मायनोरिटी बन जायेंगे और इस कमीशन के सामने अपने मसले पेश करेंगे । It is a practical joke with the minorities of the country which will not be tolerated hereafter.

SHRI P. RAMAMURTI: Will you please allow me to interrupt you for a minute? In Tamil Nadu, for example, in the border areas a lot of Telgu-speaking people are living. Similarly, in Andhra Pradesh, in the border areas a lot of Tamil-speaking people are living. Now, if the Andhra Pradesh Government does not make provision for these Tamil-speaking people being taught in their own language, or if the Tamil Nadu Government does not make provision for the Telgu-speaking people in that area to be taught in their known language, then has not something got to be done? When we are talking of minorities, it inevitably happens that people speaking different languages living in a linguistic State where the majority of the people speak a different language will naturally form a minority. What can you do with that?

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : मैं गुजारिश यह करूंगा कि मेरे दोस्त रामामूर्ति साहब ने मेरी बात को समझा नहीं । मैं यह कहता हूं कि इस मुल्क में लिंगविस्टिक मायनोरिटी के साथ भी बेइन्साफी होती है लेकिन इसको दूर करने के लिए लैंगवेज कमीशन के टर्म आफ रेफरेंस में तब्दीली करके इसके परव्यू में लाना चाहिए इसलिए कि इस लैंगवेज कमीशन के सामने सारे देश की लिंगविस्टिक प्राबलम्स की तस्वीर है ।(*Time bell rings*)—जनाब—मैंने यह देखा है कि आपने रामामूर्ति साहब को 25 मिनट दिये हैं---कम से कम मेरे साथ आप डिस्क्रीमीनेट न कीजिये । तो मैं यह गुजारिश कर रहा था कि ये कमीशन बहुत गल्त तरीके से बनाया गया है इसके पीछे स्टेचुटरी सेंकटिटी नहीं है । पहले कानून पार्लियामेंट में बनाना चाहिए ताकि इसकी सिफारिशात मेनडेटरी हों और मरकजी हुकूमत को मानना जरूरी हो । नहीं तो ये कागज फेंक दिये जायेंगे जैसे यू० पी० गवर्नमेंट ने एक कमीशन मुकर्रर किया था इसकी सिफारिशात कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई हैं---इसलिये ये मैं और भी कहना चाहता हूं कि अकलीत के मसायल हल होने वाले नहीं हैं तो इस पर दोबारा गौर होना चाहिए और बैगर मेनडेटरी प्राविजनों के मायनोरिटी कमीशन बेकार हैं । Nobody cared for those recommendations.

दूसरा सवाल इस मुल्क में अकलीतों के बेरोजगारी का है---मैं इस बात से वाकिफ हूं कि कंस्टीट्यूशन में अकलीतों को रोजगार देने के लिये कोई प्राविजन नहीं है लेकिन मैंने यह सवाल किया था जनाब होम मिनिस्टर साहब से कंसलटेटिव कमेटी में कि आप ये कहते हैं कि हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मुकर्रर किये हैं---स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मुकर्रर किये हैं लेकिन मैं आपसे जवाब चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर में रिक्रूटमेंट के लिये आपने कौन से कमीशन मुकर्रर किये हैं---हजारों औहदेदारों में आपको दो आदमी भी नहीं मिलेंगे । स्कूलों के दरवाजे, कालेजों के दरवाजे, लाइसेंस के दरवाजे, रोजी रोजगार के दरवाजे अकलीतों के ऊपर बन्द किये जा रहे हैं । आप दिल्ली

के पूरे शहर में चक्कर लगाइये जिस चौराहे पर जायेंगे आप पायेंगे कि छोटी-छोटी दुकानें बनी हुई हैं—कोई बर्फ बेच रहा है—कोई शरबत बेच रहा है,—कोई चाय बेच रहा है तो कोई पान बेच रहा है—इन हजारों दुकानों में से दो दुकानें भी ऐसी नहीं मिलेंगी जिन्हें अकलीती तबके के लोगों को एलाट किया गया हो—सिफारिशों—खुशामदों—अर्जियों और दरख्वास्तों के बावजूद—जनाबआली ये क्या मेक्यूलरिज्म है—ये कैसा कंस्टीटयूशन है—ये कैसी हुकूमत है—किस तरह से चलेगा ये मुल्क—मैं यह अर्ज करता हूं कि इस मुल्क की अकलीतें हमारा जो नेशनल चेन है उसकी एक लिंक है—

And the test of the strength of a Chain lies in weakest link.

अगर अकलीतों में कसूर है, उसमें कोई कमजोरी है या कुछ जहन हैं, इनमें कोई इंटेलीजेंस नहीं है जो इनके लिये खासतौर से इन्तजाम किया जाना चाहिए ताकि आठ करोड़ इन्सान इस देश के बेकार और निकम्मे होकर न रहें। आठ करोड़ मुसलमान इस देश के निकम्मे हैं, हमारी पूरी कौम निकम्मी है ये हम नहीं कह सकते कि हमारे बदन में नासूर हो और हम ये कहें कि बदन सेहतमंद है—पूरी बोडी को रोग लगा हुआ है—इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है—इसके मुत्तलक प्रेसीडेंट एड्रेस में एक लफ्ज भी नहीं कहा गया।

वाईस चेयरमैन साहब—लिंगविस्टिक माइनोरिटीज के साथ बेइन्साफी हो रही है—मैं उर्दू का रोना कहां तक रोऊ—कई मर्तबा इस हाऊस में उर्दू के मुत्तलक बात कही जा चुकी है लेकिन बजाय इसके उर्दू के साथ इन्साफ किया जाये—उर्दू बोलने वालों को तसल्ली दी जाये और उर्दू को इस मुल्क में ऐसा दर्जा दिया जाये जो एक शानदार जबान को दिया जाना चाहिए बल्कि होम मिनिस्टर साहब ने नई तारीख इजाद कर दी है—नई रिसर्च कर रहे हैं और उनके ऊपर इन्कशाफ होता है कि इस मुल्क में उर्दू जबान तुर्क और मुगल ले कर आये हैं। तुर्क तारीखदानों का आलमाना अन्दाज है गुफ्तगू का—हमको यह नहीं मालूम कहां से मुगल आये कहां से तुर्क आये और कौनसी जबान बोलते थे—वाईस चेयरमैन साहब—जिस वक्त इस मुल्क में मुगल और तुर्क आये हैं और इससे पहले दखिन के अन्दर दखिन जबान तरक्की कर रही थी इसके अन्दर नशर में, नज्म में, गजल मशनवी और मरशिया ने जाने कितनी तादाद में लिखी जा चुकी थीं—हमारे चौधरी चरण सिंह फर्माते हैं ये तुर्कों और मुगलों की भाषा है—बड़े अफसोस की बात है काश ये बात चौधरी चरण सिंह साहब की नावाकफियत और नादानी पर ही खत्म हो जाती—हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने बहुत बड़े तदब्बुर का सबूत दिया है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Now you please finish.

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: Sir, I have taken only 15 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): I am sorry I have been watching the time.

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: I am going to conclude

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): You must conclude now.

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: But 1 may be permitted to make my submission. I am not wasting the time of the Chair or of the House.

वजीरेआजम श्री मोरारजी देसाई जिस वक्त उर्दू के घर का इफ्तताह कर रहे थे—श्री आनन्द नारायण मुल्ला जो अंजमन तरक्की उर्दू के सदर हैं उनकी तकरीर सुन कर इन्होंने गुस्से और नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने यह कहा था कि उर्दू जबान

fShri Mohammad Yunus Saleem]

वह जबान है जिसने इस मुल्क का बटवारा किया उस वक्त हमारी गर्दन शर्म से झुक गई—क्योंकि प्राईम मिनिस्टर साहब ने गैर-मुल्कियों के सामने गैर जिम्मादारान बात कर रहे थ—हम गैर मुल्की डेलीगेटों के सामने आंखें नहीं मिला सके—मैं यह बात कह सकता हूं कि इस मुल्क का बंटवारा उर्दू ने नहीं करवाया इस मुल्क का बटवारा मुसलमानों ने नहीं कराया, इस मुल्क का बटवारा दूसरे हालात ने करवाया—अगर कोई यह कहे कि उर्दू जबान ने बटवारा कराने में कोई पार्ट अदा किया है तो यह उसकी तारीख से नावाकफियत की बात है—हम इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हैं—उर्दू इस मुल्क की जबान है—इस मुल्क में पैदा हुई है—इस मुल्क के रहने वाले इस जबान को बोलते हैं—इस जबान से प्यार करते हैं और इस जबान में इतना शानदार लिटरेचर है कि जो दुनियां की बेहतरीन जबानों के मुकाबले में पेश किया जा सकता है—इसलिये अगर इस जबान के साथ बेइन्साफी करेंगे तो इसके मानी ये होंगे कि यह पराये शगून में नाक कटाने के बराबर होगा—इसलिये आज सख्त जरूरत इस बात की है कि उर्दू के मसले पर तवज्जो दी जाये—मैं आज इस ऐवान के सामने वार्न कर देना चाहता हूं अगर थोड़े दिन और उर्दू के साथ इस तरह से बेइन्साफी की गई तो उर्दू बोलने वाले वही तरीका अख्तयार करेंगे जिस तरीके को ये हुकूमत पहचानती है और वही जबान बोलेंगे जिस जबान को ये हुकूमत समझती है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Mr. Saleem. you •must conclude please. Within a minute you must conclude please,

SHRT MOHAMMAD YUNUS SALEEM: "Why are you so unkind to me*"

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): I am not unkind. You have taken more than 25 minuted.

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: I have taken only 17 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): I am sorry I am watching the time. I watch it better than you do.

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: Mr. Ramamurti concluded his speech at 2.25. Then another gentlemen took 25 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M TRIVEDI): May I explain to you that if every speaker is going to. take 25 minutes...

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: There should be no discrimination between one speaker and another speaker. Every speaker belongs to this House. He should be given pro-, per time and proper opportunity. This is not fair. This is very unfair, Sir, I strongly protest against the discrimination, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI' H. M. TRIVEDI): There is no discrimination at all. I would like you to appreciate that you have had more than your time. I would only like, you to conclude quickly.

SHRI MOHAMMAD YUNUS" SALEEM: I was not told at the outset-how much time would be allotted to me. I was under the impression that the Chair would allot at least 25 minu_ tes to every speaker. I had planned to conclude within 25 minutes. I have taken only 17 minutes so far.

दूसरी बात कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूं—कल ही एक मुकरर ने ये सवाल उठाया था कि इन्दिरा गांधी की हुकूमत में उर्दू के मसले पर गौर करने के लिये गुजराल कमेटी मुकरर की गई थी—

इस कमेटी ने इस मुल्क का दौरा करके अपनी रिपोर्ट दी—इसमें बहुत से मुल्क के रहने वाले अखबार नवीस—अदीब—शायर और उर्दू के जानने वाले लोग शामिल थे लेकिन आज ये रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री के शेल्फ में पड़ी हुई है—मैं चाहूंगा कि इस रिपोर्ट को इस ऐवान के सामने लाया जाये ताकि हम लोगों को मालूम हो सके कि इसमें क्या कहा गया है और किस बात को ये हुकूमत मानने के लिये तैयार है और किस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद फौरन मैं इस मुल्क के अन्दर जो मआशी ढांचा खराब हो गया है उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं—आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में कीमतें रोज-बरोज बढ़ रही हैं—मुझे मालूम है कि अखबारों के जरिए सरकार की तरफ से लोगों को धोखा देने की कोशिश की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि कीमतें घट रही हैं लेकिन असल बात यह है कि कीमतें रोज-बरोज बढ़ती जा रही हैं—मैं रोज बाजार में जाने वाला शख्स हूं और रोज ही रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें खुद खरीदता हूं—मुझे मालूम है कि बाजार में कीमतें किस कदर बढ़ गई हैं—इसलिये मेरा कहना यह है कि जब तक आप ब्लैकमार्कीटियर को, होर्डर्स को, और स्मगलर्स को बन्द नहीं करेंगे उन पर सख्त पाबंदी नहीं लगायेंगे—तब तक ये कीमतें कम होने वाली नहीं हैं—मैं जानता हूं कि आप लोगों ने इनको ढील दी हुई है—इनसे डोनेशन्स वसूल करने के लिए आप इनको यह ढील दे रहे हैं—जब तक आप इनके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठायेंगे तब तक बढ़ती हुई कीमतों पर काबू नहीं पाया जा सकता है—आज सख्त जरूरत इस बात की है कि बढ़ती हुई कीमतों पर पाबंदी लगाई जाये ।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज किसानों की भलाई की बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं—मैं मानता हूं किसानों की भलाई और बहबूदी की आज सख्त जरूरत है लेकिन जब तक आप जितनी काश्त के लायक जमीन है उसको बिना जमीन वालों को नाफिज नहीं करेंगे तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता—आज जरूरत इस बात की है कि जमीन की सीलिंग नाफिज की जाये और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दी जाये और इनके लिए फर्टिलाइजर्स, इरीगेशनल पानी, बीज वगैरह की चीजों का इन्तजाम किया जाये। तभी इस देश की पैदावार में इजाफा हो सकता है। जब हम किसानों के लिए इन चीजों को मुहैय्या करेंगे और तभी इस मुल्क में जो रोजमर्रा के गल्ले में गिरानी बढ़ती जा रही है उस पर काबू पाया जा सकता है। मैं दो बातें इस मुल्क की खारजा पालिसी के मुत्तलक अर्ज करके खत्म कर दूंगा—अटल बिहारी वाजपेयी साहब पाकिस्तान तशरीफ ले गये और ऐन ऐसे मौके पर तशरीफ ले गये जिस वक्त इस मुल्क में चुनाव होने जा रहे थे, इलेक्शन होने जा रहे थे—तारीखें ऐसी मुकरर करके रखी गईं कि वहां से वापसी के बाद पाकिस्तान से दोस्ती का ढोंग रचा कर वोटर्स को फुसलाया और बहलाया जा सके कि हम पाकिस्तान से दोस्ती करने गये थे लेकिन—तो बराये वस्ल करदन आमदी—नये बराये फसल करदन आमदी। वहां जो कुछ भी हुआ वह बहुत अफसोसनाक है—पाकिस्तान में जो स्वालात उठाये गये और जिस तरह से पाकिस्तान से तालुकात के मुत्तलिक—

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Mr. Saleem, you must conclude. I am sorry. I will have to call the next speaker.

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: I am about to conclude. Within one minute, I will conclude. Bear with me for one minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Please conclude immediately.

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि खारजा पालिसी के मुत्तालिक भी खास तौर पर अरबों के तालुक से, यहूदियों के तालुक से जो हमारा रवैया है इस पर नजर डालने की जरूरत है—खाली तकरीर करने से कुछ नहीं होगा—हम चाहते हैं कि अरबों की जमीन जो जबर्दस्ती ली गई है इसको वापस किया जाये—ये कहना काफी नहीं होगा—बल्कि इनको यह कहना पड़ेगा कि फिलस्तीनियों को होम लेण्ड फरहाम किया जाये और उनको वहां पर पूरा सेल्फ डिटरमीनेशन का अख्तयार दिया जाये। जो वायदे किये गये थे, जिस तरह से तसल्ली देने की कोशिश की गई थी अवाम को—वो सब ढोंग मालूम हो गया और मैं इसके ऊपर एक शेर अर्ज करना चाहता हूं—

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Mr. Shrikant Verma.

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम :

तस्कीन ही सको न दिले नाशकीब की
सब हम पे खुल गई तेरी बातें फरेब की।

With these words I support the amendments.

श्री भीष्म नारायण सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि इस विषय में काफी सदस्यों की दिलचस्पी है और वे इस पर बोलना चाहते हैं। अतः सदन कम से कम 6 बजे तक चले।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDT); I am in the hands of the House. I would like to know the facts. There are not less than 24 speakers still left in this debate. The time available for the debate is today and Monday. After that the debate has to conclude. Now, if everybody is going to claim 25 minutes—I had a reckoning done—then at least some speakers will be left out. It is up to the House to decide whether they would like each speaker to take 25 minutes or 15 minutes. I am trying to allocate roughly 15 minutes to each speaker. Is that fair enough?

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM; It will be discrimination if you allot 15 minutes now when you have already aJlowed 25 minutes to two speakers.

{Interruptions)

श्री भीष्म नारायण सिंह : आप इसके लिये समय तय कर लीजिये। यदि समय बढ़ा दिया जाय तो अधिक अच्छा होगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H M. TRIVEDI): Extending the time of the debte is not in my hands. It is up to the Business Advisory Committee to decide. I am going by the total time available. Taking the number of speakers from all parties together, I am suggesting to the House that we cannot allocate more than 15 minutes, and would like that to be agreed to by the House.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI (Uftar Pradesh): If the House agrees, we can sit till 6 p.m. today. We can sit for one hour more.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): May I put it to you that even if we extend the time till 6 p.m. today... *(Interruptions)* Please listen. I am on my feet.

SHRI K. K. MADHAVAN (Kerala): We are also on our legs.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H M. TRIVEDI): When the Chair is on its legs, you have no right to be on your legs. Even if you extend the time till 6 pm. today, if you take the time available and the number of speakers, I may put it to you that more than 15 minutes to each speaker would not be possible. I, therefore, suggest that the House may agree to this suggestion.

श्री सीताराम केसरी (बिहार) : कन्डीशन लगा दीजिये।

شری محمد یونس سلیم : مگر
بولنے والے کو جملہ نہیں کرنے دیا
جائے گا تو پھر کیسے کام چلے گا -

†[**श्री मुहम्मद यूनुस सलीम** : मगर बोलने वाले को जुमला पूरा नहीं करने दिया जायेगा तो फिर कैसे काम चलेगा।]

SHRI K. K. MADHAVAN: I want t_0 make a positive suggestion if you will allow me. If you specify so many minutes for each speaker, then are you prepared to stick to that time-limit? Or, are you willing to be elastic in favour of one and ask another to be shor. ter? That is what I wanted to get clear.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI); I $_a$m afraid speakers have been taking undue advantage of the leniency of the Chair.

SHRI K. K. MADHAVAN: No, no leniency.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): All right. Mr. Shri-kant Verma.

SHRI SHRIKANT VERMA (Madhya Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I will speak only for fourteen minutes.

उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष इन्हीं दिनों जनता सरकार सत्ता में आई थी और कुछ भोले-भाले लोगों ने खुशी के दीये जलाये थे। अक्सर ऐसे दीये पांच साल जलते हैं। लेकिन अभी साल भर भी नहीं हुआ कि उम्मीदों के ये दीये बुझ चले। इसमें दोष लोगों का नहीं है बल्कि उन लोगों का है जिन्होंने कि लोगों में बड़ी उम्मीदें पैदा की थीं और बड़े दावे किये थे। मुझे ख्रुश्चेव की बात याद आती है उसने कहा था :

"A successful politician is he who promises to construct a bridge where there is not even a **river.**"

t[ ]Devanagri translation.

जनता पार्टी ने कुछ इसी तरह के वायदे किये। जहां नदी नहीं थी वहां भी उसने पुल खड़े करने के वायदे किये और सारे पुल ढह गये। सारा देश बड़े भारी मलबे में परिणित हो गया है और उसकी गंध चारों ओर महसूस हो रही है। सबसे पहले तो यह कि यह सरकार आजादी का नारा ले कर सत्ता में आई। आजादी से उसका अर्थ था नागरिकों की आजादी, ग्रामीणों की आजादी नहीं। सिटीजन, जब वह सिटीजन कहती है तो उसका अर्थ सचमुच ही सिटीजन होता है—सिटीज में रहने वाले लोग। लेकिन आइये हम देखें कि क्या उसने आजादी की रक्षा की? प्रेस पहली चीज, दूसरी चीज दंड व्यवस्था और तीसरी चीज न्यायालयों की व्यवस्था। उसका दावा था कि तीनों चीजों का दमन इमरजेंसी के दौरान हुआ है। अब क्या हो रहा है? प्रेस की आजादी को लीजिये। सूचना मंत्रालय को शायद इस बात की सूचना न हो कि प्रेस वाकई आजाद है या नहीं है। लेकिन इसकी जानकारी साहू जैन को है, रामनाथ गोयनका को है, वाणिज्य मंत्रालय को है, उद्योग मंत्रालय को है और कम्पनी अफेयर्स को है। अखबारों की आजादी का नियंत्रण सूचना मंत्रालय नहीं करता है। अखबारों की आजादी का नियंत्रण ये मंत्रालय करते है। अखबारों की आजादी का फैसला पत्रकार नहीं करते हैं बल्कि पत्रों के मालिक करते हैं।

सरकार के बीच और पत्रों के मालिकों के बीच एक अलिखित समझौता है और उस अलिखित समझौते के बल पर ही यह षड्यंत्र चल रहा है। मैं दूर नहीं जाना चाहता। अभी चार रोज पहले का मामला लेता हूं। बम्बई से टाइम्स आफ इंडिया एक पत्रिका निकालता है 'सारिका' बहुत बड़ी पत्रिका नहीं है। उसके सम्पादक एक मशहूर व्यक्ति हैं, कमलेश्वर, एक कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी पत्रिका में बहुत से सम्पादकीय आर० एस० एस० के खिलाफ लिखे। पहले तो उन्हें

TShri Shrikant Verma]

हर तरह की धमकियां दी गईं, उनके पास तरह-तरह की धमकियों के पत्र आये और उसके बाद मालिकों ने यह कहा कि अब उन्हें हटाया जायेगा। हटाने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला। पत्रिका जो बम्बई से निकलती थी उसको दिल्ली भेज दिया और समूचे स्टाफ को और सम्पादक को कहा कि अब वे दिल्ली चले जायें।

इस टेंशन को बर्दाश्त करने में असमर्थ सम्पादक को हार्ट अटेक हुआ और वह अभी भी अस्पताल में है। यह है अखबारों की आजादी। उपसभाध्यक्ष महोदय, अखबारों को आजादी जरूर मिली है एक अर्थ में और वह आजादी यह है कि इंदिरा गांधी को जितनी चाहें उतनी गालियां दी जायें। उपसभाध्यक्ष महोदय, एक कहावत है "तुलसी अपने राम को रीझि भजी कें खीज" यही अखबार जो इमरजेंसी के दौरान हर पृष्ठ पर श्रीमती गांधी के चित्र छाप रहे थे उनकी प्रशंसा के पुल बांध रहे थे, आज यही अखबार श्रीमती गांधी को गालियां देते नहीं थकते। क्योंकि तब भी वे भक्त थे और आज भी भक्त हैं। उस समय वे श्रीमती गांधी के भक्त थे परन्तु आज उनके स्वामी और हैं। वे अपने हित को जानते हैं। अगर यही आजादी है तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। उप-सभाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने स्वतंत्रता का एहसास नहीं कराया है; लेकिन परतंत्रता का भय जरूर पैदा किया है। यह भय पैदा किया है कि श्रीमती गांधी वापस आ सकती हैं। क्योंकि श्रीमती गांधी के वापस आने की आवाज सुनाई पड़ रही है। मुझे अफसोस है कि अब तक ऐसा कोई रबर नहीं निकाला गया है जिससे कि इतिहास को मिटाया जा सके। अगर ऐसा रबर होता तो शायद इतिहास को नष्ट कर दिया जाता। लेकिन अफसोस है कि अब तक ऐसा रबर नहीं निकाला गया है। चारों ओर आजादी का शोर है। टेनीसन की एक कविता है:

Water, water everywhere; But not a drop to drink.

यह कैसी आजादी है कि इस आजादी का जल खारा है। इसे हम चख नहीं सकते है लेकिन देख सकते है। इस आजादी का एक आकार जरूर है और इसके लिए मैं जनता पार्टी की बुराई नहीं करूंगा बल्कि कहूंगा कि इमरजेंसी के दौरान उसका आकार नष्ट हो गया था। अर्थ तो नष्ट हो ही गया था। जनता पार्टी ने उसको आकार दिया। इसलिए हम जनता पार्टी के इस मामले में कृतज्ञ है। लेकिन आकार देने के साथ-साथ उसने आजादी के अर्थ को विकृत कर दिया, तोड़ दिया। अर्थ यह हो गया कि चोर को चोरी करने की इजाजत है, डाकू को डकैती डालने की इजाजत है लेकिन पुलिस को कोई कार्यवाही करने की इजाजत नहीं है। आज प्रशासन का मनोबल गिरा हुआ है क्योंकि कोई आफिसर बोहरा नहीं बनना चाहता है, क्योंकि आफिसर स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। वह जानता है कि स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में क्या हो सकता है, अगली सरकार आ सकती है कमीशन बैठ सकता है। अभी तो दूसरी आजादी आयी है, हो सकता है तीसरी आजादी आये। आपने तमाम अफसरों का मनोबल गिरा दिया है। कोई अफसर इस लायक नहीं रह गया है कि वह कोई स्वतंत्र निर्णय ले। आप जुडीशियरी की बात करते है, श्रीमती सुमित्रा कुलकर्णी ने आज सवेरे न्यायालयों की स्वतंत्रता की बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई लेकिन जब श्रीमती गांधी के पक्ष में दिल्ली के एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया तब किसने उसकी तीखी आलोचना की? इस देश के सर्वोच्च राजनेता प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने, गृह मंत्री चरण सिंह जी ने की। आप सोचिए इस देश में न जाने कितने हजारों मजिस्ट्रेट हैं लेकिन प्रधान मंत्री एक है, गृह मंत्री एक है। आप सोचिए कि उनका मनोबल कितना गिरा होगा। आज हमारे न्यायालय आजाद हैं तो

इसका श्रेय जनता पार्टी को नहीं है, बल्कि इस देश की जनता को है; इस देश के प्रजातंत्र को है जिसके अंदर एक इन बिल्ट ढांचा पैदा हो गया है, एक भीतरी ढांचा पैदा हो गया है। इसी की वजह से उसे कोई नष्ट नहीं कर पा रहा है। इसका श्रेय श्री मोरारजी देसाई को नहीं है, चौधरी चरण सिंह को नहीं है।

अब चुनाव की बात को लीजिए। कौन सी ऐसी चीज चुनाव में नहीं हो रही है जो कि पिछले चुनावों में न हुई हो। हर तरह के हथकंडे आजमाये जा रहे है। वही जो पहले होता था आज भी हो रहा हैं। फिर जनता पार्टी कैसे दावा करती है कि उसने कई अर्थों में पिछले जो निर्णय थे उससे हटकर निर्णय लिये या अधिक स्वच्छ तंत्र प्रदान किया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, कुछ भी नहीं हो रहा है; बल्कि जो पहले हुआ था केवल उसे नष्ट किया जा रहा है। यह इसलिए नष्ट किया जा रहा है क्योंकि जनता पार्टी के लोगों को 30 साल से विरोध में बैठने की आदत हो गयी है। वे निर्माण करना नहीं जानते हैं। वे तो केवल एक चीज जानते हैं कि केवल विरोध ही सत्य होता है, चाहे जवाहरलालजी का विरोध हो, चाहे महात्मा गांधी का विरोध हो, चाहे इन्दिरा गांधी का विरोध हो। खैर, मैं श्रीमती गांधी का नाम तो नहीं लूंगा यहां पर; क्योंकि श्रीमती गांधी का विरोध करना तो एक रिवाज हो गया है। उस विरोध में कुछ अर्थ भी होता है, लेकिन जवाहरलालजी का विरोध करना, इसका क्या अर्थ होता है? जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी के साथ जुड़ी हुई जितनी स्मृतियां हैं उन्हें नष्ट करने का क्या अर्थ है? सी०एस०आइ०आर० को नष्ट करने का क्या अर्थ है? प्लानिंग कमीशन को नष्ट करने का क्या अर्थ है? इसका केवल एक अर्थ है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो एक वैज्ञानिक दृष्टि दी उसको नष्ट कर दिया जाए... (*Interruptions*) नष्ट नहीं की नष्ट करने की कोशिश की, अगर आप जैसे घटकों से उसका वश चले तो यह कभी का नष्ट हो जाये। यह तो—

Thank God. Mr. Morarji Desai is the Prime Minister; he is at least modern.

तो उपसभाध्यक्ष महोदय, ये सारी संस्थाएं, सारी परंपराएं हैं जो इतिहास के अंतरद्वंद से पैदा हुई। उनको नष्ट करने की कोशिश की जा रही है।

कल कहा गया कि जनता पार्टी दिशा-हीन है। मैं नहीं मानता हूं कि दिशा-हीन है। उसकी एक खास दिशा है वह दिशा वह है जो चौ० चरण सिंह की है, जो आर०एस० एस० की है। बाकी लोग इन्डफेक्टिव्ह हैं, बाकी लोग केवल गद्दियों में बैठे रहना चाहते हैं। चौधरी चरण सिंह और आर० एस० एस० के पास एक दृष्टि है, एक दिशा है कि एक आधुनिक समाज को एक सामंती समाज में परिवर्तित कर दिया जाये, और उस सामंती समाज की कल्पना अपनी अर्थ-नीति में चौ० चरण सिंह ने की है। मैं अपनी ओर से उनकी अर्थ-नीति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, केवल एक उद्धरण पढ़ना चाहता हूं। यह "सडे" नाम की पत्रिका कलकत्ता से निकलती है, इसके लेखक हैं श्री अलोक मित्र, जो प्रख्यात अर्थ-शास्त्री हैं और पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी सरकार के वित्त मंत्री हैं और इस तरह वे इस सरकार के बहुत विरोधी भी नहीं हैं, वे इस सरकार के मित्र हैं, और वे क्या कहते हैं चौ० चरण सिंह की अर्थ-नीति पर :

"Reading this book, no body can accuse Choudry Charan Singh of not knowing his class interests, His perception of political economy, given his class position is faultily faultless he is against heavy industry because the latter, he argues, absorbs a disproportionately large amount of the State's resources. The real reason must be his cerebral dislike of the public sector and his fear of pressures developing to raise resources for the growth of heavy industry by taxing agriculture. That without heavy industry there will hardly be any adequate base

[श्री श्रीकान्त वर्मा]

for the output of power and fertilzers is a point which Mr. Charan Singh would let his adversaries raise ; he does not have to raise it himself."

महोदय, इस एक उद्धरण से यह साफ हो जाता है कि चौधरी चरण सिंह किनके प्रतिनिधि हैं। कल श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय ने बहुत सही बात कही कि उनकी अर्थ नीति के पीछे धनी किसानों का स्वार्थ है। यह जो देहाती अंचलों में तनाव नजर आता है, जो ये हरिजन मारे जाते हैं, जलाये जाते हैं, इसको यह नहीं मानिये कि ये छुटपुट घटनाएं हैं। यह एक संगठित हिंसा है। मैं इसको जाति-द्वेष भी नहीं कहूंगा। यह वर्ग युद्ध की शुरुवात है। यह धनी किसान और गरीब किसानों के बीच युद्ध का आरम्भ है। इमरजेंसी के दौरान बहुत से बुरे कार्य हुए लेकिन कुछ अच्छाइयां भी हुई। 20–सूत्री कार्यक्रमों के अंतर्गत गरीब किसानों को जमीनें दी गईं। वह धनी किसानों को बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर उन्हें नहीं भी दी गई तो कम से कम हरिजनों के मन में यह उम्मीद पैदा हुई कि जमीन मिलेगी और यह उम्मीद का मिलना ही काफी था। इससे उन्हें आत्मविश्वास पैदा हुआ। मैं नहीं मानता सबको जमीनें मिल गईं। लेकिन उनमें आत्मविश्वास पैदा हो गया कि हमें जमीन मिल सकती है। एक आत्म-सजगता पैदा हुई और इस आत्म-सजगता को पैदा करना ही बहुत ही बड़ी बात हुई। मैं श्रीमती गांधी की बहुत सी विफलताओं को स्वीकार करता हूं। लेकिन उनकी एक कामयाबी बहुत बड़ी होगी जो हमेशा याद की जायेगी और कोई भी इतिहास को मिटाने वाला रबर या कोई भी पार्टी उसको नहीं मिटा सकेगी और वह यह कि उन्होंने गरीबों के अंदर सजगता और आत्म-विश्वास पैदा किया और उस आत्म-विश्वास को आज चौ० चरण सिंह अपनी प्रतिहिंसा में, अपनी घृणा में और अपने द्वेष में नष्ट करना चाहते हैं। हो सकता है उनका कोई उद्देश्य न हो, उनका उद्देश्य केवल यह हो कि इन्दिरा गांधी और नेहरू खानदान ने जो कुछ किया उसको नष्ट कर दिया जाये। लेकिन वह भूले जा रहे हैं कि इन्दिरा गांधी और नेहरू खानदान की स्मृतियों को नष्ट करने के प्रयत्न में वह पूरे देश को नष्ट कर देंगे। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं ने कहा था कि मैं केवल 14 मिनट बोलूंगा और मैं 14 मिनट में ही खत्म कर रहा हूं केवल यह कहते हुए कि राजनीति व्यक्ति केन्द्रित नहीं होनी चाहिए, वह समाज केन्द्रित होनी चाहिए और चार या छः व्यक्तियों को सजा देने की कोशिश में कहीं आप अपने विरुद्ध और देश के विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र न कर बैठें कि समूचा देश नष्ट हो जाये और इतिहास आप को कभी क्षमा न करे। मुझे पूरा विश्वास है कि एक वर्ष में इस सरकार ने जो कुछ किया है उसे यह देश कभी भी क्षमा नहीं करेगा।

श्री बालेश्वर दयाल (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, एक सवाल हरिजन वाला यहां भी हमेशा गूंजता है और देश में भी गूंजता है। हमारे राष्ट्रपति महोदय ने जो अपना भाषण दिया उसमें हरिजनों और आदिवासियों से संबंधित दो पंक्तियां बहुत सारगर्भित हैं। और मैं कोई नया सुझाव पेश नहीं करूंगा, जो उनकी पंक्तियां हैं उन्हीं के आधार पर कुछ ठोस सुझाव पेश करूंगा।

राष्ट्रपति जी ने कहा : "सरकार यह महसूस करती है कि इन वर्गों को राष्ट्र के प्रमुख कार्यों में अन्य वर्गों के समान स्तर पर, प्रभावकारी तथा स्वतंत्र रूप में भाग लेने में समर्थ बनाने के लिये स्थायी संस्थागत प्रबंध करने आवश्यक हैं।" और इसके आगे उन्होंने कुछ आयोगों की बात कही है। सदर साहब, हम सब लोग यहां अलग-अलग राजनीतिक वर्गों से आये हुए हैं और हम उनके प्रतिनिधि हैं, लेकिन हम लोग समाज के भी प्रतिनिधि हैं और यह हरिजनों और आदिवासियों की समस्या केवल राजकीय वर्गों की समस्या नहीं, यह समाज की समस्या है और यह सदियों से

चली आ रही है। कितने ही लोगों ने इस भेद को मिटाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक मिटा नहीं सके। उसका कुछ कारण है। जिनके हाथ में कलम की मालिकी थी उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था बनायी कि जिसमें हरिजन और आदिवासी हमेशा गिरी हुई हालत में ही रहें। जो आयोगों वाली बात कही गयी है, वह अपनी जगह ठीक है लेकिन ऐसे आयोग कई बार बन चुके हैं। सवाल यह है कि आयोग जो रिपोर्ट देते हैं, सरकारें जो कानून बनाती हैं आदिवासी और हरिजनों की सुरक्षा के लिये उनका ज्ञान भी उन हरिजनों और आदिवासियों को नहीं हो पाता है। आयोग की रिपोर्ट ऊपर ही ऊपर पड़ी रह जाती है। सवाल यह नहीं है कि हम कांग्रेस पार्टी की नीयत में शंका करें या कांग्रेस वाले जनता पार्टी की नीयत में शंका करें। इस राजनीति में शंका, कुशंका करना अच्छी चीज नहीं है, असली सवाल है काम का। जितनी भी रिपोर्टें आज तक आयीं क्या उन पर कुछ काम हुआ? वह होता नहीं इसलिये कि वह दुतरफा नहीं एक तरफा चलती हैं। सब से बड़ी कमी इस देश में है कि लोक-शिक्षण के लिये कोई संस्था है नहीं। जिन देशों ने तरक्की की है और अपने राष्ट्र का एकीकरण किया है वहां विरोधी दल सब से ज्यादा लोक शिक्षण का काम करता है। हम भी कल तक विरोधी दल में रहे। हमारा एक काम था लोक शिक्षण का। लेकिन विरोधी दल लोक शिक्षण का काम करें या न करें, पर सरकार का फर्ज जरूर है कि लोक शिक्षण का काम वह शुरू करे क्योंकि जो भी कानून बनते हैं. . .

SHRI K. K. MADHAVAN: Sir, 1 rise on a point of order. Is it not an insult to the Harijan Members of this House to say that the Harij'ans are ignorant of these reports? I am a Harijan ------- (Interruptions).

AN HON. MEMBER: It is not that way.

SHRI K. K. MADHAVAN; I have heard the translation. You cannot say it like that. He has specifically said that the Harijans do not know the reports. We know the reports.

श्री कल्पनाथ राय : आप उनको कहें कि वह हम को सुनने दें।

SHRI K. K. MADHAVAN: You are saying that the Harijans do not know the reports. We know the reports. Is it not an insult to UG? YOU should withdraw.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Please continue.

SHRI K. K. MADHAVAN: If you do not withdraw the statement, I will have to go out. I am not a language fanatic.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Every Member who follows the language will say that this was not the spirit of what the speaker was saying. Please do not take it in that fashion.

SHRI K. K. MADHAVAN: Then, what is the use of this translation? We are also intelligent people. We know much more than you. We know your mind also.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND (Punjab): He did not say Harijan *Shiksha.* He said *Lok Shiksha.*

SHRI G. LAKSHMANAN (Tamil Nadu): He said 'language fanatic'. 'Fanatic' is also a bad word.

श्री बालेश्वर दयाल : मैं स्वयं भी हरिजन और आदिवासियों में काम करता रहा हूं। पिछले 40—50 वर्ष तक मैंने हरिजन और आदिवासियों में काम किया है . . .

SHRI K. K. MADHAVAN: It is no use sitting here. You can speak your language.

श्री बालेश्वर दयाल : सदर साहब, मेरा सुझाव यह है कि जहां तक मुझे जानकारी

[श्री बालेश्वर दयाल]

है 40–50 वर्षों में लोक शिक्षण के अभाव में सरकार के कानूनों का पूरा ज्ञान उन लोगों को मिला नहीं और जहां मिला भी सारे देश में उनको सुरक्षा नहीं मिली । इसलिए जहां दो आयोग का इसमें जिक्र किया गया है, ये आयोग तो अपनी रिपोर्ट देंगे, लेकिन लोक शिक्षण वाली समिति या तो सरकार बनाये या विरोधी दल इस काम को ले तो यह हरिजन और आदिवासियों की समस्या कुछ सुलझ सकती है क्योंकि समस्याएं तो यहां सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं । इस तरह तो सुलझाना सम्भव नहीं है । इसलिए मैंने कहा मैं न कांग्रेस वालों की नीयत में शक करता हूं न जनता पार्टी की नीयत में शक करूंगा । जो लोग जाते हैं, इन हरिजन और आदिवासियों के नुमाइंदे बनकर जो भी लोग लोक सभा में विधान सभा में जाते हैं या यहां आते हैं वह दोनों जगहों में अपने को अल्प-मत में महसूस करते हैं। जब वह वहां सदन में बोलते हैं तो उनकी आवाज अल्प-मत में होने के कारण दब जाया करती है । नतीजा यह होता है कि पीड़ा लगातार दबती और बढ़ती जाती है तब कुछ सत्ता लोभी लोग आदिवासियों के प्रवक्ता बन जाते हैं और कुछ प्रवक्ता तो यहां तक बढ़ जाते हैं कि देश को कई भागों में बांटने का आधार भोले हरिजन और आदिवासियों को बना लेते हैं । इस देश में भी कई जगह आन्दोलन चले, वह चाहे सफल हुए या निष्फल हुए, मैं उसे छोड़ देता हूं लेकिन इनका इलाका, प्रांत अलग बना दिया जाए या इनका अलगाव कर दिया जाये, या प्रान्त अलग बना दिये जायें, ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इन सब घटनाओं में हमें बहुत गहराई से जाना चाहिए । अगर हरिजन और आदिवासियों के अलगाव की समस्या नहीं सुलझती है तो जैसे नारे लगा दिया करते हैं कि इनका प्रान्त अलग बना दो या अलग भाग बना दो, यह समस्या भी किसी रोज देश में व्यापक और उग्र हो जाएगी । यह बात भी मैं मानता हूं कि जो लोग विधायक बनकर लोकसभा और राज्य सभा या विधान सभाओं में जाते हैं वे सही ढंग से अपनी चीज नहीं रख पाते । अगर रख भी पाते हैं तो उसकी सुनवाई नहीं होती क्योंकि आवाज उनकी दब जाती है । मैं चाहता हूं कि जहां-जहां शैड्यूल कास्टस कांस्टीट्यूएंसीज हैं, आदिवासी कांस्टीट्यूएंसीज हैं वहां विकेन्द्रीकरण का जो नारा हमने लगाया, विकेन्द्रीकरण की भावना जो हमने जगाई उस सिलसिले में एक नई व्यवस्था हम को देनी है क्योंकि केवल सद्भावना से राजनीति में काम नहीं होता वैसी व्यवस्था भी होनी चाहिये । हमारी संद्भावना से राष्ट्र एक बने, उसमें ब्राह्मण और हरिजन में भेदभाव न हो, हिन्दू और मुसलमान वगैरा में भेदभाव न हो, ऐसी व्यवस्था हम को गठित करनी होगी । इस व्यवस्था के अन्तर्गत वह भेदभाव कटुता वाली और क्रोध वाली भावना धीमे-धीमे खत्म हो जाएगी ।

मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जहां-जहां ये कंस्टीट्युंसीज बनी हुई हैं––हरिजनों और आदिवासियों की कंस्टीट्यूंसीज हैं, वहां पर प्रखंड भी बने हुए हैं, ब्लाक भी बने हुए हैं । एक खंड अपने आप में इकाई होता है । जैसे अंग्रेजों के जमाने में हिन्दुस्तान का वाइसराय होता था । जो यहां का गवर्नर होता था उसकी सारी जिम्मेदारी होती थी कि वह हरिजनों और आदिवासियों की सुरक्षा का सीधा जिम्मेदार बने । मैं कहना चाहता हूं कि वह व्यवस्था उस हद तक बुरी नहीं थी । आज भी यहां राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल हैं उनकी भी हरिजनों और आदिवासियों की सूरक्षा-सुव्यवस्था की जिम्मेदारी सीधे लेनी चाहिये । इसलिये मैं चाहता था कि ब्लाक स्तर पर अलग से चुनाव कराये जायें और वह निर्दलीय चुनाव हों । इसके लिये जरूरी है कि निर्दलीय चुनाव ब्लाक स्तर पर हों । मान लीजिए कि एक कन्टीट्यूंसी हरिजन और

आदिवासियों की है तो उसमें दो-तीन ब्लाक आते हैं। इन तीनों ब्लाक के अलग से चुनाव हों और वह चुनाव हों गवर्नर कौंसिल के लिये। जो राज्यपाल हैं उसकी एक कौंसिल अलग बने। उसमें आदिवासी अपनी भाषा में अपनी बात कहें। मान लीजिए खड़ी भाषा है, हिन्दी वह बोल नहीं सकते, अंग्रेजी बोल नहीं सकते यों और कोई भाषा नहीं बोल सकते तो वे अपनी भाषा में, बोली में, गवर्नर कौंसिल में जाकर अपनी पूरी बात कहें। क्योंकि जो ब्लाक हैं वे अपने आप में डैव्लेपमेंट इकाई हैं, डैव्लेपमेंट युनिट हैं और ब्लाक के अन्दर अनेक तरह के भ्रष्टाचार चलते हैं और उसके सीधे शिकार हरिजन और आदिवासी होते हैं इसलिये कि वे अपनी बात को वहां कह नहीं सकते। कहीं ऐसा न हो कि उनका प्रवक्ता कोई बन गया है और वह प्रवक्ता वहां अपने को अल्पमत में महसूस कर रहा है, माइनोरिटी में महसूस कर रहा है। उसकी आवाज वहां नहीं सुनी जाती। इसलिये गवर्नर कौंसिल का ऐसा सैट-अप बने जिसमें ब्लाक स्तर से हरिजन और आदिवासी आएं और अपनी समस्याओं को वहां पर खुल कर रखें। जो भाषा वह बोलते हैं उसी भाषा में वह अपनी बात को रखें। दूसरे इस गवर्नर कौंसिल की बैठक कम से कम एक वर्ष में दो बार निश्चित रूप से हो। जो कुछ उस गवर्नर कौंसिल का फैसला हो, जिसमें हरिजन और आदिवासियों ने अपने भाव, आकांक्षाएं, शिकायत रखीं हैं उसे गवर्नर अपनी रिकमेंडेशन के साथ विधान सभाओं और लोकसभा को भेजें। यह जो अल्पमत वाली भावना कायम हो गई है यह भावना खत्म हो। पहले जो सरकार थी उसको भी हम सुझाव देते रहे और जनता पार्टी की सरकार आई इसको भी हम सुझाव देते रहे। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि कई जगहों पर तो कत्ल भी हुए हैं और उस कत्ल की आशंकित सूचना पांच-छः रोज पहले हमने दी। इस बारे में लोग बोले भी लेकिन वह बात सदन में सुनी नहीं गई। यह पिछले 30 वर्षों में भी हुआ और अब भी होता है। बहुत पहले से मैं लगातार सोच रहा हूं कि जब तक ब्लाक, खंड से अलग-अलग हरिजन और आदिवासी गवर्नर कौंसिल में नहीं जायेंगे तब तक उनकी जो आवाज है अभाव आकांक्षा है वह प्रकट नहीं हो सकती। नतीजा यह होगा कि हम जैसे जो स्वार्थी नेता हैं अलग राज्य बनाने वाली बात रखेंगे।

[**Mr. Deputy Chairman** in the Chair]

इस देश में पहले भी यह हो चुका है और अलग-अलग राज्य बनाने की बात को पुरजोर उठाया गया है। कई जगह अमल में भी आया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि देश का विखंडन न हो। यह जो सद्भावना वाला प्रचार चल रहा था इस सद्भावना वाले प्रचार को नई व्यवस्था देकर सफल प्रक्रिया अपनाई जाए। इसलिये मैं चाहता था कि इस बारे में कुछ सुझाव सरकार के सामने रखूं। मैं यह भी चाहता हूं कि अगर लोक सभा और राज्य सभा, इन दोनों सदनों की बैठक बुलाकर इस समस्या पर विचार किया जाय तो उपयुक्त होगा। मैं बहुत दिनों के बाद इस जगह पर आया हूं और यह मानता हूं कि अब इस समस्या का हल होना संभव है। मैं यह भी मानता हूं कि किसी वर्ग के 2–5–10 आदमियों को करोड़ों का प्रवक्ता बना कर यह समस्या हल नहीं हो सकती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि समस्त आदिवासियों और हरिजनों में स्वयं स्फूर्त्त सही प्रवक्ता बने। अगर इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाएगी तो सिर्फ खण्ड स्तर पर और प्रखण्ड स्तर पर ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों का भला हो सकता है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में जो देश के विघटन की बातें कही जाती हैं वे बंद हों।

ये कुछ सुझाव मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबंध में कहना चाहता था और इसलिए मैंने इनका जिक्र यहां पर किया है। धन्यवाद

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, Shri Sanjiva Reddy after assuming the office of the President of India has addressed the Joint Session of Parliament for the first time. This is an Address not only to the Members of Parliament but to the nation as a whole and in this Address the policy and programme of the Government of India is made known to the people and to the nation as a whole. I must say that this Address does not contain anything which is inspiring or dynamic. We were expecting much more from the President and the Govern, ment of India. All the same, I am glad that the President has made it clear that the Government is remov-. ing the authoritarian provisions that were introduced in the Constitution. I am quite sure that all the political parties and all the people who believe in democracy and democratic prin. ciples would co-operate with the Government and support it in undoing the provisions of the Forty-second Amendment by abolishing the distortions that were introduced into the Constitution during the Emergency. The Government has restored the freedom of the press and the freedm of the people and the liberty of the citizens which had been taken away by the previous Government under the premiership of Mrs. Indira Gandhi. The judiciary which is the custodian of democracy, is being restored to its proper place by this Government and we are very glad about it. The Supreme Court and the High Courts had been reduced to the position of third class magistracy by the previous Government. Now, at least, these highest courts of India are be. ing restored to their original position.

While welcoming the setting up of the Minorities Commission, 1 beg to say that the terms of reference and the functions of this Commission are not quite clear. At the same time, I am quite clear that the Janata Government has recognised the existence of minorities in this country, namely, Muslims, Christians and others, because it has appointed the Minorities Commission. I am very glad about it and I welcome the setting up of this Commission. A backward classes commission is also bein^ set up. In this connection, I should like to say that Muslim minorities are not only a religious minority but they are also a backward community. They are backward educationally, they art backward socially and they are backward economically. In many States they are as good or as bad as the Harijans are. So, I should apppal to the Government to direct toe Backward Classes Commission to consider whether the Muslim community could also be included as a backward community. In many States like Kerala and Tamil Nadu Muslims have been treated as a backward community and extended all facilities that are being given to other backward communities. I appeal to the Government of India as a whole; they should consider whether this community could be considered as a backward community for the purposes of the Backward Classes Commission.

The next Five-Year Plan, it has been hinted at in the President's Address, will lay particular emphasis on agriculture and allied activities, irrigation power and all that. In this con. nection, I should iike to say that the green revolution which is the criterian of every Government, is becoming a dry revolution. I would appeal to the *mata Government to see that the green revolution is going to be a green revolution. Sir, the prices of food-grains are going down very low and the prices of commercial ciops are going up. As such, this will upset the rural economy. Farmers who cultivate foodgrains, are going to convert their farms for commercial crops. As such, the production of foodgrains is going to be reduced. I would, therefore appeal to the Governmet to see that subsidy is given to the farmers to produce more foodgrains; other-wise, it will upset our food production programme.

Nothing has been said shout the implementation of land reforms. I

do not know why. Even in some of the northern States, land reforms are being taken very lightly. There are land-lords who possess hundreds and thousands of acres of land in the name of one man or one family. These land reforms should be taken very seriously and minimum economic holdings should be fixed so that fragmentation of land could be avoided in the best interest.3 of land reforms and agricultural production.

Crop insurance is one necessity for the farmer. We have been pleading for the introduction of crop insurance scheme and it has not been considered by the Government. Nothing has been done about it.

Our achievements in foreign affairs are very good and credit for the same goes to our hon. Foreign Minister, Shri Vajpayee. He has improved our relations with the neighbouring countries and also with the socialists countries and Russia as well as with the United States of America and Britain, We have restored our old friendship with our neighbouring countries like Ceylon, Bangladesh and Pakistan. As far as Bangladesh and Pakistan area concerned, they are not only our neighbouring countries, they are a part of our own history. History of India, of Bangladesh and of Pakistan is the same; geography is the same; cultural background and civilisation is the same. I am very glad that Shri Vajpayee has taken so much interest tc maintain our relationship with Bangladesh and Pakistan and I am sure that he will see to it that our friendship is restored with China also, so that when our border tension is reduced, we are able to divert our energies and resources for the national development.

On the eve of the visit of Mr. Carter, a number of Palestinian students in Delhi were served with a notice, not to move out of their residences. Some of these students were arrested also. I do not know why lit was done when everything was peaceful here. I hope the Government will examine this aspect because this may create a bad feeling among the Palestinian friends and students who are in India.

Unfortunately, war has been going on between Ethiopia and Somalia. India should use its good offices with the United States of America **and** the USSR and the U.K. and see that the dispute between Ethiopia and Somalia is arbitrated upon so that peace is mai'atained and preserved in this region.

I would also like to say about our Centre-State relations. Much has been said about the Centre-State relationship. There is no doubt that we must have a strong Centre but when I speak about strong Centre, in my opinion, more financial powers should be given to the States. We cannot equate the other States with Kashmir. We know, Kashmir has got a historical background; we know, a special status has been given to Kashmir in the Constitution itself. Therefore, Kashmir should not be equated with the other States. Kashmir has been give'n a special status because of historical reasons. As far as the other States are concerned, they should be given more financial powers so that they would be able to carry on their developmental activities and their initiative would not be curtailed. When we speak about giving more powers to the States, the States should also give more powers to the local bodies, to the zilla parishads, to the pancha-yats and so on. In my own State, Kerala, for the last sixteen years, we never had any elections to the pan-chayats. sixteen years ago, in 1962, elections to the panchayats were held. Now, the panchayat presidents would say that they would not go back and that they have been i'n office for more than sixteen years. In Kerala, Assembly elections have come and gone. Chief Ministers have come and gone. Chacko has come and gone; Pattom Thanu Pillai has come and gone; R. Sankarav> has come and gone; and

[Shri Hamid Ali Sehamnad] now, Mr. Antony is here. He is also trying to go out. so many people have come and gone. Of course, Karunakaran has gone because of Rajan's case. But he is again trying to come back. Now, you find that even there, the State wants to have more powers in its hands. They do not want to Sive Powers to the zilla parishads, to the local bodies and to the panchayats. This is going on. My friend's party is ruling in Kerala. 1 would make an appeal. There should be decentralisation. More powers should be given to the States. At the same time, the States should not be selfish and have all powers with them. They should give more powers to the panchayats, to the municipalities and so on. There should be decentralisation of powers. There should not be concentration of powers in the hands of a few people. This is absolutely necessary. With these words, I conclude.

•

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO; You should begin from the highest level. You should start from the Centre.

SHRI RISHI KUMAR MISHRA (Rajasthan): Mr. Deputy Chairman, Sir, last year, when we met in this House, after the elections to the Lok Sabha, I had stated that my party, the Congress, though it was defeated in the Lok Sabha elections, regards it as a victory for democracy and I congratulated my friends in the Janata Party on their success in securing the mandate of the people. However, Sir, I must admit that it was a premature statement which I -made at that time. The hope that the Janata Party will at least restore democracy in this country has been belied completely. The last twelve months of the Janata Rule is a record of broken promises, unfulfilled assurances, hollow declarations, disillusionment and disenchantment. When I am using these phrases, Mr. Deputy Chairman, I am doing it consciously and deliberately and after a very careful examination of the performance of the Janata Government in the field of economic development, in the field of administration, in the field of law and order, in the field of education and so on. I think, Mr. Deputy Chairman, the President's speech, insipid and disappointing as it is, truly reflects the performance of the Janata Government.

Let us begin, Mr. Deputy Chairman, with the most important promise which brought the Janata Party to power. It was the promise of restoration of the basic civil rights, restoration of the right to the people, to the working class, to organise them-' selves and to fight for their demands and grievances. I would like to enquire from the spokesman of the Government and the Treasury Benches whether the attack on the teachers in U.P. is consistent with democracy, whether the attack o'n the medicos in Bihar is consistent with your commitment to democracy, whether the firings and the lathi-charges on studentg in U.P., Bihar and elsewhere is consistent with your democratic professions and whether the attack on the workers in Ghaziabad, Sonepat, Faridabad, Kanpur and other places in the country is consistent with youi professions of restoration of civil rights and trade union rights. For the first time in the history of this country a Government banned the right of the workers to go on strike. It was do'ne in the industrial zone *ot* Uttar Pradesh soon after the Janata Party came to power. I would like to know whether the ban on the right of the workers to go on strike is consistent with the restoration of basic democracy, whether the promulgation of mini MISA in Madhya Pradesh is consistent with the assurance that was given, whether the decision to incorporate the provisions of preventive detention in the Criminal Procedure Code is consistent with the premises that they have made to the people. I can go on, Mr. Deputy Chairman, adding to this list many

more things. Every week of Janata riue has witnessed, auring the last 12 months an attack on the basic democratic rights of the people. And what is worse, Sir. though the emergency has been removed, there is a deliberate attempt to strike terror into the nearts of not omy the opponents outside the Janata Party, but even within the Janata Party who do hot agree with the Home Minister or with the R.S.S. Only today three Janata Members of Lok Sabha, Sar-vashri Shard Yadav, Harikesh Bahadur and Lalu Prasad Yadav, have come hack from Gwalior. They went there because the RSS Chief Minister in a public meeting called upon the RSS cadres to attack those Yuva Janata workers who were demanding the withdrawal of the mini-MISA. Sir, the use of RSS storm-troopers to silence the opponents within the Janata Party is the beginning of a fascist regime. This is the beginning of a fascist regime in this country. I would like to appeal to all those within this House and outside this House. To see that the danger of authoritarianism is looming large on the horizon, the failure of the Janata Party to solve the basic economic problems of this country is pushing it in a direction where they are trying to silence the voice of protest by taking recourse to strong-arm methods and neo-fascist and semi-fascist methods. Mr. Deputy Chairman, Sir, the job of a Government is essentially to govern.

SHRI SITARAM KESRI; There is Hone to hear from the Treasury Benches.

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जनेश्वर मिश्र : हम लोग आपकी सेवा म बैठे हैं ।

श्री सीताराम केसरी: कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर भी तो रहना चाहिए ।

SHRI RISHI KUMAR MISHRA; bathe first anu basic responsibiity of any Government is to guarantee security to the citizens of this country, and the record of no Government in this country, in any State or at the Ce'xitre, has been so disappointing as the record of the Janata Government. Mr. Deputy Chairman on an average, in Meerut division from where the Home Minister of this country comes, every fourth day there *s cases of rape, one dacoity, one murder, lour riots, two lootings ten burglaries and three road accidents. Now these are the figures given by the DIG of that range in a press conference. This is not an allegation made by a political opponent. The crime figures in Bihar are rising. According to the Janata M.P., a senior leader Mr. Ram-anand Tiwari, the crime figures of Bihar are bei'ng suppressed deliberately and he has alleged that 120 cases of dacoities were refused to be registered and they were later registered only as burglaries. As far as Delhi is concerned, Mr. Deputy Chairman, I need not say much about it. All of us are living in this capital for half of the year and a newspaper commented that it is scandalous that the acts of lawlessness in Delhi should have sharply increased—nine robberies in a single evening over a small distance of about 25 kilometres. In Punjab the murder number has gone up. Assaults on public servants have increased and when people protest, see how the police reacts—it catches hold of the Secretary of the Union Ministry of Tourism takes him to the police station because they are not able to catch hold of the dacoits. They keep him there for two hours and he has to contact the Home Ministry in order to get out of it. There is a climate of chaos, Mr. Deputy Chairman, because of the failure of the Government to maintain law and order.

On the industrial relations front it appears that the country is being pushed towards chaos. Of course, when you have Ministers who have orga-

[Shri Rishi Kumar Mishra] nised acts of sabotage and acts of law lessness, evidently thi$_s$ is what is go-'ing to happen. There have 4 P.M. been 1363 strikes and 199 lock-outs, affecting 10 lakh workers during the Janata rule from April to October, 1977. And what is more dangerous is that within the Janata Party, because of their failure to maintain industrial peace, a climate is being created to attack the basic rights of the workers. Mr. S. M. Joshi, Janata Party leader and one who has, I am sorry to say, a socialist background, has demanded a ban on strikes in industries of plants where the workers are receiving wages.

Mr. Deputy Chairman, I am pointing out all these developments because the Indian people dismantled the emergency regime, the Indian people dismantled the authoritarian regime, the working class people fought for the restoration of democracy* I would like to warn the Janata Government that if they think that in order to cover up their failures to solve the problems of the people they can re-impose on this country an authoritarian structure by taking recourse to the terror tactics, this will not work. Shri Baleshwar Dayal, for whom many of us have great respect because he has devoted a lifetime for working among the Scheduled Tribes and the Bhils of Madhya Pradesh and Rajas-than, referred to the problems of the Harijans and Adivasis. Mr. Deputy Chairman, the less said about it, the better it is. When the President of India was delivering hi$_s$ Address to the Joint Session of Parliament, newspapers carried a $_{re}$port that a Harijan wa$_s$ burnt alive in Rupetha village of Rohtas District. Th$_e$ name of the young man was Vashistha Dusadh. Those people went there and gave th$_e$ names of five persons in the FIR saying that these were the persons who were res-ponsible for it. Not one of those five persons was arrested and the Bihar Government says that they are not able to trace them. It has been allege^ that this is largery because they have political affiliations with one of the constituents of the ruling party.

In Gujarat, which is Prime Minister's own State, incidents of atrocities on the Harijans a'nd on the agricultural labour are increasing every day. In the Baula Village Shrimati Kul-karni is not here; she knows about that village— agricultural labourers, including four women, were assaulted by landlords and when there were complaints, nothing was done about it. In Orissa, after the Janata Party has come into power, on an average, every 15 days there is an incident— a big incident—of assault on the Harijans. The latest was in the Bada-banta village of Cuttack District where 200 persons gathered together, forced the landless out and attacked the agricultural labour. Of course, in Uttar Pradesh, forcible possession of land given to the Harijans is going on a very large scale.

Now*, Mr. Depuy Chairman, why this happening? There ar$_e$ any is number of such incidents. Why is this happening? I shall not give my own explanation for this. I shall only quote what a Janata Party M. P., Shri Yamuna Prasad Shastri, has said in regard to the growing incidents of atrocities on the Harijans in Madhya Pradesh and other parts of the country. He says:

"The feudal elements feel that the Government belongs t$_0$ them and knowingly or unknowingly an impression to that effect has been created."

This is the statement made by Shri Yamuna Pradsad Shastri and I havp nothing to add to that.

In the economic field, Mr. Deputy Chairman, I have a constructive suggestion to make. I recommend to the President that he should re-name some of the Ministries of this Government. The Ministry for Industry should be re-named a.3 the Ministry of

De-industrialisation. The Ministry of Commerce whose job 13 to promote export should be re-named as the Ministry of Import Promotion and the Ministry of Agriculture whose job should be to help the small marginal farmers and agricultural labour should be renamed as the Ministry of Rich Farmers, because this is exactly what is happening.

The Janata Party's claim that they are going to spend 40 per cent, of their inv'estible outlays on agriculture is nothing but a joke

AN **HON.** MEMBER: Wrong.

SHRI RISHI KUMAR MISHRA: All of us know that during the last few Plans the total investment on agriculture is now being revised by the Planning Commission. This includes investment on agriculture, on rural education, on agricultural research, on fertilizer etc. It comes to 33 per cent. This 7 per cent, increase in that outlay is being presented to this country as a very major departure. And, Mr. Deputy Chairman, we must understand that those who are talking of neglecting industries in this country are working against agricultural development in this country because the farmers, the agriculturists of this country want fertiliser, want electricity, want other inputs which are thp products for industrial development.

Mr.Deputy Chairman, the attack by the Janata Government on science and technology is something which is hitting at the basic national independence our country. Sir, the decision of the Government to unilaterally give up nuclear tests is not only a surrender a compromise with our national honour but it is jeopardising the future of science and the technological progress of our country. Sir, the future of the world will not be in the hands of those who control armaments. It will also not be in the hands of those who have money power. But the future of the world will be controlled by those who have technological power. And the biggest problem which the developing countries in the world are facing is concentration of technological power in the hands of three of four countries of the world, people who are not able to look beyond their nose, who cannot comprehend all the problems and challenges which we have to face in the 21st century. They are acting in a manner which will make India dependent and vulnerable to external pressures.

Before I conclude, Mr. Deputy Chairman, I would only like to say that a stage has reached in this country when the battle agaimst the Janata Party's policies and Janata Party's programes of imposing a backward regime in this country, of letting loose repression on the poorer sections and also of pursuing policies which will compromise national indepence and self-reliance has become a battle for the future of this country, for the poor of this country, to save rural labour, agricultural labour, the working class, the middle classes, from the regime of a handful of exploiters and their supporters who want to use the slogan of democracy in order to impose an authoritarian structure in order to divide this country by pursuing reckless policies which have communal overtones which have linguistic overtones, which tend to weaken this country, which tend to make India subservient to certain powers in the world. These facts have neither been mentioned in the President's Address nor in the latter .speeches of the External Affairs Minister. They do not have the courage to refer to the most important problems in foreign affairs which affect India's security, namely, Diego Garcia. Why should the President's Address not mention that the military base in Diego Garcia be removed? Is it because we want to placate Mr. Carter? He talks coldly and bluntly and we do not speak of Diego Garcia. We give up on the question of nuclear proliferation test.

Shri Ramamurthy referred to the question of Iranian students. I must say that it is shameful for a Government to treat the Iranian students in manner that they have been treated, to treat the Palestinian students in the

[Shri Rishi Kumar Mishra]

manner that they have been treated, to push back the Bangladesh refugees from India in order to placate the military regime that is growing all around the country. India, Mr. Deputy Chairman, has a record of fighting for democracy fighting for human values, figting for freedom. No Government *ot* India should act in a manner which compromises these basic postulates by acting in a manner which is shameful. The way they are going on does not enhance but undermines and compromises India's position especially among those countries in the world which are fighting for freedom. I am quite sure, Sii', the discussion in this House will make the Janata Government sit up. They should not indulge in self-righteousness vis-a-vis the excesses that were comitted during the period of emergency, when authoritarianism that was attempted to be imposed. These were not the propensities of a single individual ,

These were the results of the whole system to solve the basic prolems of this country and if they continue with those policies and if they seek to suppress those problems and not solve them, they will also meet the same fate. The Indian people have shown their capacity to throw out the most powerful authoritarian regime that ■was sought to be imposed. They will throw out your regime also in no time, I am quite sure. Thank you.

SHRIMATI NOORJEHAN RAZACK (Tamil Nadu): With great respect, Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for the opportunity given to me to participate in the discussion on the President's Address.

It is indeed a salutary feature that the powers of the courts and the freedom of the press have been restored in the wake of lifting of the emergency. The courts and the press are the two eyes of democracy and can be powerful instruments for the development of the country on all fronts. In this connection, right-thinking citizens will not fail to express their hopes that the courts will maintain the very high standards for just and expeditious settlement of cases and that the press—one and all—will exercise their rights fairly and fearlessly with real objectivity, with the sole aim of making the country better at every step.

We find that the Government has claimed credit for proper management of the economy and for paving the way for making a rapid advance in the coming years. I fo_r one would not like to dispute it. However, it will be less than charitable if we do not admit that the considerable food and foreign exchange reserves formed a suitable base for wise and farsighted measure to make a big and calculated leap for accelerated progress. Nevertheless, it has to ba said that the efforts with a sound base for takeoff have not been laudable and imaginative to arrest the soaring prices of all essential commodities. The common man in the organised sector of course is able to bear the brunt to some extent, but what about the common man in the unorganised sector? It would be facile to argue that he will drawn anyway whether the prices are a few points above or below a line. The efficiency of the Government will be largely judged by the availability of commodities for a bare living to the common man at reasonable prices. Of this we have not seen an evidence so far. The plea that the situation has not worsened beyond repair would be only a tragic confession of ineptitude in tackling the problems dyamically.

Regarding the economic and industrial policies, I have to admit to a feeling of confusion by conflicting statements of various members of the Government. Nobody will quarrel about the emphasis on development oi small-scale and cottage industries. It is all to the good. But how much have they developed during the past years? How much new employment has been generated last year? We do not see any evidence. Nor does the PresL dent's Address give any indication.

On the other hand, we hear disturbing reports about import of polyes-

ter filament yarn for helping big industries and computer equipment and " about support to big carpet inudstries, which should be left t_0 the solo domain of thousands of our carpet craftsmen. What is the firm and clear policy of the Government in this regard?

It is heartening that agricultural production is looking up, but, at the 'same time, it is to be released that our full potential for growth has not yet been adequately tapped.

A problem of gigantic magnitude, the problem of housing continue to haunt us, and the conventional methods of housing will not make much of ..a dent on the problem. Ways and means have to be found for the community itself to be involved in a far-sighted and imaginative programme of functional houses, if hundreds of thousands of our brethren are to have a roof over their heads. The President',3 Address has not touched on this manifestly urgent problem.

Though the need of the hour is rapid rural development, let us not forget that India has forged to a front place in science and technology which should be purposefully used as part or an overall programme for updating traditional skills and improving production and distribution techniques.

In the field of education, there is an air of uncex'tainty. What is the final pattern of education for our children?

In the field of health, the situation is depressing. A vast majority of the rural communities remain deprived of total medical care, whereas, on the other side, we hear of unemployed medical graduates. What is the clear policy of the Government to make a break-through on this problem? From all accounts, the growth of population is outstripping our control and unless the Government organises energetic efforts for control of births, it will lead to all development being stultified.

Sir, the issues at stake are vast and momentous. They cannot be solved by any one set of people, however conscientious though they may be. It calls for a total effort and highest qualities of pragmatic and scientific thinking supported by self-effacing professional competence in implementation. A multi-party approach is indicated for making multi-pronged efforts on an agreed strategy. But this is not going to be helped, as we saw the other day, by certain Hindi zealots pressurising the President to address in Hindi. There are much greater things to be done than foisting Hindi on the whole country. That way lies the danger to the unity of the nation. Let us have our sights clearly fixed on the first things that should be done first, namely, the socio-economic betterment of the masses by devising an overall strategy and by galvanising the community for meaningful participation.

Another important problem to which I want to draw your attention is this. The people from the Southern States have been struck by an unprecedented calamity due to cyclone which hit us very hard indeed. Countless lives, cattle, houses, fishing boats, etc. have been lost. The task of rehabilitation of the suffering people demands a national effort and not only the effort of the State concerned. The Centre has given only advance plan assistance. For the States like Tamil Nadu, whose resources are slender, the Centre should come out with a liberal grant so that the States can not only attend to the repair of the cyclone ravages but also take up important development work. In all such cases of national calamity; the Central Government should lay down precise guidelines for immediate aid without taxing the State resources.

Another thing which I want to mention here, Mr. Deputy Chairman, Sir, is the slogan of the Janata Party: humble and simple life. Last month —if I am not mistaken, it was in January—I had been to Ernakulam.

[Shrimati Noorjehan Razack]

There was a Public Relations Officers' conference there. When I was there at Ernakulam, I was told that hon. Mr. Advani was there and some State Ministers were also there, and for the sake of cooking for them there was a batch of nearly 15-—20 people—all taken from here for the sake of cooking for the Ministers. And the Janata Party's slogan is "Humble and simple life." I do not know how much they have spent for the food there. It is a disgrace for the State of Kerala. I do 'not know whether the Kerala people were not in a position to give them good food At the same time...

(Interruptions)

Please allow me to talk. This is "my maiden speech, Please allow me to talk for a few minutes.

At the same time, Deputy, Chairman, Sir, the Chief Minister of Tamil Nadu very often visits Delhi and stays in the Tamil Nadu House. He enjoys the simple f°°d that is serve to him. He is a man of priciples and he does what he says. Nobody on earth can deny this. When we say that we want to have a simple and humble life, we must first of all make ourselves as an example to others.

Today morning, Shrimati Kulkarni, while discussing the matter, said that the Janata

अगर उनके कन्धे चौड़े हैं तो मैं यह जानना चाहती हूं कि इन कन्धों पर क्या बठा हुआ है। जनता आज पुकार रही है और लोग भूख से चिल्ला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम भूख से मर रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि चीजों के दाम कम हो गये है और स्पेशियली इन्होंने कहा था कि जनता साड़ी के दाम कम हो गये हैं।

Just because I am myself a lady, I want to stress on that point. Deputy Party's shoulders are Chairman, Sir, I am really ashamed to talk about it. People talk about it in the public. Janata saree, they do 'not want to take for the second time.

Another thing that my friend mentioned is that the cost of the saree has come down from Rs. 30 to Rs. 15. The people who purchased the saree say that they are unable to wear it is next time. The colour goes and it is torn within no time. And members of the Janata Party are very proud *in* saying that their shoulders are broad,

They cavi praise themselves, but they should do some concrete work. (Interruptions) I am not finding fault with the Party but the thing is that they must do some concrete work and let the public be pleased with them The Janata, the public, is crying, but the Janata Party is unable to hear the voice. You should see that something is done for them so that they lead a happy and good life.

With this I conclude my speech with reaffirmation of ray thanks to you, Sir, for according me the opportunity.

SHRI CHARANJIT CHANANA (Delhi): Mr. Deputy Chairman, Sir, 1 shall refer to only the economic issues covered by the Hon. President in his Address On the prtee front, the Janata Government could deserve real congratulations if the inflationary pressures, as they have claimed, had been brought under check. We appreciate that the Hon. President was realistic enough that he admitted in the same address jater that he did not feel complacent about the price situation.

The next day the hon. Commerce Minister selected a few items of essential commodities from the wholesale Price Index Number prepared by the Economic Adviser's office, which recorded a price fall over a few weeks and he went on to say that the prices had gone down. The hon. Ministei should have selected not only thost

items which fed his argument, but he should have taken a period which was a meaningful period for comparison. Now, 1 have, in fact, worked out a meaningful trend and movement of the prices, and it is a comparison between the prices as on 5|2|1977, when there was the Congress regime, and the prices as on 4|2|1978 under the Janata regime. The same indices relate a different story. The index for food articles on 5]2|1977 was 158.8 -and it went up to 169.8 on 4|2|1978, thus recording a rise of 7 per cent. The index for foodgrains rose from 160.4 a_s on 5|2jl977 to 170.8 as on 4|2|1978, recording a rise of 6 per cent. The index for pulses rose from 168.8 as on 51211977 to 230.4 as on 4|2|1078. This represents a rise of 38.5 per cent. The index for fruits and vegetables indicate a rise of 12 per cent. The index for eggs, fish and meat indicate a rise of 12.5 per cent and the index for condiments and spices indicate a rise of 22.5 per cent. The highest weightage is given in this Index to food articles, namely, 29.8 per cent. When you move on to the Consumer Price Index, which is more meaningful, the picture is different. The wholesale prices are meaningless to the consumer because consumers like you and me do not go to tho wholesale markets to buy things. When applied to the poor man, the weightage of these items would cross 60 per cent. Facts speak louder than statistics.

Fortunately the Prime Minister appears to be getting out of his habit of promising to bring the prices down within four months. And whenever he gave the promise, he never gave the date from which it would start. He made a different public confession at Chowpatty in Bombay on the evening of the President's Address. Referring to the demand for bringing down the prices of commodities immediately, Mr. Desai pointed out that it would be unfair to ask for the baby immediately after the marriage. He said, "It will be sometime before the babv arrives. It may take five years sometimes and more in certain cases. 1904 RS—9

It ail depends on individuals. How can anyone expect the Janata Party to bring down the prices within 12 months of being in office?" He added that efforts in that direction had already been initiated and they would certainly start bearing fruit in the months to come.

The baby Mr. Morarji Desai i_s promising is clearly a freak. Obviously the Janata gynaecologist is not yet sure of the date of delivery and is also hesitant to order a Caesarian operation.

Although the price indices relate the story of falling prices, the consumer has been undergoing the strain of a price hike. In fact, the consumer always puts a very meaningful question to you, that is, whether he is telling the truth or the indices are telling the truth. The public have to decide themselves as to who i_s telling the truth in the matter.

Sir, Mr. Patel has given hope to the Government employees of a rise in their D.A. The worker, however, lives in doubt because he knows that the indices are cheating him, without knowing how much.

Our Prime Minister has rendered a piece of advice to the public on getting rid of the price hike in pulses and vegetable oils. He advised the people to shift from high-priced items to low-priced alternatives. One, changing consumption patterns is not an overnight exercise. Two, the poor vegetarian whose only dish with cha-pati or rice is dal, can only shift to SALT.

The honourable President has also talked very high of a proper management of the economy which, according to him, resulted in a higher growth rate. Apparently, a management technology helping an economy like India's attaining a 5 per cent growth rate, deserves or should deserve congratulations. The 5 per cent estimate appears to be nearer a gues-

[Shri Charanjit Chanana] timate rather than a projection because the predictable non-agricultural part of the economy is going at **a** record low charge because of the sluggishness in investment climate.

Shyness of capital in the country has been recognised both by the Government and the industrialists. Shri Patel might have been preparing the Budget preamble while speaking in Surat. But he admitted in his public speech at Surat that the investment climate was so sluggish that it had become a puzzle for him. Probably in this Budget he might make an effort to natter the industrialists in the way in which it suits them to improve the investment climate.

The 5 per cent growth rate expres-ed by the honourable President also gives credit to the agricultural sector having behaved well. Let us wish rather let us pray, that the God of Rain remains in a good mood for the next crop. A policymaker does not and should not base his projections without studying the past performance or behaviour of the monsoon. The meterological experts do not support the optimism of whosoever has worked **out** the guestimates for the President's Address unless it has been done only to flatter the master. Westerly winds, at a height of 30,000 ft., are too strong this year which leads to the late advance of the monsoon or inadequate rain. Secondly projections are also built on the past behaviour of the monsoon. An analysis of 102 years of the behaviour of the monsoon shows that the probability of the next rainfall to be good is only 13 per cent. While analysing the behaviour of the monsoon between 1876 and 1977 the meteorologists have worked out the probability of a good monsoon in northern India at 17 per cent and for the Peninsula at only 10 per cent.

The quick estimates prepared by the Central Statistical Organisation on the 23rd of the last month indicated **that** the- national income in 1976-77 increased by 1.4 per cent as compared to an 8.8 per cent growth in 1975-76. But the same Organisation attributed this fall in the growth rate in 1976-77 mainly to the low level of agricultural production. The SCO estimates mention that "all other sectors,—this relates to the behaviour of sectors other than agriculture in 1976-77— however, registered substantial increases; noteworthy among them are: manufacturing—9.7 per cent, construction—9.6 per cent, electricity, gas and water supply—11.1 per cent, and railways—7.4 per cent. The Janata Government inherited this also but in 11 months they have gambled away with this lot. The rate of capital formation is also registering a downfall. This, Sir, is not a healthy index for a developing economy like ours which has crossed the take-off stage.

May I draw your kind attention to another interesting gymnastics in statistics? The CSO estimates were based on 1970-71 base whereas all the earlier estimates declared and announced by the Government, including the economic survey, had a different base, namely, 1960-61. For reasons best known to the statisticians, the game of comparing the in-comparables is a puzzle for the common man. To please the masters, the statisticians erected a new index with a new base. This reminds one of a heated dialogue between Chamberlain and Churchill when the latter was his Minister. Chamberlain had asked Churchill to supply some statistics to him. Having got no response from Churchill for a few days, he got annoyed and asked for Churchill's explanation as to why the data had not been supplied to him. Churchill very softly replied to him: My Lord, you had asked for statistics. But you forgot to mention whether you want the statistics for or against the proposal.

The present growth rate has not been prepared by the CSO; nor are the projections based on the figures prepared from the estimates of **CSO.**

Thus, the source of collecting or fabricating the data is also based on *who can supply for and who can supply against'. This time the de. mand was for a higher rate of growth whereas last time the demand was for a lower growth. The growth rate based on guesstimates depends on the moods of Rain God. Supposing—God forbid and we pray that the Rain God remains in good mood—He is off his mood, then it is not only the agricultural part of the growth rate which will be affected by the behaviour of rains, but also the agro-based industry depending for its raw materials on agriculture.

The next point in the President's Address is the balance of payments. The balance of payment and the foreign exchange reserves came in the Tot inherited by the Janata Government again. The balance of payment was - strong enough to accommodate what the President has mentioned as deceleration in export earnings. The mounting foreign exchange reserves at an average rate o[1] [R]s. 150 crores per month have touched Rs. 3,600 crores. Unfortunately, the mounting reserves, if not utilised, would prove inflationary and in fact they have started showing that sign.

The claim of proper management of economy by the Janata Government does not stand scrutiny because these reserves, along with the money supply, would produce inflationary trends.

The last budget resorted to a disguised method of deficit financing by taking Rs. 80 crores out of the foreign exchange reserves. This time the Finance Minister has already made an announcement of resorting to or utilisation of the foreign exchange reserves. This, in fact, for a student of economics, would mean only deficit financing. The hon. President's claim of proper management of the economy, therefore, is contradicted by this. The best economic manager must work for a model of optimum utilisation of these foreign exchange reserves.

The Indian settlers abroad should not only be persuaded to increase their savings, but they must be persuaded to channel these savings through such investments which must promote such products which will find a market in the countries where they are settled. That would promote an expanding cycle of savings and investment and again greater earnings and investments and so on and so forth. This would be the proper thing to do and this would be helpful in making optimum utilization of the foreign exchange reserves. *(Time bell rings.)* ... Sir, T will just take a few minutes more.

Then, I come to the question of money supply. The honourable President's statement on money supply again is not correct. The calculation of the quantity of money, the percentage worked out by him, has ignored—and purposely not counted—the foreign exchange reserves available.

The Janata Government claims to have inherited an economy in which poverty and unemployment were very acute particularly in the rural areas during the past thirty years and it has not benefited large numbers. This is a very interesting slogan, although many of the stalwarts of the Janata Government today were partners in the game of the previous Congress governments during the last thirty years. Well, it is never too late to realise a mistake. Let us wish and hope that the oriented strategy of development, as mentioned by the President, is worked out in the Janata laboratories and that we are given a recipe which removes the country's unemployment and under-employment. Another object of the emerging new strategy is also welcome and it is the significant reduction in the disparities in income and wealth. Well, this also appears only to be a slogan. Today, many of my friends have talked of land reforms and the land legislation

[Shri Charanjit Chanana] which is going to come because the rural development schemes unfortunately appear to be going to the benefit cf the landlords only. In fact, it should start with a cost-benefit analysis with the object of giving the maximum benefit to the tiller and not to the landlords only.

SHRI K. K. MADHAVAN: Sir, on a point of submission. Earlier, the honourable Vice-Chairman assured the House that the specified number of minutes would be adhered to.

SHRI CHARANJIT CHANANA; Sir, the honourable President has mentioned the New Industrial Policy. Unfortunately, the industrialists seem to be living in an atmosphere of confusion and uncertainty since, in spite of the announcement, there are many ministerial statements which contradict each other. The public sector seems to have been relegated to the Background. The open letter of Mr. Minoo Masani, one of the Janata rightist stalwart to the Finance Minister, published in "The Indian Express", may be a preamble to the Janata Budget. It is very interesting. He has put before the Finance Minister models of his ambition, the models of Taiwan, Hong Kong and Singapore. These economies, my friends know, are being managed by the western multinationals. Does he and do the rights in the Janata Government plan converting the Indian economy also into an economy mortgaged to the multinationals? How would these leaders of the free trade fit in the integrated rural development schemes? .... *(Time bell rings)* .... Sir, I would conclude the whole thing by just saying that a slogan is very interesting and serves as a useful medium of communication. But *it* you go on giving false slogans, these slogans would not give us anything at all. So, Sir, my submission to the President is that the Janata Government should raise such slogans which they can put into practice. They should convert their slogans into practice and they should mean business. They should start doing the work and put their slogans into practice. Thank you, Sir.

SHRI LAKSHMANA MAHAPA-TRO; Sir, he referred to the Janata laboratory. It is a laboratory with lamps, but without spirit; it is a laboratory where the test-tubes are broken and the crucibles are damaged

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Lakshmanan.

SHRI G. LAKSHMANAN: Mr. De puty Chairman, Sir, I have great plea sure in welcoming the Presidential Address. But I have my own reser vations on certain views expressed by the President of India. Mr. Deputy Chairman, the incident that took place when the President began to deliver his Address was most ugly and it would not be in the interest of the unity of our country. I would like to tell my friends who are having Hindi as their mother-tongue as I have Tamil as my mother-tongue, not to follow this method of forcing the President to speak at least a few words in Hindi. What pleasure do they get? I cannot understand Sir .....

AN HON. MEMBER; Nobody pressed him.

SHRI G. LAKSHMANAN: It has come in the papers.

SEVERAL HON. MEMBERS: No, no.... *(Interruptions).*

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD: When the question of Hindi comes up, do you remember that all the political parties—Janata, Congress and everybody—join together?.. *(Interruptions).* There are no two opinions.

SHRI G. LAKSHMANAN: I am afraid, here in our country there are persons who know Hindi only and who want that only a man who knows Hindi can become the President of India, and that a Tamilian or a man from Andhra or Karnataka cannot become the President of India. There-

lore, Sir, the Janata Government should take note of it. I would demand of this Government this assurance. The assurances given by the late Prime Minister, by the late, lamented leader, Jawaharlal Nehru, have been flouted during the Presidential Address. Therefore, I demand of this Government to give a constitutional guarantee to the non-Hindi speaking people. There should be a constitutional amendment that English shall continue to be an official language in India... (Interruptions).. that English shall continue to be an official language of India, even if a single citizen of India wants it,

SEVERAL HON. MEMBERS; No, no...

(Interruptions)

SHRI G. LAKSHMANAN; We all agree on that point. We are a member of the Commonwealth. Even today our nation is a member of the Commonwealth. In which language did Mahatmaji speak when he went to the U.K. to get independence for this country? And what is this fanaticism against English? Sir, my friends will not agree, but the fact is that we have been made civilised people only because of English language. I am not afraid of making this statement. If you thrust Hindi on these people, I am afraid the unity of India will be jeopardised. In the larger interests of the nation, I would make a personal appeal to all my friends. Nobody can ask us to go out of India, nor are we prepared to go out of India. If you continue this behaviour of imposing Hindi on the non-Hindi-speaking people, what is taking place in Cuba, in Canada, in the U.K., in Scotland, etc. will be repeated here ilso. Language is a sensitive subject. t know, Sir, that the Government of tadia is every year spending not less lhan Rs. 100 crores on the propagation of Hindi. I was going through t pamphlet issued by the Government 9f India and I found that so many 'lasses were going on, *30* many teachers were engaged and conveyance charges were being paid. So...

(Interruptions).

SHRI K. K. MADHAVAN: In Hindi they have only one word for 'yesterday' and 'tomorrow'—not different words...

(Interruptions).

SHRI G. LAKSHMANAN: The money that the Government of India gets is the money of the peasants of Tamil Nadu and of the tax-payers throughout the country. How can they spend that money only on a particular language? Therefore, I would demand of this Government to-give us a constitutional guarantee or else you would be responsible for sponsoring agitations.

AN HON. MEMBER: No.

SHRI G. LAKSHMANAN: Definitely. If Vou do not want it, please stop this fanaticism. What is English? English was the language of the ruling class when the English ruled us. Now English is our servant. You must understand this. Why are you so fanatic and prejudiced against that language? What is our international link? Our international link is only English. When Shri Morarji Desai speaks here, he speaks in Hindi. Wnen he goes to the U.N.O. or the U.K. or America or to any other country, he speaks English. English is all right there. But in India he speaks Hindi. Though he knows English, you will welcome him if he speaks Hindi. Therefore, English cannot be separated from this country. It is in the interest of our national integration and unity of this country that English shall have to continue. That is why, Shri Jawaharlal Nehru gave an assurance that English shall continue to be the official language till the non-Hindi speaking people want to change it. Now, I am not satisfied with that assurance. That assurance is being flouted perhaps because some other party has come to power. Therefore, Sir, I want a constitutional guarantee.

[Shri G. Lakshmanan]

That assurance of Shri Jawaharlal Nehru should be incorporated in the Constitution. The constitutional amendment should be brought forward by the Janata Government. There is a feeling in our part that the Janata Government is very much interested in imposing Hindi on the non-Hindi speaking people. At least, in order to save themselves from political attack by the Congress friends, I would ask the Janata Government to bring in a constitutional amendment saying that English shall continue to be used in this country as long as the non-Hindi speaking people require it

There is another very important thing. I am speaking on the President's Address. My lady colleague and my other colleagues alio spoke. This opportunity has been denied to the people of Tamil Nadu. When the Assembly started on the 20th itself, the Governor's Address which gives out the policy of the Government has been denied to the people of Tamil Nadu.

SHRI U. R. KRISHNAN (Tamil Nadu): It is not so, Sir. There are precedents to that effect.

SHRI G. LAKSHMANAN: Sir, here my lady friend spoke on what the President spoke. That right and privilege has been denied to the people of Tamil Nadu. It is not a party issue. It is an issue based on democracy. It is a constitutional right of the people of Tamil Nadu to have the Governor's Address. Now, we are speaking on the President's Address. *(Interruptions)* Mr. Krishnan, I am only telling them that this is what has happened. If we are the ruling party there, you will not leave us for any procedural defect which you find in us. We have got to express it. *(Interruptions)* You can speak if you want to speak afterwards. *(Interruptions)* I am only telling the fact. Sir, I do not know why such a great man, the Chief Minister *o'* T L^{V} •] !^{T}a hi, works against the democratic traditions of our country and the people of Tamil Nadu. *(Interruptions)* Sir, you are presiding over this House and the President's Address is being discussed here. That right has been denied there_____

SHRI U. R. KRISHNAN: Sir, it ia not correct. I protest against this.

SHRI G. LAKSHMANAN; Sir, this is Council of States. Whatever happens in the State, I must place it before this House.

SHRI U. R. KRISHNAN: Sir, I protest.

SHRI G. LAKSHMANAN: Your protest will be recorded and your Chief Minister will know it. Your protest is also being recorded. Sir, I may tell you that in the State of Tamil Nadu, after that great democratic leader became the Chief Minister, this right has been denied. This has to be noted by this House.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD: May I ask one question? May I know the reason why the Governor's Ad-drsss was suspesded? Was it because the Governor was not in a positio:i to address in Tamil? Or, was there any other reason?

SHRI G. LAKSHMANAN: There ar$_{e}$ some other reasons. That reason is not correct. Sir, in the Budget Session, the policy and programme is to be given by the Governor. What are we discussing now? We are discussing whatever that is going to come up here before us.

Sir, there is one significant omission in the Presidential Address. Our Congress friends here have been saying that in one year nothing has been done and that it is going to be fought in the str3ets and all that. I would ask them: What was the position when they handed over the Government to the Janata Party? Sir, 70 per cent of the poou^tion was below the poverty line. Sir, Rs. 6,000 crores were in the hands of bio monopoly interests as black money, according to the Wan-

choo Committee Report. About 125 families were controlling the economy of the country. In such a condition, Mrs. Gandhi handed over the charge. Of course, she did not handed over. She was defeated because of these actions. Therefore, Sir, in such a condition, Mr. Morarji Desai has taken charge of the new Government. When that is the position, I would only ask my Congress friends one thing. What all they have done during this one year may not be suitable to you, may not be palatable to you. But still you have got to consider what they have done in the past one year. The main thing that they have done is that they restored democracy to the people of India which you failed to do. Hats off to the Janata Government and the Janata leaders who have restored democracy to the people of India. Therefore, Sir, if our Congress friends say that they have not done anything so far.... (Interruptions)

SHRI KALP NATH RAI; **What** has the Corigress said?

SHRI G. LAKSHMANAN: **You** all say that they have done nothing and there is nothing in the Presidential Address.

Therefore, Sir, in such a condition, they handed over the Government to the new Party, to Mr. Morarji Desai, and they in their own way are trying to do something. And those things have been mentioned by the President in the form of a Presidential Address. Sir, according to 5 P.M. me, the greatest omission in the Presidential Address is the absence of any mention as to how Government is going to solve the unemployment problem in this country. (Interruptions). Please do not interrupt me like this. Otherwise I will take more time. Labour is wealth in any country. But labour in this country is sitting idle. Whatever plans you may have and whatever programmes you may have, you cannot succeed because whatever is being earned through labour, js being eaten away by those people who **are** unemployed. To give you an example, if in a family of five members only two are earning and the other three are unemployed, the earnings of the two people will also have to support the three who are not earning anything. The two earning people will alsG have to feed the three who are unV employed and that family cannot therefore prosper. Such a situation, unfortunately, is in existence in our country. Therfore, Sir, this unemployment problem should be solved. You may have your own policies regarding looking after the village sector or cottage industries sector and all those things, but the main thing that has to be done in this country is that employment has got to be provided to those people who are prepared to work and earn wealth for this country. No point has been made by the President regarding this aspect of the matter. I hope this thing will be noted by the ruling party.

Then, Sir, what is the defect with the economy of this country? Sir, I will give you one instance. Today-ever silver is being imported in this country. But do you know who is having the permits for its import? Those who do not do anything with that ever sit ver have the permits. Thousands of permit holders are there in ever-silver and they stock it and they make utensils out of it and they sell them at their own prices. Who are these permit-holders? These permit-holders are those people who pay huge sums of money to the party funds of any party.

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: To which party?

(Interruptions)

SHRI G. LAKSHMANAN: Have it as it suits you. I have not mentioned any party.

You know kerosene is being distributed through Indian Oil. But all big business magnates are still doing b'ack market in it and in this way black-money is being generated. Indian Oil

LShri G. Lakshmanan]

is a public sector undertaking and the distribution of kerosene is in the hands of big business magnates and monopoly capitalists. In iron and steei, cement, and other things who are the distributing ageVicies? The distributing agencies are monopoly interests, capitalists and vested interests. Therefore, I would suggest through you to this House, Sir, that all this distribution should be done through a public distribution system. To give you an example how this can be done I say that all the people living in a district, including peasants and other people, should purchase a share of Rs. 10 each and thus establish a company. The capital of the company thus raised may be Rs. 20 lakhs or Rs. 50 lakhs. That company should directly purchase from the producers whatever is needed for the people and that company alone should distribute it to the people without the interference of any middleman.

SHRI HAMID AL1 SCHAMNAD: Just like co-operative societies.

SHRI G. LAKSHMANAN: They are not able to do it. I want to take in all the people. You know the Hindustan Lever produces a lot of things and it is going on accumulating its wealth. What has happened to Tatas? Before independence, their wealth was only Rs. 100 crores; now it is Rs. 1,000 crores in spite of the income tax, the wealth tax and all that. How this money has come? It is because the public distribution system is not being followed. Therefore, Sir, we can also control the prices....

(Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN; Please wind up.

SHRI G. LAKSHMANAN: There are so many interruptions, Sir.

SHRI HAMID ALI SCHMNAD: He is capable of facing ten people.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That happens with all important people,

SHRI G. LAKSHMANAN; There-tore, unless and until the public distribution system *h* followed, taking the entire population of the country as a whole, we shall not be able to control tne piices. Th* consumers should be made the members of that body responsiDle for the public distribution system within their district. Permits for distribution of kerosene oil etc. saouid be given to them only. Why should you give permits for ever-silver steel to the same people? I know of people who were penniless about five years back, are going on purchasing houses. They have become so rich because of these ever-silver permits. I do not know how they manage with all the income-tax and other taxes. If you are not able to set these things right, definitely you will also go the same way as the Congress went, after five years. Therefore, some revolutionary changes have to be brought about. Revolutionary changes have to be evolved. Unless and until you bring about these revolutionary changes in the country's economy, you cannot control these vested interests. What about these 75 or 100 families which are controlling the economy of the country today? What action has the Janata Government taken against them? What about Tatas and how could they increase their wealth from Rs. 100 crores to Rs. 1,000 crores? Unless you very vehemently take up these matters, you cannot achieve what you want to achieve.

SHRI KALP NATH RAI: What about State autonomy?

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: Now. he will say about Sarkaria Commission.

SHRI G LAKSHMANAN; Yes, we are capable of facing Sarkaria Com mission, not only Sarkaria Commis sion, but even for Mr. M. G. Ramachandran. Don't worry. We are not afraid of any commission. Some other commission is also going to be there fr Mr. M. G. Ramachandran _____ (In terruptions). Because you rfised it, I win have to say that. Sir, before the

elections, he got Rs. 45 lakhs from Mrs. Indira Gandhi and you know, he exchanged_____

(Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN; Order please.

SHRI G. LAKSHMANAN: Because you are bringing in Sarkaria Commis sion, I have to say this. He got Rs. 45 lakhs from Mrs. Indira Gandhi. time he was not the Chief Minister. Then he exchanged the cheque of Rs. 25 lakhs with cash, and Rs. 20 lakhs in thousand-rupee currency notes were changed in a bank in Madras. I can even name the bank. (Interruptions). All those things are under the CBi Therefore, you dnn't worry.... (In terruptions). She I did not want to mention all these things ----------

(Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order please. Don't interrupt the hon Member.

SHRI KALP NATH RAI: Give the name of the bank.

SHRI G. LAKSHMANAN: I am happy, he mentioned Sarkaria Commission ....

SHRI KALP NATH RAI: Give the name of the bank.

SHRI G. LAKSHMANAN: You can come to me and I will tell you the name.

SHRI U. R. KRISHNAN; You are an expert in changing hundred rupee notes.

SHRI G. LAKSHMANAN: Not only hundred rupee notes, even thousand rupee notes, Mr. M. G. Ramachandran is capable of changing. Could he not change hundred rupee notes?

Now, Sir, I would like to say some thing about State autonomy. I have no time, but still, I would mention one point. In regard to State autonomy, there is a national debate going on in this country today whether the Prime Minister accepts it or not. Our President also said something about State autonomy to 'Link'. How is it that hot even a single sentence has ap peared in the President's Address? When Shrimati Indira Gan dhi was the Prime Minister, whenever any policy decision was opposed by her, nobody raised that subject inclu ding Dr. Zakir Hussain. Likewise, is it a fact that Mr. Sanjiva Reddy, having known the view of the Prime Mini ster on the subject of Centre-State re lations, did not touch it? This is my do'ibt. Mr. Sanjiva Reddy may not have done like that. Of course, the President's Address is prepared by the Cabinet and, therefore, they have not mentioned it. But stffli Mr. San jiva Reddy should have insisted that Centre-State relations should also find a place. We should discuss it and set tle it through a national debate. This is an omission in the President's Ad dress. Sir you have already rung the bell. Mr. Kalp Nath Rai had a Plan not to allow me to speak because I am .speaking in English. Thank you.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): Mr. Deputy Chairman, Sir, the President's Address shoul ' n it only be a corerct balance-sheet of the performance of the Janata Party Government, in the political and economic sphere, but it should also be a pointer to the direction in which the country will progress. Judged by that standard, his Address to both the Houses of Parliament this year is more or less ritualistic and colourless. The very fact that as many as 262 amendments have been moved to the Motion of Thanks highlighting some of the very basic and major problems which the President has conveniently ignored, is proof of the lack of such requirements. Naturally, Sir, this has caused disappointment amongst all sections except the ruling Party. Sir, we were keenly expecting to know how this Government proposes to curb the in-flationary pressures and tackle the problem of unemployment. We also wanted to know how this Government will create a suitable climate for good industrial relations and promote production and economic

[Shri Narasingha Prasad Nanda]

growth. We also wanted to know what steps this Government will take to bridge the domestic savings-investment gap. But we regret to say that the President's Address is significantly silent on all these very important aspects. The Members who have participated earlier in this debate have covered various points. I would not tread the beaten path and repeat the same points. I would refer to a very important aspect about which I have given some serious thought. Apparently, the President has expressed no concern about certain dark forces affecting national integration. After all, we are a nation first and then anything else. Only yesterday in this very august House an hon. Member was talking of India being a country of many nations. Another Member was arguing with vehemence that there is a lack of integration from heart. Yet a third Member was referring to the intolerance exhibited by the dominant language group in this House. And you find, Sir, the repetition of the same thing today also. A political section in this country in the garb of a cultural movement speaks of its dream of a Hindu India, not satisfied with Secular India. Sir, we are now witnessing politics of the worst type— *Aya Rams and Gaya Rams.* Whatever be the claim of the Janata Government, it is essentially a party of the Hindi hinterland, with most of its members drawn from rich peasantry, headed by Sardar Charan Singh.

AN HON. MEMBER: Choudhury Charaia Singh.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: No, I say: Sardar Charan Singh. It is a meaningful statement. Industry and commerce, urban elites, full of vested interest, believing in, what is known in political parlance, *status quoism. In* the North-West, *extreme* South and Eastern region we have legional parties. Divisive political under-current is discernible mostly in the North-Eastern reeion of this country which may eventually prove dangerous to the integrity of the country. This uncertainty and instability is taking place in a very subtle way, with a free-for-all atmosphere all round.

The President's Address exudes, complacency and does not take note of some of the serious developments that ar$_e$ taki'ag place in the Indian politics. Government should take care to nip in the bud all such fissiparous tendencies before they assume enormous proportion.

Another important aspect which I would like t$_0$ mention is th$_e$ very attitude of this Government, the psychological attitude of this Government, the approach of this Government primarily. I do not say that they are doing nothing, but primarily and basically they ar$_e$ hurrying themselves in th$_e$ past, beginning $_w$ith the digging of the time capsul$_e$ and through commissions they are trying to judge the acts and omissions of the past Government, completely unconcerned with the present and totally lacking the vision of the future. By now, Sir i£ I am correct, we have already 48 to 50 Commissions and the estimated cost of these Commissions will nfti into crores of rupees.

एक माननीय सदस्य : अभी और बनने हैं ।

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: Sir, after all, this Government will be judged by its own performance and not merely on the basis of the exposure of certain failures of the past Government. How long will they use such things of the past Gov-ernment as a weapon in their hand without having regard to the present or to the future? How long this counter-productive exercise will continue t$_0$ be carried on at the cost of public exchequer is a question which is troubling every body's mind. I have my own doubts

about the wisdom of such a counter-productive exercise.

Another thing I would lik$_e$ to poi'nt out is the style of functioning which is very peculiar to this Government— i.e. setting up of committees or commissions. You know very well that in Great Britain whenever public opinion mounts against a particular policy of th$_e$ Government, the Government sets up a committee $_a$nd uses it as an umbrella against the mounting public opinion. And only status qiioist governments can take that step. The present Government have succeeded in setting up committees only. If the question of public distribution system i$_s$ there, set up a committee to go into the question o* controls and regulations. The committee will take its own time and th$_e$ Janata Party's lifetime will be over. So they will have 'n$_0$ problem regarding controls and regulations.

SHRI PATITPABAN PRADHAN: It is not so.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: That is not desirable. I seek your protection, Sir. What is this? This is Elders' House. I would expect the Members to listen to me. I do not expect every body to agree with me. I must $_s$peak $_0$ut what I feel about these things.

Sir, there is labour unrest from one end of the country to the other. Mr. R. K. Mishra referred to this labour unrest. And what did the present Government do? They set up the Bhoothalingam Committee—the ghost committee—for setting out the income, prices and wages policy which they will follow. God knows when that ghost committee will submit its report and the Government of India will act on it.

We find that the atrocities on Hari-jans are mounting every day. We are getting reports of atrocities on Hari-jans. This is more due to loss of confidence in the present leadership and the growth of the feudal attitude of the rich peasantry in the rural areas. Now what have they done? They just set up three Commissions—Minorities Commission, the Backward Classes Commission and the Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. You will kindly see that the whole style of functioning of the Government is that v/henever you raise a question, they do not take any decision immediately. The only decision they take is to set up a commission. Then, they have also set up a Police Commission. I do not want to enumerate all these commissions, but the whole style of functioning is to postpone any effective decision on major burning issues of the day. This is the approach of the Government, this is the style of functioning of this Government.

So far as the economic aspect is concerned—kindly permit me to conclude in two minutes—I would not mind the President giving a good certificate, a good chit to the present Government for its political acrobatics. But in the economic field,, it is a total failure. Dr. Chanana, who is an economist, has already analysed the expected growth rate of 5 per cent and showed how incorrect it is. He has also analysed how unsound the money supply policy is and whether the national income has really increased. He has also analysed certain other important aspects.

I am not going into these details. But their own Finance Minister said how the country is progressing. What is the growth? We must kviow about our domestic savings and we must know how much we have invested. What is the investment during the last year? While participating in an international seminar of economic journalists, their Fittance Minister, Mr. Patel, said that the static investment trend was puzzling him and said that the reasons were somewhat deeper. He says that they have removed

[Shri Narasingha Prasad Nanda]

all the constraints but even then the investment is not forthcoming. The reason, I submit, is the uncertainty of the mind of the present Government about the direction in which they will take thi$_s$ country. The President himself in the concluding paragraph 28 says:

> "Hon'ble Members during this Session you have to consider the statement of Receipts and Expenditure and the Demands for Grants for the coming financial year which will determine the new direction in which the country will progress in the comiVig years."

The President is also kept in the dark about the direction in which the coun. try will progress in the coming years. W$_e$ will have to wait for th$_e$ receipts and expenditure which will be placed by the Finance Minister before the Parliament. Till then w$_e$ must be kept in dark. Therefore, this Government, in order to justify jt$_s$ existence must take decisions which would remove inconsistencies and try to implement the promises which it made to the electorate of this country. I would submit, Sir, that they should try for a healthy, robust and forwardlooking economy and not a static economy trying to take back the wheels of progress of this country by twenty five or thirty years.

श्री सीताराम केसरी : महोदय, सारे देश के सामने जनता पार्टी लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में पैदा हुई और आप जानते हैं कि.....

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : लोक नायक या लोकनायक ?

श्री सीताराम केसरी : नहीं, लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जनता पार्टी पैदा हुई और उन्होंने अपने आन्दोलन में तीन मुद्दे दिये थे । पहला भ्रष्टाचार उन्मूलन, दूसरा शैक्षणिक सुधार और तीसरे बिहार असेम्बली का विघटन । जहां तक बिहार असेम्बली के विघटन का प्रश्न है वह तो पूर्ण हो गया मगर लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जो जनता पार्टी की सरकार इस देश में आयी क्या वह लोकनायक के किसी अन्य मुद्दे को पूरा कर सकी ? जो उन का मकसद था क्या उस को यह पूरा कर सकी ? नहीं । आज सारे देश से देखिये कि भ्रष्टाचार किस तरह से बढ़ रहा है । सरकार से लगा कर जनता में और उद्योगपतियों के बीच में यह ब्लैक मार्केट के रूप में किस तरह से छा गया है । जितने जबरदस्त ढंग से भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था उतने ही जोर से जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद देश में करप्शन बढ़ रहा है और सारे देश में करप्शन फैल गया है । दुःख की बात यह है कि सरकार के जो गृह मंत्री हैं वह लौह पुरुष माने जाते हैं .....

(Interruptions)

श्री कल्पनाथ राय : क्या ?

श्री सीताराम केसरी : उन को लौह पुरुष कहा जाता है मगर मैं आप से कहता हूं कि आज क्या दिल्ली में शान्ति है ? क्या दिल्ली में अराजकता नहीं फैल रही है ? क्या आपको पता है कि एक रात को भारत सरकार के मंत्रालय के सेक्रेटरी श्री आर० पी० नायक को पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया और आधे घंटे तक रखा जब कि सरकारी कार पर वह जा रहे थे और उन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड भी दिखलाया कि भारत सरकार के टूरिज्म विभाग का मैं सेक्रेटरी हूं पर उन्हें गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने मिस्टर बोहरा की गिरफ्तारी पर प्रोटेस्ट किया था । यह तो सरकार का सब से बड़ा तरीका है कि किस तरह से अफसरों को डेमोरेलाइज करके

सच्ची बातों को छिपाये रखना चाहती है । इसलिए उपसभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो रास्ता अपनाया जा रहा है, जो भी उस रास्ते पर जाता है न जाने क्यों वह पागल हो जाता है । नतीजा क्या होता है कि करप्शन बढ़ता है ।

आपने करप्शन की सफाई में पूर्व सरकार को कहा कि वह हार गयी । तो आप भी नाश हो जाओगे । अगर मेरी गलती पर आप आये हैं तो वही गलती आप दिखलाते हैं जो कि देश के सामने पूर्व की सरकार ने किया था तो आप भी नहीं रहने वाले हैं । आज ही हमारे गृह मंत्री जी ने 1974 से 1977 तक के क्राइम की लिस्ट पेश की । हमने कहा कि लिस्ट के आधार पर हम हार गये लेकिन आप इस लिस्ट को दिखाकर जिन्दा रहना चाहते हैं तो कैसे रहेंगे, नहीं रह सकते हैं ।

एक बात और कह दूं । अभी कुछ दिन पूर्व इसी सदन में हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि विरोधी दल का कोई मतलब नहीं है । मुझे हंसी आई । इसी तरह से जब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा था कि विरोधी दल का कोई मतलब नहीं है तो नतीजा क्या हुआ कि हम यहां चले आये और आप वहां चले गये । इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस सरकार को भी कि आपका जीवन ज्यादा दिन तक नहीं है ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह चर्चा आई कि विदेशों में भी अशांति फैली हुई है, देश में तो है ही । उसका कारण है । इमरजेंसी के उठने के बाद ये बातें आई कि सभी के मुंह बन्द थे । मगर क्यों आज बातें हो रही हैं ? क्या विगत चुनावों में आनन्द मार्गियों ने इनका समर्थन नहीं किया ? जिस तरह से हम ने आनन्द मार्गियों के खिलाफ कदम उठाये, उनके कुकर्मों पर उन्हें दंड देते रहे, उसी तरह से विरोधी दल के लोगों ने कभी उसकी भर्त्सना नहीं की । वह इनसे अपेक्षा करते थे, उनको भी कुछ आशायें थीं क्योंकि इनका आंतरिक गठबंधन था । यही वजह है कि जब जार्ज फर्नेन्डीज पर से डाइनामाइट केस उठाया जा सकता है तो उनके ऊपर से केस क्यों नहीं उठाया जाए ? मैं उनका समर्थन नहीं करता । लेकिन इनकी सांठगांठ थी । इसलिए विदेशों में हमारे एयर इंडिया के कर्मचारी या हमारे दूतावासों के कर्मचारी लोग उनके आक्रमणों के शिकार बन रहे हैं । इसलिए मैं कहूंगा कि इन सब चीजों पर जिस तरह से अराजकता फैला करके, आन्दोलन करके, दुर्भावना पैदा करके ये सत्ता में आये हैं, मैं कहता हूं कि उन वायदों को पूरा नहीं करेंगे तो इनकी सरकार ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है ।

अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, एक रात में 13–13 डकैती हुई किसी का दो हजार छीन लिया, किसी का 1500 छीन लिया, किसी का 500 छीन लिया । आज आप सड़कों पर देखियेगा, मैं खुद अनुभव करता हूं । मैं पंडारा रोड एबी–2 में रहता हूं । एक दिन मैं रात को अपनी कोठी के अहाते में घूम रहा था । जैसे ही दरवाजे पर कार देखी तो मैंने टोका । फिर वे रुके, फिर वह गाली बकता हुआ आगे चला गया । वह भी राहजनी करने के लिए वहां पर आया था । मैं आपसे कहता हूं कि इन सारी चीजों पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा । प्रतिहिंसा की भावना पर चूंकि जनता सरकार आई है, जिस आधार पर इसका निर्माण हुआ है इसकी सारे देश को जानकारी है, इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार खाली प्रतिहिंसा लेने की भावना में लगी रहेगी तो कोई भी देश का कल्याण नहीं करेगा और जनतंत्र का भी कल्याण नहीं हो सकता । दो चीजें मैं आपको कहता हूं । एक तो यह कि जनता नाम पर जनता पार्टी की फारमेशन हुआ । दूसरी बात जिस दिन

[श्री सीताराम केसरी]

से इन्होंने डेमोक्रेसी की रक्षा के नाम पर और जनतंत्र के नाम पर सत्ता संभाली है उसी दिन से उन्होंने प्रजातंत्र का गला घोंटना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिये मैं आपको बताता हूं कि कर्नाटक की विधान सभा की बैठक अगले दो दिनों में बैठने वाली थी लेकिन असेम्बली उन्होंने डिजोल्व कर दी। क्या बात थी ? दो दिन बाद असेम्बली देख लेते जिसमें ताकत होती वह बना लेता।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : खरीदना शुरू कर दिया था ।

श्री सीताराम केसरी: उपसभापति महोदय, मैं भी उस जगह पर रह चुका हूं। मैं जानता हूं कि आदमी सत्ता में कैसे पागल होता है। जब मैंने कहा कि मैं जय प्रकाश बाबू से बात करना चाहता हूं तो उन्होंने नहीं करने दी। मिनिस्टर लोग इसी से कहते थे कि सी०आई०ए० से जयप्रकाश जी ने 50 करोड़ रुपये लिये हैं। 26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस पर हम से श्री राजनारायण ने पूछा कि तुम्हारे नेता के पास कितनी दौलत है तो मैंने उनको बताया कि उतनी नहीं है जितनी जयप्रकाश के पास थी जब हम पावर में थे। जो पावर में आता है वह पागल हो जाता है। वह समझता है कि विरोधी दल के पास बहुत सी दौलत है। वह यह समझता है कि क्योंकि विरोधी दल के पास कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, इसलिये पैसा ही होता है। सत्ताधारी अपने विरोधियों की उभरती हुई शक्ति को देख नहीं पाते हैं। आप यह जान जाओ कि जनता पार्टी ज्यादा दिन तक ठहरने वाली नहीं है। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि यह 6 महीने से भी ज्यादा ठहरने वाली नहीं है।

एक माननीय सदस्य : किसी ज्योतिषी से पूछ कर आए हैं क्या ?

श्री सीताराम केसरी : मैं ज्योतिषी हूं। मैं राजनीति जानता हूं। कुलदीप नायर ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ आर्टिकल भी गन्दा लिखा था और आज यही इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि मैं साउथ में सभी जगह गया हूं। खेद की बात है कि कहीं भी इमरजैंसी की बातें नहीं हो रही हैं। वह कंडम कर रहे थे। मैं कह रहा था कि कब तक चलता रहेगा। कब तक शाह कमीशन बैठा कर जिन्दा रहेंगे। आप जान जाइये कि गांव-गांव में आपके खिलाफ एक भावना बन रही है। मैं बताना चाहता हूं कि यह देश संतों का है। जिस तरह से जयप्रकाशजी, मोरारजी भाई, चन्द्रशेखरजी को गिरफ्तार करके हम हारे उसी तरह से आप इन्दिरा गांधी को बदनाम करके ज्यादा दिन नहीं ठहर सकते। यह आप निश्चिततः जान जाइये। यह संतों का देश है। आप इतिहास उठा कर देख लीजिए पाटलिपुत्र से कश्मीर घाटी तक जब कभी किसी शासक ने अन्याय किया है तब ही यह हुआ है। आपके साथ भी वही होगा। जब से आप शासन में आए हैं कभी टाइम्स आफ इंडिया के मालिक को लिख रहे हैं, कभी स्टेट्समैन के मालिक को लिख रहे हैं तो कभी हिन्दुस्तान टाइम्स के मालिक को लिख रहे हैं। प्रेस को धमका कर रोब देते हैं।

मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कोका कोला क्यों बन्द किया ? इसलिये बन्द किया क्योंकि आपने 50 लाख रुपये से ऊपर लिम्का वालों से चन्दा लिया एक तरफ आपने कोका कोला बन्द किया और दूसरी तरफ अमरीका से बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को बुला कर बात कर रहे हैं और तीसरी तरफ आप तीन बिलियन डालर के इन्वेस्टमैंट की पश्चिमी जर्मनी से बात कर रहे हैं। क्यों ? क्या गलत बात है कि बिना चन्दा इकट्ठा किये आप जीत कर चले आए ? क्या यह सच नहीं है कि पिछले असेम्बलियों के चुनाव में आपने तीन करोड़ रुपये इकट्ठे किये ? क्या यह सच नहीं है कि सेठों से 50 लाख रुपये लेकर उनको छोड़ दिया आपने उन्हें इसलिये गिरफ्तार किया था कि आप उनसे

रुपये लें और आपने सभी बड़े उद्योगपतियों से लिया। यह कब तक चलेगा ? यह बन्द कीजिये । इससे इतिहास की पुनरावृत्ति होती है । जिन गलतियों के लिए हम हारे हैं वे ही गलतियां आप कर रहे हैं । इसी तरह से आप भी चले जायेंगे ।

आपके द्वारा यह कहा जाता है कि पार्टी का तिरंगा झंडा नहीं रहेगा । मैं पूछता हूं कि आदरणीय मुरारजी भाई क्या उसी सरकार में जिस पार्टी का यह झंडा है उसके उपप्रधान मंत्री नहीं रहे ? क्या इसी झंडे के नीचे आदरणीय जगजीवन बाबू नहीं रहे और क्या इसी झंडे के नीचे आदरणीय चन्द्रशेखर नहीं रहे ? आदरणीय बहुगुणा जी, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी, ये सब लोग पहले कांग्रेस में थे । मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस देश का शासन कांग्रेस के टुकड़े ही चलाएंगे, आप में वह सलाहियत नहीं है । मेरे दोस्तो, आज आप लोग जनतन्त्र में जनता से मत लेकर आए हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आने वाले चार वर्ष तक प्रशासन चलाओ । लेकिन मुझे लगता है कि आप इस देश का प्रशासन नहीं चला पाएंगे । आज देश में यह कहना कि हम उसको गिरफ्तार करेंगे, इसको गिरफ्तार करेंगे, इस तरह से देश का प्रशासन नहीं चलता है । आप एक बार नहीं, अनेक बार लोगों को जेल में भेज दीजिये, लेकिन यह सोच लीजिए कि इसका नतीजा क्या होगा? जो गलतियां हमारी ओर से हुई थीं वही गलतियां आप भी कर रहे हैं ।

मैं एक बात अन्त में और कहना चाहता हूं । जनता पार्टी की सरकार का जब मंत्रि-मंडल बना तो एक दिन आदरणीय श्री अटलबिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि पिछली सरकार ने विदेशों में हमारी प्रतिभा, हमारी प्रतिष्ठा धूमिल बना रखी थी । इसी सदन में उन्होंने यह बात कही और खुद ही उसका उत्तर भी दे दिया और कहा कि खास तौर पर पाकिस्तान में इस प्रकार की भावना फैला रखी थी । उन्होंने कहा कि पहले मैं जनसंघ में था, अब जनसंघ विलीन हो गया है, जनता पार्टी में शामिल हो गया है । उन्हें इस बात को मानना चाहिए कि विदेशों में जनसंघ की प्रतिष्ठा धूमिल थी । अब तो जनता पार्टी बन गई है । मगर साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अब इस देश की वैदेशिक नीति में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वह पश्चिमी राष्ट्रों के कदमों में जाने लगी है । अभी हाल में काठमांडू के अन्दर चीन के वाइस-प्रेजीडेन्ट श्री तेन ने दोस्ती की बात कही है । अमेरिका के राष्ट्रपति भी यहां आए और पिछले दो महीनों के अन्दर अनेक देशों के, खास तौर पर वेस्टर्न कन्ट्रीज के राष्ट्रपति लोग यहां पर आए हैं । इससे साफ पता चलता है कि आपका रुझान किस तरफ जा रहा है ।

अन्त में एक और बात कह कर मैं अपना भाषण खत्म कर देना चाहता हूं । मुझे एक बात का बहुत कष्ट है । इस देश में हम लोग जनतंत्री पद्धतियों के लिए लड़े हैं और हमेशा जनतंत्री भावनाओं का आदर करते रहे हैं । इस देश में जनतंत्र की स्थापना के लिए हम लोग लाखों की संख्या में जेल भी गये हैं । जब कभी सरकार ने कोई गलत काम किया तो उसके विरुद्ध हम लोगों ने प्रदर्शन किया और उनमें भाग लिया था । लेकिन पिछले दिनों जब यहां पर ईरान के शाह आए तो कुछ लोगों ने उस देश में लाखों गिरफ्तार लोगों की बहाली के लिए उनके सामने प्रदर्शन किया और इस बात की मांग की कि ईरान में जनतन्त्र के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनको रिहा किया जाय । लेकिन आपकी सरकार ने उन प्रदर्शनकारियों को जलूस नहीं निकालने दिया और उनको गिरफ्तार कर लिया । किसी भी जनतंत्री देश में इस तरह के प्रदर्शनों की अनुमति होती है ।

[श्री सीताराम केसरी]

अन्त में एक बात मैं और कहना चाहता हूं। हमारे दोस्तों को शायद इस बात से थोड़ा कष्ट भी होगा। एयर इंडिया के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री जे० आर० डी० टाटा को सब लोग जानते हैं। उन्होंने अपने प्रयत्नों से एक छोटी सी संस्था को दुनिया के हवाई मैप में लाकर खड़ा कर दिया। मगर व्यक्तिगत द्वेष के कारण आपने सत्ता में आने के बाद उन को हटा दिया। व्यक्तिगत विद्वेष से शासन में आकर शासन नहीं चलाया जाता है। आप लोगों ने गांधी जी की समाधि पर कसम खाई है, लेकिन आप उस कसम को भूल गये। आपने यह झूठी कसम खाई है। मैं समझता हूं कि यह धोखा और जालसाजी थी। आप लोग जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं और आदरणीय जय प्रकाश नारायण जी की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। आप लोग जब से सत्ता में आए हैं तब से आदरणीय जय प्रकाश जी को भूल गये हैं और उनके आदेश को भी भूल गये हैं, उनके नारे को भी भूल गये हैं, उन के वायदे को भी भूल गये हैं। आपको जय प्रकाश जी का वरिष्ठ व्यक्तित्व मिला और उनके बगल में बैठ कर आपने अपनी सरकार बनाई। लेकिन दोस्तो, इस बात को याद रखिये, आप इस तरह से ज्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रह सकते हैं। जब तक आपकी भावनाएं पवित्र नहीं होंगी तब तक आप ज्यादा दिनों तक प्रशासन नहीं चला सकते हैं। जय हिन्द।

श्रीमती हामिदा हबीबुल्लह (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, अभी हमारे एक आनरेबल मेम्बर ने जिक्र किया कि जनता पार्टी डेमोक्रेसी लेकर आई है। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूं कि क्या जो लूटमार, हरिजनों के साथ बुरा बर्ताव, रेलवे में सबोटाज, कानपुर में लेबरों को महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, इन सब के बाद आप कहेंगे कि भूखे मरो, कत्ल हो जाओ, तुम्हारे बच्चे मर जायेंगे, तुम्हारी जमीन छीनी जायेगी, मगर हम डेमोक्रेसी लाये है, इसका आनंद लो। यह एक लाल की दुखभरी कहानी है। हमने सोचा था कि एक लाल की दुखभरी कहानी के बाद हमें प्रेसिडेन्ट अड्रेस में कुछ ऐसी बातें नजर आयें जिसमें उम्मीद की झलक दिखाई दे। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ जनता पार्टी को वोट दिया था। हमारी भूखी, नंगी और परेशान जनता की, बेशक इम्पलाइमेन्ट और गरीबी की समस्या दूर नहीं हुई थी। उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ जनता पार्टी को वोट दिया। हमने कहा कि जिसका जनता ने वोट दिया है, जिसको गद्दी पर बिठाया है, उसका अधिकार है और हमने सर झुकाकर उसको कबूल किया। हमने कहा कि आइये जनता की मुसीबतों को हल कीजिये। हम इसमें आपकी मदद करेंगे। मगर उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके कि यह जनता पार्टी हमारी गलतियों से सबक सीखती उसने इलेक्शन में हमें भला-बुरा कह कर वोट तो ले लिये मगर उसके बाद वह समझते हैं कि इस मुल्क पर हुकूमत करना सिर्फ इंदिरा गांधी को भला बुरा कहना और कांग्रेस पार्टी को भला बुरा कहना है। आज तक जनता पार्टी ने कोई भी प्रोग्राम नहीं दिया। उन्होंने अपना मैनीफेस्टो दिया। उस मैनीफेस्टो में उन्होंने वायदा किया था और हम समझते हैं कि वह उसे पूरा करेंगे। मगर उपसभापति जी, अब यह साफ जाहिर हो गया है कि बेचारी जनता पार्टी को यह नहीं मालूम कि उसका क्या प्रोग्राम होना चाहिए। एक पार्टी स्वतंत्र पार्टी जो पूंजीपतियों और राजा महाराजाओं को प्रोटेक्ट करने वाली पार्टी इनके साथ है। इसलिये उस पार्टी की धारणायें इसके साथ होना लाजिमी है। दूसरी तरफ मजदूरों और

किसानों का दम भरने वाली पार्टी कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट उनके साथ है। इस तरह एक बिल्कुल लेफ्टिस्ट और दूसरी राइटिस्ट है। एक का मुंह इधर है, दूसरे का मुंह उधर है। कैसे एक रास्ते पर यह पार्टी जा सकती है? इनको रास्ते का पता नहीं था। इस अड्रेस में भी साफ जाहिर है कि कोई रास्ता इनके सामने नहीं है। यह सिर्फ हमारी कमजोरी है कि हमारे से कुछ गलतियां हुई और उसी का ये लोग शोर मचाये हुए हैं। यह समझते हैं कि इस बात को जनता हमेशा याद रखती जायेगी। इनका न कोई मकसद है, न कोई मंजिल है न कोई रास्ता है। जनता की तरफ से यह आवाज आती है। मैं चाहूंगी कि एक दो भाई जो जनता पार्टी की तरफ से यहां बैठे हुए है, वह सुनें। अपनी गलतियां, अपना क्रिटिसिज्म भी सुनिये। जनता आपके बारे में क्या कहती है :

जिसके आने की गुलशन में धूम थी,
वह बहार आते-आते कहां रह गयी।

उपसभापति महोदय, हरिजनों के साथ जो जुल्म जबर्दस्ती हो रही है, उसके बारे में बहुत से सदस्यों ने यहां पर बताया। मैं उसको बार-बार क्या दोहराऊं? हरिजनों के पास जो जमीन थी वह उनसे छीनी जा रही है। यह क्यों हो रहा है? यह इसलिये कि आप लोगों को लेंड रिफार्म से कोई मतलब नहीं है, आप लैंड रिफार्म की बात नहीं करते हैं। जब आप लैंड रिफार्म की बात नहीं करेंगे तो रूरल एरियाज में तरक्की कैसे होगी। जब लैंड रिफार्म की बात नहीं हुई तभी बड़े-बड़े जमींदार जमीन छीन रहे हैं और वे लैंड-लेस गरीब हरिजन की जमीन वापस ले रहे हैं। सब जगह इस तरह जमीन को वापस लिया जा रहा है। मैं यह नहीं कहती कि कांग्रेस पार्टी ने सब लैंड-लेस हरिजनों को जमीन दी थी। मगर जितनों को दी थी, उनसे भी वापस ली जा रही है। आपको मालूम है कि जिस वक्त आपकी हुकूमत पावर में आई, उस वक्त बड़े-बड़े जमींदारों, यह कहा कि अब जनता पार्टी आ गई है अब हम आजाद हैं। आप आजादी की बहुत बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सब गड़बड़ करने वालों, लूटमार करने वालों और स्मगलर्स, सबको आजादी मिल गई है। जितना चाहो गड़बड़ करो, जितना चाहो रेलों में तोड़-फोड़ करो, जितना चाहो कालेज और स्कूलों में हड़ताल कराओ, जितना चाहो लेबर को मुसीबत में डालो तथा फैक्टरीज को बन्द करो। यह आजादी मिली है। आजादी अगर भूख और गरीबी से मिलती तो तब उसे आजादी कहा जा सकता था। क्या यह आजादी गरीबों को मुसीबत देने के लिये मिली है? आपने हर चीज के लिए एक कमीशन तो जरूर बना दिया। आपके पास तो हर एक मर्ज की एक ही दवा है और वह है कमीशन। आप देखिए एक माइनारिटीज कमीशन बन गया है। मैं पूछना चाहती हूं कि मेरे इधर बैठे हुए साथी यह बतायें कि माइनोरिटीज की मुश्किलात क्या है? क्या उनकी भी मुसीबत यही गरीबी, बेरोजगारी वाली मुसीबतें नहीं हैं? उनकी मुसीबतें जरा ज्यादा हैं। उनकी मदद करने वाले कम हैं। माइनारिटीज की मुसीबतें असल में हैव और हैव नाट्स वाली मुसीबतें हैं। आपने माइनारिटीज कमीशन का सदर किस को बनाया है? वह पूंजीपतियों का लीडर, वह स्वतंत्र पार्टी का लीडर जिसने हमेशा बैंक नेशनलाइजेशन की मुखालफत की, जो पूंजीपतियों और राजा-महाराजाओं का नेता रहा। उनको क्या पता कि गरीब आदमी को गरीबी और मुसीबत क्या होती है। उसको क्या पता कि माइनारिटीज की मुसीबत क्या है। आप लोगों को दूर नहीं जाना पड़ता। अगर माइनारिटीज की असली मुसीबतें आप समझना चाहें तो उत्तर प्रदेश की तरफ देख लीजिये। वहां माइनारटीज में 80 फीसदी बुनकरों की कम्युनिटी है। इन बुनकरों को आज आप इतनी मुसीबतों में डाले हुए हैं। सूत महंगा है। बुनकर सूत ले कर किसी तरह कपड़ा

[श्रीमती हामिदा हबीबुल्लह]

बुनता है, उसके लिए निकास का कोई प्रबंध नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा बड़े-बड़े बंडल बांधे हुए सिर पर रख कर दिन रात चक्कर लगाते रहते हैं चाहे पानी हो, चाहे आंधी हो। अगर बिक गया तो ठीक, नहीं तो घर आ कर फाके करो। यह है आपकी माइनारिटीज कम्युनिटी के साथ हमदर्दी। भूखे रहो, नंगे रहो। ठीक है कमीशन को खाओ और कमीशन से ही घर बन जायेगा। कमीशन बना दिया है। यह मांग माइनारटीज कम्युनिटीज की तरफ से बराबर रही है कि उर्दू को सैकेंड आफिशियल लेंगुएज बनाया जाये। उर्दू की बाबत बहुत सारी बातें हुईं। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं। उर्दू को सैकेंड आफिशियल लैंगुएज बनाने की मांग क्यों की गई है। इसलिए कि उससे रोजी-रोटी का सवाल जुड़ जाता है। अगर आफिशियल लैंगुएज बन जाती हैं तो हमारे हिन्दू और मुसलमान बच्चे सब एक साथ एक हद तक पढ़ेंगे। आफिशियल लैंगुएज हमारी हिन्दी है। अगर सेकेंड आफिशियल लैंगुएज उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में उर्दू को बना दिया जाता है तो हिन्दू मुसलमान भाई सभी बच्चे पढ़ेंगे और नौकरी में कोई फरक नहीं रहेगा। इस तरह से उनकी भावनाएं उर्दू के साथ जुड़ी हुई हैं। उर्दू पढ़ने वाले बच्चे का कोई ठिकाना नहीं है। अगर उर्दू उसको आती है न उसको रोजी मिलती है न रोटी मिलती है। लेकिन मांग की जा रही है इंटीग्रेशन के लिये, दोस्ती के लिए, मुहब्बत के लिए, इसीलिए यह मांग की जा रही है। इन मांगों के साथ बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आज उर्दू के बारे में इस किस्म के तकलीफदेह ऐलानात उन मिनिटर्स की तरफ से होते हैं जो बेहद उम्दा उर्दू बोलते हैं। वे कहते हैं उर्दू तुर्की से आई यहां उर्दू बोलना नहीं चाहते, सुनते भी नहीं हैं। कभी कुछ कह देते हैं। क्या इस तरह से आप माइनारिटीज के दिलों को मोह लेंगे ? क्या कमीशन बना कर आप उनके दिल बहलायेंगे ? क्या राजा रानी की कहानियों की तरह से दिल बहला देंगे ? उपसभापति महोदय, यह रोजी रोटी के मामलात हैं ? यह इकोनोमी के मामले हैं। इस प्रकार से जनता पार्टी समाजवाद की तरफ नहीं बढ़ेगी। इस तरह से हर एक के लिए रोजी-रोटी का इंतजाम नहीं करेंगे तो मेरा यह कहना है कि आप चले जाएंगे, आपकी सरकार खत्म होगी। आपकी सरकार के खतम होने से मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा। मगर यह मुल्क मेरा है, यह बच्चे मेरे हैं, यह देश अपना है। आइंदा दिन जो आ रहे हैं, अगर आप इस बरबादी में हमको डालते हैं तो हम सब को मुसीबत आएगी चाहे आप इधर बैठें या उधर बैठें हमारा देश है, इसको तरक्की करनी चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए मगर आप इसको मुसीबत में डाले हुए हैं क्योंकि आपका एक ही प्रोग्राम है और वह है कमीशन बिठाओ, लोगों के ऊपर एतराज करो, कुछ भी गवर्नमेंट को बुरा भला कहो सब मसले हल हो जायेंगे।

उपसभापति महोदय, अभी एक भाई ने यहां कहा कि 'लेबर इज वैल्थ फार दी कन्ट्री' आपने देखा कि कानपुर में जो स्वदेशी मिल है बराबर वहां पर लेबर के साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है। मैं कानपुर से बहुत नजदीक रहती हूं मैं अक्सर वहां जाती रहती हूं। महीनों वहां के लेबरों को तनख्वाह नहीं मिलती है अगर वे आवाज उठाते हैं तो जेलों में भर दिये जाते हैं। गोलियां इस तरह चल रही हैं कि पुलिस ने हर जगह गोली चलाना शुरू कर दिया है। कहीं वह लेबर के ऊपर चलाती हैं, कहीं स्टूडेंट्स के ऊपर। अभी बाराबंकी में ही कुछ स्टूडेंट्स ने गड़बड़ किया और पुलिस ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। एक बच्ची छत पर खड़ी हुई थी देखने के लिए एक गोली उसको लगी और वह मर गयी। यह कौन सा तरीका है ? इस तरह से स्टूडेंट्स के साथ क्यों बर्ताव हो रहा है ? यह आपको क्या हो गया है ? आप

लोगों का क्यों नहीं यहां कन्ट्रोल रहा है । मैं इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव कमेटी में भी हूं वहां भी हलचल मची हुई है । यूनिवर्सिटियां बन्द हो रही हैं, पढ़ाई खत्म हो रही है, कोई डिसीप्लन नहीं रहा है । थोड़े से लड़के अगर गड़बड़ी करते हैं तो सब के ऊपर मुसीबत आ जाती है । सबकी तालीम खत्म हो जाती है, यूनिवर्सिटी बन्द हो जाती है । आपका कोई कन्ट्रोल नहीं है । न आप डिसीप्लन दे सकते हैं और न इम्प्लायमेंट । फिर मेरी समझ में नहीं आता है कि आप क्या दे सकते हैं ? टीचर्स वाले मामले में क्या हुआ था, टीचर्स को कितनी सजाएं हुई, वे अपनी मांग मांग रहे थे, जायज मांगें मांग रहे थे । मगर उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं था । हर वक्त उनको सजाएं देंगे, दूसरे आदमी रख लेंगे, नौकरी से निकाल देंगे इस तरह कहा जाता रहा । डराना धमकाना कोई बात नहीं है । क्या सिर्फ डराने धमकाने के लिए ही जनता ने आपको वोट दिये थे । उनकी कितनी उम्मीदें थीं ? आज स्टूडेंट्स धमकाये जा रहे हैं, लेबर धमकायी जा रही है । सुनते हैं मीसा को खत्म करके एक और कानून लादा जायेगा जो उससे ज्यादा खतरनाक होगा । हम बच्चे नहीं हैं जो बहल जायेंगे । क्या आप इस तरह से कानून लायेंगे, जबर्दस्ती करेंगे और सब चीजें बन्द करेंगे । आप कहते हैं, मुझे मालूम है बराबर कहा गया है कि यह तो स्टेट सब्जैक्ट है । अगर ला एंड आर्डर यू० पी० में खराब है तो यू० पी० में जाकर पूछो । यू० पी० में आपकी जनता सरकार है इसके अलावा तमाम नादर्न स्टेट्स में आपकी सरकार है फिर क्यों नहीं आप इंतजाम करते कि आपके और उनके बीच कुछ बात हो । उनको कंट्रोल करने की यदि आप जरूरत नहीं समझते हैं तो फिर आप क्यों कहते हैं कि सब जगह हमारा रूल हो । आप क्यों कोशिश करते हैं कि साउथ में भी हमारा रूल हो जाये । जब आप कन्ट्रोल नहीं कर पाते हैं, कोई काम नहीं कर पाते हैं तब आपका स्टेट्स में कोई मतलब नहीं है, क्यों आप वहां अपनी गवर्नमेंट चाहते हैं ?

आप दिल्ली नहीं देख पाते हैं । दिल्ली में रोजाना कत्ल गारद हो रहे हैं आप उनको भी नहीं देख सकते हैं । लेकिन आप यह याद रखते हैं कि पिछले 30 साल में कुछ भी नहीं हुआ । मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि सारी दुनियां यह कबूल करती है कि सन् 1947 में भारत में एक सुई भी नहीं बनती थी और आज कोई चीज नहीं है जो इस मुल्क में न बनती हो । इस तरह से आप यदि करेंगे कि कई अच्छे काम हुए हैं और जो गलत काम हुए हैं बेशक आप उनको बुरा कहिए और कोशिश कीजिए फिर न दोहराने की । आप हमारा कोआपरेशन चाहते हैं । हम लोग भी चाहते हैं कि अपोजीशन की तरफ से आपको कन्स्ट्रक्टिव सुझाव मिलें । हम भी चाहते हैं कि मुल्क सुखी हो चाहे आपके ही रूल में सुखी हो जनता आराम और चैन से रहे, हमारे भाई बहिन सुखी हों । मगर यह भी कोई तरीका है कोआपरेशन लेने का कि हमारा कोई सुनने वाला ही नहीं है । जबर्दस्ती हम बैठे हुए हैं । उपसभापति महोदय, मुझे एतराज है इसके ऊपर कि यहां पर कोई मिनिस्टर इत्यादि सुनने वाला नहीं है । आप हमें बरबादी की तरफ ले जा रहे हैं । मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि "अपनी बरबादी का अफसाना न सुनिये मुझसे, अपनी बरबादी का अफसाना न सुनिये मुझसे, इसमें कुछ आपके एहबाब के नाम आते हैं" अगर हमसे मदद लेनी है तो कान खोल कर हमारे एतराजात सुनिये ।

6 P.M.

हम फैक्ट्स एंड फीगर्स आपके सामने लाए हैं और इसलिए लाए हैं कि हमारे मुल्क के रहने वाले हमारे भाई-बहिन खुशी से, खुशहाली से, जिन्दगी गुजार सकें ।

[श्रीमती हामिदा हबीबुल्लाह]

उपसभापति महोदय, मैं आखीर में यह अर्ज करूंगी—

"मेरा रोना नहीं है यह, रोना है सारे गुलिस्तां का
वोह बुलबुल हूं फुगां हर गुल की है गोया फुगां मेरी ।"

श्री उपसभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned at one minute past six of the clock till eleven of the clock on Friday, the 24th February, 19 *to.*

z. S. 1—1904 R. S.— 10-4-78—570.